राजकुमार भाटिया

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

जून, 1978 मूल्य : एक रुपया

आपातकाल के बाद बिहार में छात्र आन्दोलन!

- चेहरे नहीं, सत्ता का चरित्र बदलो!
- दिल्ली विश्व विद्यालय कांड ....
- आरक्षण की राजनीति!
- सत्ता राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य नहीं कर सकती

—नानाजी देशमुख

मेरे साहसी युवको !

यह विश्वास रखो कि तुम्हीं सब कुछ हो—महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आये हो, मौदड़-घुड़कियों से भयभीत न हो जाना—नहीं, चाहे वज्र भी गिरे, तो भी निडर खड़े हो जाना और कार्य में लग जाना ।

—स्वामी विवेकानंद

जबतक मनुष्य के जीवन में राष्ट्रहित का भाव नहीं आयगा, तब तक राष्ट्र की समृद्धि सम्भव नहीं । संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र और इसका कण-कण मेरा, इसका दुःख मेरे लिए लज्जा की बात है, ऐसी भावना से ओतप्रोत वैचारिक और मानसिक क्रान्ति की आज आवश्यकता है । ऐसा वैचारिक परिवर्तन लाने के लिए समाज के प्रत्येक घटक में अपने समाज, अपनी परम्परा और अपने राष्ट्र के प्रति उत्कट प्रेम जागृत करना पड़ेगा ।"

—श्री गुरुजी

स्वार्थ अपने-अपने कुटुम्ब के दायरे में तो उदार रहता है—लेकिन मानव—कुटुम्ब की विशालता के आगे संकीर्ण हो जाता है ।

—डॉ० राममनोहर लोहिया

दूसरे की बात सुनना या उसके मत की आदर करना एक बात है और दूसरे के सामने झुकना बिल्कुल भिन्न बात । दूसरे की इच्छा के सामने झुकने की तैयारी में एक खतरा सदैव बना रहता है । जो सज्जन एवं धर्म भीरु होते हैं वे तो सदैव अपनी बात का आग्रह छोड़कर दूसरों की बात मान लेते हैं, किन्तु जो दुर्जन एवं दुराग्रही हैं वे अपनी बात मनवाकर समाज के अगुआ बन जाते हैं और धीरे-धीरे सामन्त एक विकृत रूप में उपस्थित होकर समाज के लिए कष्टदायक हो जाता है ।

—दीन दयाल उपाध्याय

इस अंक में

शिक्षा प्रणाली को एक नयी दिशा	—जयप्रकाश नारायण	6
हमारे विश्वविद्यालयों में असन्तोष	—आचार्य कृपलानी	8
प्रौढ़ शिक्षा : एक जनान्दोलन	—ओमप्रकाश कोहली	28
शिक्षानीति : यथास्थितिवाद का दुष्चक्र तोड़ो	—बाल आप्टे	9
पंत नगर : छात्रों की विवेकपूर्ण भूमिका	—कस्तूरीलाल तागरा	18
विज्ञापन और सिनेमा में नारी का इस्तेमाल	—स्नेहलता रेड्डी	38
रचनात्मकता की बजाय विध्वंस को प्राथमिकता क्यों ?	—राष्ट्र प्रकाश	46
मत	आरक्षण की राजनीति —गोविंदाचार्य	4
विशेष रिपोर्ट	आपातकाल के बाद बिहार में छात्र आन्दोलन सरयू राय	10
दिशा	सुधार चाहने वाले लोग हैं कहां ? —स्वामी विवेकानन्द	19
जिसकी चर्चा है	• जयप्रकाश नारायण • नानाजी देशमुख • जार्ज फर्नांडीज • प्रबाल मैत्र	21
भेंट वार्ता	नानाजी देशमुख से महावीर दत्त गिरि की बातचीत	26
रपट	दिल्ली विश्वविद्यालय में दोषी कौन ? —अरुण जेटली	34
छात्र संसद :	छात्र संघ आवश्यक है ?	30
खेल संसार :	खेल अधिकारियों की राजनीति	33
परिचय :	बृजभूषण	12
कविता :	रामजी गिरि	40
हलचल :		41
मुख पृष्ठ :	जे० मार्टिन	

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधि मासिक

○ वर्ष 1 ○ अंक 1 ○ जून, 1978

अपनी बात

प्रिय पाठक बन्धुओं,

सप्रेम नमस्कार !

'राष्ट्रीय छात्र-शक्ति' का प्रथम अंक आपके हाथ में है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में शिक्षा क्षेत्र के सार्थक योगदान की चिंता और सामाजिक-राजनैतिक परिस्थितियों के प्रति इस वर्ग की पकड़ की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति का उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं। राष्ट्रीयता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय व परिवर्तन से प्रेरित विद्यार्थी व शिक्षक समाज का स्वर प्रतिबिम्बित करने के ध्येय में लेखन की प्रखर शक्ति का उपयोग करने की भावना से 'राष्ट्रीय छात्र-शक्ति' का प्रकाशन करने का हमने निश्चय किया है।

'राष्ट्रीय छात्र-शक्ति' हर माह शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि मासिक के रूप में देश के हर कोने में पहुंचेगी। आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के प्रांगण से सीधे समाचार और महत्वपूर्ण विचार आप तक पहुंचेंगे।

'राष्ट्रीय छात्र-शक्ति' देश भर के विद्यार्थी व शिक्षक समाज को एक मंच पर लाकर विवेक सम्मत दिशा देने में सहयोगी होगी।

पत्रिका में अधिकाधिक निखार आए, और यह उत्तरोत्तर ज्ञानवर्धक एवं रोचक बनती जाए तथा यह पत्रिका देश एवं विशेषकर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रश्नों पर सार्थक एवं प्रभावी बहस का मंच बन सके, इस दृष्टि से आपके सुझावों का सहर्ष स्वागत है। अपने सुझाव से हमें बराबर अवगत कराते रहें। विश्वास है आप सबका सहयोग निरन्तर मिलता रहेगा।

सधन्यवाद !

आप सबका
सम्पादक

संपादक
अरुण जेटली

प्रबन्ध संपादक
महावीर दत्त गिरि

संपर्क हेतु
'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' हिन्दी मासिक
36, बंगलो मार्ग, कमलानगर, दिल्ली-110007

शुल्क की दर

वार्षिक	... ...	10 रुपये
छमाही	... ...	5 रुपये
आजीवन	... ...	100 रुपये
एक प्रति	... ...	1 रुपये

आरक्षण की राजनीति

□ गोविन्दाचार्य

सारा बिहार आरक्षण सम्बन्धी विवाद की आग में सुलग रहा है। हालांकि जनता पार्टी से सम्बन्धित कई मन्त्री और विधायक इस सम्बन्ध में केन्द्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर हल निकालने के लिए इस महीने के पहले सप्ताह में दिल्ली गए थे, जहां अप्रैल के तीसरे सप्ताह में फिर से विचार-विमर्श का फैसला कर वे लौट आये हैं, तो भी 31 मार्च में पटना के प्रदर्शन को अगर संकेत माना जाय तो कोई साधारण बुद्धि वाला आदमी भी आगे के घटना-चक्र का अनुमान लगा सकता है। मजे की बात यह है कि इस विवाद में जनता पार्टी दो खेमों में बट गयी है और कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टियां इसका फायदा उठा रही है।

आरक्षण के सम्बन्ध में विवाद महीनों से चल रहा है। प्रांतीय मंत्रिमण्डल में भी इसे लेकर मतभेद था। लेकिन मुख्यमन्त्री श्री कर्पूरी ठाकुर की आतुरता ने संकट उत्पन्न किया। लोगों का कहना है कि उनके फुलपरास विजय के बाद (या कारण) उत्पन्न अहंकार ने उन्हें निरंकुशता और मनमानी की ओर प्रवृत किया। बिहार के बारे में, जो जातिवाद का गढ़ रहा है, उन्हें समझ नहीं थी ऐसा कतई नहीं माना जा सकता। कुछ लोगों की मान्यता है कि इस विवाद से वे पिछड़ा वर्ग के, जो वोट की दृष्टि से बहुसंख्यक है, मसीहा बन सकेंगे यह दुराभिलाषा काम कर रही थी।

मंत्रिमण्डल में मतभेद

कहा जाता है कि उन्होंने मन्त्रिमण्डल के कुछ सदस्यों के द्वारा इस विषय को आगे बढ़ाया, पिछड़े वर्ग के कुछ नेताओं को यह कह कर उकसाया कि, "तुम नहीं चिल्लाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा ?" वित्तमन्त्री श्री कैलाश-पति मिश्र ने बिहार में इसके गम्भीर परिणाम होने की चेतावनी भी दी। सामान्यतः आरक्षण के बारे में किसी के दो मत नहीं थे। पर सभी इसे व्यापक सहमति और वातुमण्डल बनाकर स्वीकृत कराने के पक्ष में थे।

प्रदर्शनों का दौर

मुख्यमन्त्री श्री कपूरी ठाकुर के इशारे पर 9 मार्च को पिछड़ा वर्ग संघ के तत्त्वाधान में श्री राम अवधेश सिंह सांसद के नेतृत्व में पटना में प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इसी समय प्रदर्शनों की मानों होड़ लगी थी। बिहार इतनी गतिविधियों का केन्द्र कभी नहीं देखा गया था। 9 मार्च पिछड़ा वर्ग संघ प्रदर्शन, 12 मार्च जे०पी० अमृत महोत्सव के कार्यक्रम, 14 मार्च विद्यार्थी परिषद, जनता युवा मोर्चा, छात्रसंघ समन्वय समिति की विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन, 18 मार्च युवा जनता का प्रदर्शन, छात्र युवा संघर्षवाहिनी द्वारा स्थान-स्थान पर अनशन के कार्यक्रम आदि आयोजित थे, जिनकी विभिन्न स्तरों पर तैयारियां चल रही थीं।

9 मार्च के प्रदर्शन में कुर्मी जाति के लोगों ने साथ नहीं दिया। उन्होंने यादवों के हावी होने का आरोप लगाकर अपना अलग प्रदर्शन 14 मार्च को श्री श्रीचंदापुरी के नेतृत्व में करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि 9 मार्च के प्रदर्शन के लिए आर्थिक सहायता का भार बिहार मंत्रिमंडल के 2 सदस्यों ने अपने ऊपर लिया।

इसी बीच आरक्षण विरोधियों का खेमा भी जाति के आधार पर नेतागिरी चलाने के उद्देश्य से कुछ तैयार हो चुका था। आरक्षण के समर्थन और विरोध में नारे, वक्तव्य, भाषण आदि हवा में तैरने लगे। 11 मार्च को आरक्षण सम्बन्धी घोषणा मुख्यमन्त्री महोदय ने की। केन्द्रीय पार्लियामेंटरी बोर्ड की सहमति की घोषणा अखबारों में आ गई। जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व के लोगों ने जिस हलकेपन से इस विवाद को उस समय लिया था उसके कारण भी तनाव बढ़ा। सुना जाता है कि इस सवाल पर जनता पार्टी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर और बिहार के वित्तमन्त्री श्री कैलाश पति मिश्र के बीच टेलीफोन पर झड़प भी हो गई।

वातावरण विशेषकर कालेजों में विषाक्त हुआ। 10 मार्च से कालेज छिटपुट वारदातों का केन्द्र बनने लगे। कालेजों के बन्द करने की घोषणा हो गयी।

अमृतमहोत्सव का हाल

12 को जे०पी० अमृत महोसव के अवसर पर दादा कृपलानी और जे० पी० पर पत्थर बाजी हुई। आरक्षण समर्थकों और विरोधियों ने एक-दूसरे पर और दोनों ने मिलकर कांग्रेस, सी० पी० आई० पर इसके लिए इलजाम लगाया। जगजीवनराम को सभा में मंच पर जाने नहीं दिया। उधर मुजफ्फरपुर में जार्ज फर्नांण्डिस की दुर्गति हुई। कालेजों में छात्र दो गुटों में बंट गए। कांग्रेस और सी०पी० आई० ने अराजकता में घी डालकर अपनी रोटी सेंकने की कोशिश की।

पार्टियां बंट गई

इस अवसर पर एक दुखद तथ्य सामने आया। बिहार के सारे राजनीतिक दल (जनता पार्टी समेत) एवं छात्र युवा संगठन आरक्षण समर्थक और विरोधी खेमों में बंट गया। आरा जिले के सी०पी०आई० के कार्यकर्ता आरक्षण समर्थक थे तो दरभंगा और मधुबनी के कार्यकर्ता आरक्षण विरोधी गुट में सक्रिय थे। जनता

पार्टी सांसद और विधायकों ने अपने-अपने जातिगत खेमों में जगह ली। इसमें अपवाद स्वरूप सामान्यतः तीन ही संगठन उल्लेखनीय है जो इस विवाद से अलग रह सके और तीसरी शक्ति की भूमिका निभाने की सोच सके। वे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सर्वोदय बिहार में जातिवाद खुलकर खेलने लगा। युवा जनता के लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। प्रांतीय अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और राष्ट्रीय सदस्यों श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, विधिलेश कुमार सिंह के वक्तव्य आरक्षण समर्थक और विरोधी निकले। युवा जनता के लोग प्रान्तीय बैठक कर अपना रुख तय करने में घबड़ा रहे थे। जनता मोर्चा के अध्यक्ष विक्रम कुंवर जहां आरक्षण विरोधी मोर्चा, फारवर्ड लीग और मानवाधिकार रक्षा समिति में अगुवाई कर रहे थे, वहीं प्रान्तीय संगठन मन्त्री श्री सरयू राय पूरे संगठन को इस विवाद से निकाल कर एकत्रित भूमिका की तैयारी में जुटे थे।

14 मार्च का प्रदर्शन स्थगित

इसी बीच 14 मार्च को विद्यार्थी परिषद और जनता युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले जुलूस का समय आ गया। 12 मार्च की घटना के कारण उत्पन्न बिहार में तनाव की स्थिति, आम छात्र का इस विवाद में उलझाव की मनःस्थिति सभी दलों की अपनी राजनैतिक गुटबन्दियों और गोटी बैठाने की कोशिश आदि को देखते हुए परिषद के कार्यकर्त्ताओं ने एक आपत्कालीन बैठक 13 मार्च को प्रातः बुलाकर 14 मार्च को प्रदर्शन से अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं होगा बल्कि अनेक अराजक तत्वों के कारण उस दिन अनपेक्षित घटनाओं की सम्भावनाओं को समझकर प्रदर्शन को स्थगित करने का निर्णय किया। प्रान्त भर से 21,500 प्रकदंनकारियों के भाग लेने की सूचना कार्यालय को प्राप्त हो गयी थी। बिजली की गति से कुशलता-पूर्वक प्रदर्शन के स्थगन की सूचना को अमल में लाया गया। परिणामस्वरूप 14 मार्च को 3000 के लगभग प्रदर्शनकारी सूचना के अभाव में आ पहुंचे और उन्हें समझा-बुझाकर लौटाया गया। उस दिन अलग से सूचना देकर बिहार प्रदेश जनता युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं की बैठक हुई जिसमें परिषद के उपस्थित 100 कार्यकर्त्ताओं ने अपने को इस विवाद से अलग रखकर तीसरी शक्ति की भूमिका निभाने का फैसला किया। इस जातिवादी तूफान में अपने को संजोकर एकत्र रखकर आगे के लिए तैयारी करना वस्तुतः ही भागीरथ कार्य था। उस दिन का प्रदर्शन स्थगन को सभी विज्ञ लोगों ने सराहा। बताया जाता है कांग्रेस, सी०पी०आई० और जनता पार्टी से सम्बन्धित कई नेताओं का मुह स्थगन का समाचार सुनकर लटक गया।

युवा जनता—अनेकता की एकता

तभी 18 मार्च आ धमका। केन्द्रीय जनता पार्टी के नेतृत्व से सम्पर्क साधा गया कि वह बिहार की अराजकता की स्थिति में हस्तक्षेप करें, जनता पार्टी में मेल स्थापित करें। उस दिन अजीब समा था। एक ओर शहीद स्मारक पर विद्यार्थी परिषद और जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्त्ता शहीदों की स्मृति में उपवास कर बैठे थे। स्टेशन के पास चौराहे पर छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्त्ता अनशन कर रहे थे। युवा जनता की ओर से एक जुलूस निकला। युवा जनता समर्थित एक धड़े और एस०एफ०आई० और नक्सलवादियों के छात्र गुट बी०एस०ए० के संयुक्त तत्वावधान में दूसरा जुलूस निकला। पांच छः जिलों के प्रतिनिधियों के द्वारा बाद में प्रकाशित समाचारों के विपरीत "बिछड़ा पावे सौ में साठ" और "छत्तीस का जब वादा था, तो 26 में क्या बाधा है" युवा जनता की एकता (या अनेकता ?) का पर्दाफाश कर रहे थे। आरक्षण विरोधी धड़े ने प्रदर्शन में सहयोग किया ही नहीं। हां, प्रदर्शन और उपवासों का दिन शांति से बीत गया।

वातावरण विषाक्त था ही। गाड़ियों के रोकने, प्रदर्शनों के समाचार में बढ़ोतरी, इक्के-दुक्के विधायकों और सांसदों को घेरने की घटनाएं आम समाचार बन गई। इस बीच 31 मार्च को फारवर्ड लीग द्वारा आरक्षण की खिलाफत में विधान सभा पर प्रदर्शन करने का निश्चय हुआ। बिहार में कुछ अनिष्टकारी घटनाएं होकर ही रहेंगी, यह लगने लगा। 18 मार्च को विदेशमंत्री श्री वाजपेयी के पटना आकर वक्तव्य दिये जाने और दिल्ली आकर केन्द्रीय नेतृत्व को बिहार की स्थितियों से अवगत कराने के आश्वासन से कुछ आशा बंधी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र एम०पी० और श्री दिनेश सिंह राज्य सभा के चुनावों के निमित्त पटना आए और उन्होंने भी बिहार की विकट स्थिति को समझ कर बीच-बचाव की कोशिश शुरू की। प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री के पास सैकड़ों बार हस्तक्षेप के निवेदन भेजे गए। 31 मार्च के प्रदर्शन होने और न होने पर आगे के राजनीतिक संकट की भीषणता निर्भर थी। ज्यों-ज्यों समय बीतता था, संकट गहराता जा रहा था। 31 मार्च की फारवर्ड लीग की तैयारी, सरकार द्वारा कड़ाई की जाने की बयानबाजी 18 मार्च, सन 74 की याद दिला रही थी।

30 मार्च का दिन उत्सुकता की चरम सीमा का दिन था। सभी की आंखें इस ओर लगी थीं। लगभग 32 विधायकों की बैठक जिसमें ठाकुर नगेन्द्र सिंह, बृजकिशोर सिंह, श्री रमाकान्त पाण्डेय, रामजतन सिन्हा, विक्रम कुंअर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं; जे०पी०, श्यामानन्दन मिश्र, और परिषद के कार्यकर्त्ताओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्त्ता श्री गोविन्दाचार्य ने उस बैठक में जनता युवा मोर्चा के श्री सरयू द्वारा एक कागज पर एक संयुक्त समिति बनाकर 31 मार्च के प्रदर्शन को टालते हुए 2 अप्रैल को जनता पार्टी के अध्यक्ष चन्द्र शेखर की उपस्थिति में वार्ता द्वारा हल निकालने का सुझाव लिखित रूप से दिया, जिसे श्यामनन्द मिश्र ने तुरन्त मान्य करते हुए उपस्थित विधायकों से अपील की। परन्तु फारवर्ड लीग के नेताओं का कहना था कि हम तो जे०पी० की मध्यस्थता मानने को तैयार हैं पर श्री कर्पूरी ठाकुर इसे स्वीकार करेंगे इसमें हमें सन्देह है। इसलिए यह तय हुआ कि दिल्ली जहाज से प्रस्थान के पूर्व श्री श्यामनन्दन मिश्र मुख्यमन्त्री से जे०पी० की मध्यस्थता स्वीकार करावें और जब श्री कर्पूरी ठाकुर राज्यपाल अभिभाषण पर हुए बहस के उत्तर में भाषण करें तो इसका उल्लेख करेंगे। तब फारवर्ड लीग के नेता 31 मार्च के प्रदर्शन को स्थगित कर उसे जनसभा का रूप देंगे। और अन्ततः

[शेष पृष्ठ 33 पर]

शिक्षा प्रणाली को एक नयी दिशा

जयप्रकाश नारायण

दीर्घकालिक दृष्टि से शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देना उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना की व्यवसाय को, तभी संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भारत के साधारण नागरिक के लिए सार्थक हो सकते है। संघर्ष की भांति उन्नति की जड़ें भी मानव मस्तिष्क में होती है। इस कारण चिर स्थायी शान्ति की भांति स्वतन्त्रता तथा समानता की नींव डालने के लिए शिक्षा जितनी आवश्यक है उतना ही आवश्यक है राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्थानों का पुनर्निर्माण। जनता पार्टी अगर पिछले दो चुनावों में जनता द्वारा उसमें व्यक्त किये गये विश्वास की रक्षा करना चाहती है तो उसे शिक्षा प्रणाली में बदलाव को प्रधानता देनी होगी। मैं शिक्षा शास्त्री नहीं, पर एक ऐसे व्यक्ति की भांति जो कि वर्तमान शिक्षा पद्धति की असंगतता तथा लक्ष्यहीनता से चिन्तित है, यहां कुछ विचार सुझा रहा हूं जिन पर जनता सरकार से गम्भीर विचार तथा दृढ़ कार्य करने की अपेक्षा है। कुछ सुझाव दीर्घकालिक तथा कुछ अल्पकालिक है जिन पर शिक्षा क्षेत्र में कार्य किया जाना चाहिए।

"मैं आशा करता हूं कि सरकार, विशेष रूप से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय उन पर शीघ्रता से विचार करेगा।

अल्पकालिक कार्य

(1) यह निश्चित है कि सरकारी नीति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यदि मुख्य शिक्षा संस्थाओं के प्रमुख योग्य नहीं है और उन्हें समान विचारों वाले सहयोगियों का स्वतन्त्र सहयोग नहीं मिलता तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। मैं यह निष्कर्ष निकालने में सफल हुआ क्योंकि यह प्रकट है कि विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नेशनल बुक ट्रस्ट तथा दिल्ली व अन्य स्थानों में स्थित अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की स्थिति प्रतीत नहीं होती। यह सच है कि इनमें से कुछ संस्थान जैसे "भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद" समाज के पिछड़े वर्गों के अधिकारों के प्रति वचनबद्ध है पर वह भूतपूर्व शासन द्वारा नियुक्त लोगों के साथ कार्य करने को बाध्य रहे हैं जो कि शिक्षा को भी शक्ति की राजनीति, जिसमें वह तथा उनके संरक्षक व्यस्त हैं, का एक हिस्सा मानते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय इन संस्थानों के अधिकारियों का पुनर्स्थापन करे तथा उन संस्थाओं के प्रमुख के रूप में इन व्यक्तियों को नियुक्त करे जिनकी योग्यता, निपुणता तथा कर्तव्यपरायणता सन्देह की सीमा से परे हो। मैं कुछ विशेष नाम सुझाना नहीं चाह रहा हूं पर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इस देश की शिक्षा सम्बन्धी प्रतिमाएं जानते हुए मंत्री महोदय को उपयुक्त नाम ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। पर यदि वह आवश्यक समझते है तो ऐसे व्यक्तियों का नाम बताने में मैं प्रसन्नता अनुभव करूंगा सलाह मंत्री महोदय को लाभान्वित करेगी। परन्तु अंतिम निर्णय मंत्री जी का ही होगा।

(2) हमारे विश्वविद्यालयों के शिक्षा कार्यक्रमों में जो कि जन समुदाय की विभिन्न समस्याओं से विमुख हैं, में दुर्भाग्यपूर्ण साम्यता तथा निर्जीव सारूप्य है।

उदाहरण के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में, कुछ विषयों में छोटे तथा कम कर्मचारियों वाले विभाग जो कि केवल कुछ ही छात्रों को आकर्षित कर पाते हैं, चलाने में बहुमूल्य साधनों को व्यर्थ करने का कोई कारण नहीं है। यह अधिक उचित होगा कि एक समन्वित कार्यक्रम द्वारा इस प्रकार के विषयों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस प्रकार बांट दिया जाय ताकि समुचित कर्मचारियों, पुस्तकालयों द्वारा निर्देश दिये जायें तथा उच्च-स्तरीय शोध सुविधाएं दी जा सकें तथा साम्यता से बचा जा सके। एक ओर कलकत्ता, बम्बई आदि विश्वविद्यालयों तथा दूसरी ओर पिछड़े क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रम एक जैसे होने का कोई औचित्य नहीं है। यह अधिक सटीक होगा यदि बड़े शहरों के विश्व विद्यालय, बैंक व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तथा व्यापारिक संबंधों आदि विषयों में विशेष शिक्षा दें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय आदि की शिक्षा दी जाये। अर्थात विभिन्न विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम, इन क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित हो जिनमें वह कार्य करते हैं। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का क्षेत्रीय निर्दिष्ट पुनर्कन उन्हें केवल विकास की समस्याओं के संगत ही नहीं बनाएगा वरन जन समुदाय को भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अधिक बल प्रदान कर सकेगा।

औपचारिक शिक्षा

(3) मौजूदा शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देने के लिए एक लम्बा समय चाहिये, परन्तु पिछड़े वर्गों की कुछ ऐसी समस्याएं है जो कि इस लम्बे समय तक इन्तजार नहीं कर सकती है। मैं इस प्रकार के दो उदाहरण दूंगा जिन युवक-युवतियों ने बिहार आन्दोलन के समय कालेजों का बहिष्कार किया था वह भिन्न प्रकार की, अधिक अभिप्राय पूर्ण उच्च शिक्षा के पात्र थे। दूसरा 50 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक आयु वर्ग के तथा 90 प्रतिशत उच्च शिक्षा आयु वर्ग विभिन्न कारण विशेष द्वारा आज उचित शिक्षा से दूर है। यह शंका का प्रश्न है कि क्या राष्ट्र कभी भी मौजूदा प्रणाली को विभिन्न आयु वर्गों की क्षुधा पूर्ति के योग्य बना सकेगा अथवा नहीं? इसलिए यह आवश्यक है कि विभिन्न वर्गों जैसे स्कूली छात्र किशोर, युवक गृहणियां तथा कामकाजी पुरुषों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के ठोस कार्यक्रम बनाये जाएं ताकि आधुनिक जानकारी तथा कौशल को उनके लिए सुगम बनाया जा सके। इस प्रकार के कार्यक्रम उत्तरदायित्व तथा विकास की समस्याओं का पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ सामना करने की क्षमता बढ़ायेंगे। मैं जानता हूं कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ कदम उठाए गए है पर मैं

इतना और कहना चाहूंगा कि अभी तक इस जानकारी को व्यवहार में बदलने के लिए उठाये गये कदम महज सांकेतिक ही है।

एक रास्ता

(4) आगामी पांच वर्षों में अध्यापकों तथा छात्रों को एक असरदार कार्यक्रम के लिए तैयार करना ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा अनौपचारिक शिक्षा को औसत खर्च द्वारा जनसमुदाय तक पहुंचाया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी संरक्षण के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रयोग सीमित रूप में भी सफल नहीं हुए। असफलता उन विचारों की नहीं थी बल्कि योजना बनाने तथा कार्यान्वयन के दफ्तरशाही तरीकों की थी। यदि पहुंच का मार्ग बदल दिया जाये तथा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले लोगों का सही प्रकार के नेताओं द्वारा प्रेरित किया जाये तो कोई कारण नहीं है कि यह कार्यक्रम सफल न हों। जैसा कि हाल ही की घटनाओं द्वारा स्पष्ट है, इस देश के नवयुवकों में इस प्रकार की आशाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आदर्शवादिता है।

दीर्घकालीन कार्य

(5) मुझे बताया गया है कि भारत में कुल शिक्षा व्यय का एक तिहाई उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाता है जो कि इस आयु वर्ग के 10% को पहुंचता है। इसका अर्थ यह है कि अधिकांशतः मध्यम व उच्च वर्गों के बच्चे ही शेष 90% लोगों के मूल्य पर लाभान्वित होते हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सारी उच्च शिक्षा की शुल्क तथा निजी अनुदानों द्वारा स्वयं आर्थिक व्यवस्था की जाये तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों के छात्रों, जो कि उच्च शिक्षा की योग्यता रखते हैं, को समुचित छात्रवृत्तियां दी जाएं जो कि आसान किस्तों में वापस लौटाई जा सकें। इस प्रकार की व्यवस्था कई देशों में है। यह सच है कि इस व्यवस्था को संतोषजनक बनाने के लिए सरकार, स्थानीय अधिकारियों तथा शिक्षा संस्थानों द्वारा विशेष संगठित प्रयासों की आवश्यकता है। फिर भी मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसे प्रयास सामने नहीं आ रहे हैं जबकि शिक्षा व्यय को लाभान्वित लोगों में वितरित करना उच्च-शिक्षा को सुगम बनाने का एकमात्र साधन है।

(6) व्यावसायिक शिक्षा को आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाना भी आवश्यक है। इस शिक्षा द्वारा तैयार डाक्टर, इंजीनीयर तथा व्यवसाय विशेषज्ञ आगे चलकर अच्छे प्रतिफल प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ अधिक आय की तलाश में विदेश भी चले जाते हैं। एक गरीब देश अपने व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए धन के रूप में सहायता दे, ऐसा कोई कारण मुझे नजर नहीं आता।

(7) व्यावसायिक संस्थानों में शुल्क बढ़ाने तथा विशेष योग्यता प्राप्त गरीब छात्रों के लिए ऋण छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि इस सम्दर्भ में बौद्धिक पलायन के प्रश्न पर भी विचार किया जाये। कोई भी जानता है कि डा० हरगोविन्द खुराना जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भी अपने देश में समुचित शोध सुविधाओं के अभाव में विदेश चले गये। इस प्रकार के व्यक्ति पूरे विश्व की निधि होते है न कि किसी एक देश की। पर ऐसा कोई कारण नहीं की भारत डाक्टरों तथा इंजीनियरों को प्रशिक्षित करे तथा बाद में बतौर उपहार दूसरे देशों को भेंट करे जबकि उनकी सेवाओं की हमारे गांवों में तथा शहर के पिछड़े इलाकों में आवश्यकता है। अगर उनका देश ही उन्हें संतोषजनक कार्य के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करे तो वह नैतिक रूप में बाहर बसने की नहीं सोच सकते।

मैं प्रशिक्षित व्यवसायियों द्वारा विदेश जाने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं सुझा रहा क्योंकि वह स्वतंत्र समाज की आत्मा होते हैं, परन्तु मेरी दृष्टि में पर्याप्त हरजाने की मांग उचित है ताकि न केवल उनके प्रशिक्षण में खर्च पैसा बरन उनके बाहर चले जाने से हुई हानि को पूरा किया जा सके।

(8) यह भी आवश्यक है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा के अवसरों को रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा सके। इस प्रकार के रोजगार में उच्च वेतन होना ही जरूरी नहीं जैसा कि इस समय व्यावसायिक लोगों में प्रचलित है, पर जरूरी है ऐसे वेतनमानों का विश्वास दिलाना जो कि भली-भांति सोची गयी आय नीति के अनुरूप हों। इस हालत में इस प्रकार की नीति बनाना एक मुश्किल काम है पर यदि हमारे विभाजक न्याय तथा समर्पण की बात महज एक व्याख्यान नहीं है तो भारतीय समाज के हर वर्ग को ऐसी उचित आयनीति को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार की नीति का निर्धारण हमारे अर्थशास्त्रियों तथा समाज वैज्ञानिकों के लिए एक स्वागत योग्य ललकार साबित होगी।

व्यावसायिक न्याय

(9) यह मान्यता सही है कि व्यावसायिक न्याय के लिए पहली शर्त है समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर। हमारी अद्भुत सांस्कृतिक तथा जैविक उपलब्धियों को जिनसे सामान्य वर्ग अभी दूर है, ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसरों के वायदे का अर्थ है उन्हें विशेष सुविधाएं देना, न केवल प्रवेश के अवसर पर बरन पूरे शिक्षा काल में ताकि वह समान उपलब्धियां प्राप्त कर सकें तथा भविष्य में भी रोजगार के समान अवसर प्राप्त कर सकें। जो सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं वे पूर्णरूप से अपर्याप्त है तथा गलत ढंग से सोची तथा कार्यान्वित की जाती हैं। वह सामान्य वर्ग से प्रतिभाएं खोजने की कोशिश करते है साथ ही अपने पिछड़े वर्ग के साथियों की प्रगति के प्रति उदासीन रहते हैं। यह सच है कि इस क्षेत्र में किसी संतोषजनक नीति का निर्धारण सरकार तथा समाज वैज्ञानिकों की कल्पनाशक्ति तथा आन्तरिक बल को कष्ट देगा।

(10) ऊपर सुझाये गये सभी मध्यों के लिए न केवल शिक्षा अधिकारियों द्वारा उचित संकल्प तथा वास्तविक प्रयत्नों, बरन् राजनैतिक तत्वों, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों, प्रबन्धकों, छात्रों तथा अभिभावकों की स्वीकृति भी आवश्यक है। यह स्वीकृति वास्तविक रूप में तभी सम्भव होगी जब पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर, ऊपर सुझाये गये सभी वर्गों में वाद-विवाद आयोजित किये जाएं। केवल वादविवादों द्वारा ही एक राष्ट्रीय मत उभर सकता है तथा दृढ़ कदम उठाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय एकमत के अभाव में कोई भी क्रांतिकारी तथा स्थायी बदलाव संभव नहीं होगा तथा समग्र क्रांति की बात केवल एक राजनैतिक नारेबाजी बन कर रह जायेगी। ★

हमारे विश्वविद्यालयों में असंतोष

□ आचार्य कृपलानी

मुझे बताया गया है कि भारत के 105 में से 50 विश्वविद्यालय काम नहीं कर सके हैं। इनमें से कुछ में छात्र हड़ताल पर हैं। एक पूर्व अध्यापक के नाते मैं छात्र हड़तालों के विरुद्ध हूं जो इस शिक्षा में भी बाधा डालती है मैं तो कहता हूं कि इस दोषपूर्ण शिक्षा से अच्छा है कि कोई शिक्षा ही ही नहीं।

विगत में छात्र हड़तालें प्रायः राजनैतिक दल कराया करते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति उससे भिन्न है क्योंकि उनमें से अधिकांश स्वतः स्फूर्त प्रतीत होती हैं। छात्रों का विरोध यहां इस उचित शिकायत पर ही आधारित है कि आपातकाल में उनके विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का आचरण उचित नहीं रहा। कुछ उपकुलपतियों ने तानाशाही सत्ता के एजेन्टों के रूप में कार्य किया, अध्यापक व छात्रों को मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। उस मीसा के अन्तर्गत जो तस्करों व समाजविरोधी तत्वों से निपटने के लिए लागू किया गया बताया गया था। यदि संरक्षक अपने संरक्षितों के संरक्षक के दायित्व को तिलांजलि दे दें तो वे अपने प्राथमिक कर्तव्य से च्युत माने जाने चाहिए। 1907 के बाद से जब कि बंगभंग आन्दोलन जोरों पर था, छात्रों में जोश था और कुछ ने हिंसा का सहारा भी ले लिया था। अन्य सभी छात्र बंगभंग आन्दोलन के संरक्षक समझे जाते थे। स्वभावतः पुलिस से बचने के लिए वे छात्र होस्टलों में आश्रय ले लिया करते थे।

मैं उस समय फर्गुसन कालेज पूना का छात्र था। वहां दक्षिण कालेज नामक सरकारी कालेज भी था। उसके प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे। एक बार वहां पुलिस एक भगोड़े की तलाश में आई। उसने प्रिंसिपल से होस्टल कम्पाउन्ड में तलाशी के लिए अनुमति मांगी। प्रिंसिपल ने सीधे-सीधे पुलिस से बाहर निकल जाने को कह दिया और पुलिस बाहर चली गयी। इसके बाद प्रिंसिपल ने दो छात्र नेताओं को बुलाया और कहा कि यदि होस्टल में कोई भगोड़ा है तो उसे तत्काल वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जो भी वहां था वहां से चुपचाप चला गया।

चूंकि उस समय भारत में हर अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य का एजेन्ट समझा जाता था अतः उस दृष्टि से वह प्रिंसिपल भी साम्राज्यवादी था। पर वह एक भद्र पुरुष था। छात्र उसके संरक्षित थे वह उनका संरक्षक था। वह नहीं चाहता था कि उनमें से कोई भी कठिनाई में पड़े। उसका विचार था कि साम्राज्य को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिये। उसका प्रथम दायित्व तो यह देखना था कि छात्र किसी भी तरह परेशान न हों।

यदि आपातकाल के दिनों में कुछ उपकुलपतियों ने अपने विश्वविद्यालयों में छात्रों व अध्यापकों का संरक्षण नहीं किया और उनके बदले अधिकारियों को उनका शिकार अनुसरण करने दिया जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था और जो बिना किसी मुकदमे के जेलों में ठूंसे जा रहे थे तो उपकुलपतियों ने अपने पवित्र कर्तव्य से वंचना की। भारत देश में अध्यापकों व गुरुओं को देवतुल्य समझा जाता रहा है। मैं आज के अध्यापक से देवता बनने की आशा नहीं करता पर उसे अपने पेशे व पद सदाचरण तो दिखाना ही चाहिए।

अध्यापकों का कर्तव्य पालन होता है इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने प्रारम्भिक जीवन में इस पेशे को अपनाया था जबकि मेरे पिता जो एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे, इसके विरुद्ध थे और मुझे प्रशासनिक या वकालत पेशा अपनाने को कहते थे। उन दोनों पेशों से ही उस समय पर्याप्त धन प्राप्त होता था। यहां यह उल्लेखनीय है कि मैंने देश भक्त सार्वजनिक जनों द्वारा प्रारम्भ किये गये स्कूल में अध्यापकी की।

अध्यापक वहां अति कम वेतन लेते थे यद्यपि वे अन्यत्र बहुत अधिक कमा सकने की योग्यता रखते थे। शिक्षा और ज्ञानदान के लिए उनका त्याग स्मरणीय था। मैं स्वयं बुरा अध्यापक नहीं निकला। आज मेरे पुराने छात्र अपने सफेद बालों के साथ (मेरे खुद के तो नाममात्र को ही रहे हैं) मुझे बड़े आदर से मिलते हैं और पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। मैं उन्हें नहीं पहचान पाता पर वे अपने मास्टर साहब को जानते हैं। मेरा सदा विश्वास रहा है कि अधिकांशतः छात्र असन्तोष उचित अध्यापकों के अभाव के कारण है।

आज उपकुलपतियों की बात उठती है तो मुझे आश्चर्य होता है कि वे कैसे अध्यापक हैं जिन्होंने अपने छात्रों व साथियों के साथ विश्वासघात

[शेष पृष्ठ 17 पर]

शिक्षा नीति : 10+2+3 या 8+4+3 ?

यथास्थितिवाद का दुष्चक्र तोड़ो

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो० बाल आप्टे का केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री को पत्र

सेवा में,

श्री पी० सी० चुन्दर
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री
भारत सरकार
नई-दिल्ली

प्रिय श्री चुन्दर,

भारत सरकार 10+2+3 के स्थान पर नयी प्रणाली 8+4+3 को ला रही है—ऐसी विस्तृत रूप में चर्चा है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि निर्णय होने से पहले हम आपको अपने विचारों से अवगत करा दें क्योंकि हम इसके पक्ष में नहीं है।

कई वर्ष पहले 10+2+3 की प्रणाली को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था और इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए गये। कुछ राज्यों ने इस नयी प्रणाली को लागू करने की दिशा में काफी कुछ किया है। किसी भी प्रकार के बदल के कारण प्रशासनिक, आर्थिक समस्याएँ, नये विद्यार्थियों का पंजीकरण, अध्यापकों का रोजगार, शिक्षा संस्थानों की प्रशासनिक समस्याएं और भविष्य में इसके कारण आने वाली समस्याएं ऐसी कई प्रकार की बातें सामने आती हैं। यह प्रक्रिया पहले भी चल चुकी है और उसी की पीड़ा अभी तक पूरी नहीं हुयी है। अध्यापक और विद्यार्थी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है और करोड़ों रुपया खर्च होना है। इस कारण से शिक्षा क्षेत्र में अशान्ति अभी तक व्याप्त है।

इस स्थिति में एक नये प्रकार को लागू करना अपने आप में अशान्ति और अव्यवस्था को ही बढ़ावा देगा। और एक प्रणाली के प्रहार के विचार से ही मन कंपित हो जाता है।

घोड़े के आगे गाड़ी रखने का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। वैसे हम 10+2+3 की प्रणाली के बड़े पक्षधर है ऐसा नहीं। इस प्रणाली के कारण पर्याप्त रोष है क्योंकि इसके कारण 1 वर्ष अधिक लगता है—जबकि कई प्रान्तों में साधारणतया शैक्षणिक अवधि 14 वर्ष है। इस सारी स्थिति के बावजूद भी 10+2 प्रणाली के पक्ष में कई बातें कही जा सकती हैं। इस प्रणाली के अन्दर अपेक्षित है, गहरी उदार शिक्षा, जिसमें सामाजिक सेवा और हाथ के काम का अनुभव पहले दस वर्ष में होता है और कला दो के स्तर पर विविध रूप में व्यावसायिक शिक्षा की भी बात है। इस प्रणाली की असफलता भी इन्हीं बातों में है जैसे सामाजिक शिक्षा और काम के अनुभव की विफलता। व्यवसायिक शिक्षा का पूर्ण रूपेण अभाव ही सामने आया है। जब तक ये असफलताएं स्पष्ट रूप में सामने नहीं लायी जाएंगी और ठीक नहीं की जाएंगी, नयी प्रणाली का भाग्य भी वही होगा—जो पहली प्रणाली का हुआ है और यह शिक्षा व्यक्ति में यथास्थितिवाद को ही बनाये रखेगी। यह यथास्थितिवाद जो कि आज चल रहा है—केन्द्र और राज्यों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस समस्या का हल केवल गणित के हिसाब से न होकर इस दिशा में कुछ ठोस पग उठाकर होगा-जैसे पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाना, काम का अनुभव लेने वाले कार्यों में अधिक धन लगाना, व्यवसायिक शिक्षा में अधिक खर्च करना और इसके लिए लगातार चलने वाली अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

इस बात को जानते हुए कि पहले ही काफी राशि खर्च हो चुकी है और नया बदल मनोवैज्ञानिक रूप से भी सभी जनों को बुरी तरह प्रभावित करेगा—यह आवश्यक है कि पुरानी पद्धति से हटने के पहले चल रही प्रणाली का मूल्यांकन किया जाय।

अर्थ शास्त्रियों का यह तर्क कि माध्यमिक स्तर पर दो साल की कटौती का अर्थ यह होगा कि आठ साल की शिक्षा के बाद लाखों बाजार में काम के लिए दाखिल हो जायेंगे (काम मिलने की संख्या में वृद्धि हुए बिना) और जो रोजगार की समस्या पहले ही शुष्क बनी हुयी है अधिक शुष्क होगी इसको साधारण रूप में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह सनकी प्रतीत होती है। हम, इसलिए शिक्षा मंत्रालय से अपील करते हैं कि वह जल्दबाजी न करें और अपनी अपनी प्राथमिकता शिक्षा के संरचात्मक पहलू से विषयात्मक पहलू की ओर अधिक करें। जो कुछ भी बदल करके प्राप्त करना चाहते हैं—उसे वर्तमान प्रणाली में लागू करके प्राप्त किया जा सकता है और यदि फिर भी विषय सूची में परिवर्तन के बाद आवश्यकता महसूस हो तो प्रणाली में परिवर्तन किया जा सकता है। पहले ही हम अपने विचारहीन प्रयोगों के कारण दो पीढ़ियों को नष्ट कर चुके हैं इसलिए हमें तीसरी पीढ़ी को बचानेके लिए प्रयत्न करना चाहिए।

इसलिए हम ईमानदारी से यह कहना चाहते है कि प्रणाली परिवर्तन के स्थान पर शिक्षा के अंतरंग परिवर्तन को बढ़ावा देने का निर्णय किया जाय।

यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विचार हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर इन सब विषयों की चर्चा करना चाहूंगा। और भी दूसरे प्रश्न है जो शिक्षा की नीतियों से सम्बन्धित है।

आदर सहित,

भवदीय
ह० बाल-आप्टे

विशेष रिपोर्ट

आपातकाल के बाद बिहार में छात्र आंदोलन

आंदोलन की संभावनायें बरकरार

सरयू राय

मार्च के प्रथम सप्ताह में छात्र-युवा सहित आम जन बरबस एक प्रश्न कर बैठता था—क्या बिहार में पुनः आन्दोलन होगा ? मार्च में बिहार की राजधानी में प्रदर्शनों एवं उपवासों का ताता लगा रहा। ऐसा लग रहा था कि जनता सरकार के शासन के एक वर्ष के अन्दर बिहार आन्दोलन की चौथी वर्षगांठ पर छात्र-युवा एक बार पुनः अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हुए हैं। असंतोष की अभिव्यक्ति के लिये जनमानस पुनः उद्वेलित हो उठा है। मार्च महीने का प्रारम्भ बिहार आन्दोलन की कड़ी को आगे बढ़ाने—सत्ता परिवर्त्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन के लिए रचनात्मक संघर्ष में छात्र-युवा सहभाग के हिमायतियों के लिए प्रसन्नता, उत्साह तथा कुछ कर गुजरने की नवीन प्रेरणा लिये हुए था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनता युवा मोर्चा तथा छात्र-संघ समन्वय समिति के संयुक्त तत्वावधान में बजट सत्र के प्रारम्भ दिन 14 मार्च को विधान सभा के सामने प्रदर्शन, 18 मार्च को बिहार आन्दोलन के शहीदों की स्मृति में उपवास तथा 22 मार्च को मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा ने सम्पूर्ण छात्र-युवा जगत को रचनात्मक संघर्ष के द्वारा बिहार आन्दोलन के बलिदानों को सार्थक करने के लिए उठ खड़ा होने का साहस एवं शौर्य प्रदान किया। दूसरी ओर युवा जनता ने आल इण्डिया स्टूडेण्ट फेडरेशन सहित तथाकथित वामपंथी मोर्चे के एस० एफ० आई० तथा बी० एस० ए० के के साथ संयुक्त प्रदर्शन की घोषणा की। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी ने भी 18 मार्च को जिला केन्द्रों पर उपवास का कार्यक्रम घोषित किया।

अलग-अलग प्रदर्शनों की घोषणा से दो बातें प्रमाणित हुईं। 1- बिहार में आज भी छात्र-युवा आन्दोलन की सम्भावनाएं सम्पूर्ण रूप में विद्यमान हैं। 2- आपातकाल की घोषणा के बाद बिहार का युवा मानस बुरी तरह विभाजित है। ये दोनों बातें बिहार आन्दोलन के साथ जुड़ी हुई हैं। आज भी बिहार में छात्र-युवा आन्दोलन की वे अन्तर्धारायें मौजूद हैं जिनका सूत्रपात बिहार आन्दोलन के साथ-साथ हुआ तथा जिनकी नियति आन्दोलन से जुड़ गई थी। आज अन्तर है तो इतना ही कि बिहार आन्दोलन के दौरान ये धारायें समानान्तर और अविरोधी थी। परन्तु आज ये न समानान्तर हैं और न अविरोधी। बिहार प्रदेश छात्रसंघ संचालन समिति तथा स्थानीय स्वतः स्फूर्त संघर्ष समितियों के परम्परानुकूल एवं समानधर्मी तत्वों ने इन धाराओं के बीच सहयोग एवं समन्वय बनाये रखा। सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए संघर्ष के दौरान इनके स्वरूप, संरचना, कार्यपद्धति एवं व्यवहार शैली का अन्तर सहयोग एवं समन्वय में बाधक नहीं बना। अन्तर्विरोध का बीज संघर्ष समितियों के गठन में ही मौजूद होने के बावजूद जे० पी० के व्यक्तित्व की विराटता ने इन्हें आन्दोलन की मुख्य धारा से जोड़े रखा।

आज दीख रहा बिखराव आपातकाल की घोषणा के तुरन्त बाद स्पष्ट हो गया था। संघर्ष समितियों में शामिल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वाहिनी के युवकों ने आपातकाल के दौरान जनान्दोलन को सबल बनाने के लिए असह्य परेशानियों और कष्टों को झेलकर जेलयात्रा का तानाशाही आमन्त्रण स्वीकार किया। परन्तु वैसे फैशन परस्त युवकों ने, बिहार आन्दोलन में शामिल होना जिनकी बाध्यता थी तथा जो व्यक्तिगत, सामूहिक या गुटीय हितों तथा राजनैतिक स्वार्थों के दबाव में आन्दोलन के साथ चलने को मजबूर थे, अपनी रणनीति समयानुसार बदल दी। कुछ तो निष्क्रिय होकर आन्दोलन की निरूपयोगिता प्रतिपादित करने लगे तथा कुछ ने युवा कांग्रेस और मुखबिर तक की भूमिका अदा की।

आपातकाल समाप्ति के बाद जनता शासन के एक वर्ष में बिहार आन्दोलन की धाराओं को गति मिली। परन्तु परिवर्तित

आपातकाल समाप्ति के बाद जनता शासन के एक वर्ष में बिहार आन्दोलन की धाराओं को गति मिली परन्तु परिवर्तित परिवेश में इनकी भूमिका बदल गयी। संघर्ष समिति बिखर गयी। आपातकाल के संघर्ष में सुविधा की रणनीति अपनाने वाले सुविधानुसार सत्ता संघर्ष की होड़ में शामिल हो गये। विधान सभा चुनाव समाप्त होते ही सत्ता और संघर्ष के सिपाही अलग-अलग दिखाने लगे।

युवा मानस बुरी तरह विभाजित और दिग्भ्रमित

परिवेश में इनकी भूमिका बदल गई। संघर्ष समिति बिखर गयी। आपातकाल के संघर्ष में सुविधा की रणनीति अपनाने वाले सुविधानुसार सत्ता संघर्ष की होड़ में शामिल हो गये। विधान सभा चुनाव समाप्त होते ही सत्ता और संघर्ष के सिपाही अलग-अलग दिखने लगे।

बिहार आन्दोलन की परिस्थितियों ने जिन धाराओं को समानान्तर और अविरोधी बनाए रखा, आपातकाल के संघर्ष ने उन्हें आमने सामने खड़ाकर बेनकाब कर दिया था। जनता पार्टी के प्रारम्भ काल ने उन्हें सत्ता और संघर्ष के विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया पर अब ये न समानान्तर रही न अविरोधी। एक वर्ष के अन्दर ही उनकी खाई न पाटी जाने की हद तक चौड़ी हो गयी है।

मार्च 77 के प्रारम्भ में सत्ता से अलग रहकर परिवर्तन के लिए संघर्षरत छात्र-युवकों ने सत्ता की छाया में पल रहे पुनरावृत्ति के वाहकों के विरुद्ध मोर्चा बनाने की शुरुआत की। जनवरी के प्रारम्भ में पटना में आयोजित अखिल भारतीय छात्रसंघ प्रतिनिधि सम्मेलन ने प्रस्ताव पारित कर बिहार प्रदेश छात्रसंघ प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन करने तथा बिहार आन्दोलन की मांगों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने का निर्णय किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा जनता युवा मोर्चा ने छात्रसंघ प्रतिनिधियों के इस निर्णय का स्वागत करते हुए उन्हें पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। बाद में छात्रसंघ समन्वय समिति, अ० भा० विद्यार्थी परिषद तथा जनता युवा मोर्चा ने बिहार आन्दोलन के मांगों की पुष्टी तथा संघर्ष के बाद विरासत में प्राप्त जनता सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिए जनमानस तैयार करने हेतु 14 मार्च, 18 मार्च तथा 22 मार्च के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए बिहार आन्दोलन के समर्थक सभी छात्र-युवा संगठनों का सहयोग लेने का प्रयास किया। परन्तु दूसरी ओर, रचनात्मक संघर्ष के द्वारा सम्पूर्ण क्रान्ति के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए युवा शक्ति के साथ सहयोग करने के स्थान पर बिहार युवा जनता ने आपातकाल समर्थक ए० आई० एस० एफ० तथा श्री जयप्रकाश नारायण विरोधी फैशनपरस्त वामपंथी युवा संगठनों का अलग मोर्चा बनाकर सरकार विरोधी आन्दोलन चलाने का फैसला किया। सत्ता के गलियारे में ऐश फरमा रहे संघर्ष समिति के नेताओं ने भी युवा जनता को शह दी। बिहार आन्दोलन की दो प्रवृत्तियां एक वर्ष बाद पुनः आमने-सामने थीं। इस एक वर्ष में बिहार के छात्र-युवकों ने अनुकूल सत्ता शक्ति के प्रभाव को महसूस किया। आपातकाल के संघर्ष में प्रतिकूल सत्ता शक्ति के कारण ध्येयनिष्ठ तथा अवसरवादी रणनीतियां स्पष्ट हुई थीं तो एक वर्ष अवधि की भावुक शक्ति ने भी संघर्ष और भोग की रणनीति का विकल्प छात्रों-युवकों के समक्ष प्रस्तुत किया। विद्यार्थी परिषद और छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी ने सत्ता भोग से दूर रहकर सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन के लिए रचनात्मक संघर्ष का विकल्प स्वीकार किया तो युवा जनता ने विधान सभा की सदस्यता तथा विभिन्न समितियों और बोर्डों के माध्यम से सत्ताभोग के लिए आपसी संघर्ष का।

> **बिहार के शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद ही एक मात्र ऐसा संगठन है जो लोकनायक की सम्पूर्ण क्रांति में आस्था रखते हुए भारतीय आदर्शों के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र की रचना, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए रचनात्मक संघर्ष तथा सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन के लिए छात्रशक्ति का उपयोग अपने विविध कार्यक्रमों द्वारा कर रहा है।**

इस वर्ष के अन्दर छात्र-युवा गतिविधियों के राजनैतिक तथा गैरराजनैतिक खेमों में युवा शक्ति की भूमिका के विषय में विवाद छिड़ा है। गैर राजनीतिक छात्र-युवा संगठनों में विद्यार्थी परिषद और वाहिनी के बीच दलगत राजनीति से अलिप्त रहने तथा सम्पूर्ण क्रान्ति से प्रतिबद्ध होने की समानता के बावजूद संगठन, विचार पद्धति, कार्यक्षेत्र तथा कार्यक्रम की दृष्टि से अलगाव है। लोकनायक जयप्रकाश द्वारा सम्पूर्ण क्रान्ति का वाहक तथा जे० पी० के निजी विचारों को कार्यरूप देने के लिए गठित वाहिनी में बिहार आन्दोलन में सक्रिय छात्रों-युवकों का एक अच्छा खासा ईमानदार तथा कर्मठ समूह है जिसे सर्वोदय और जे० पी० के निर्देशन का लाभ मिलता है। परन्तु संगठन का अभाव तथा युवा मानस में सम्पूर्ण क्रान्ति की अस्पष्टता वाहिनी की कमजोरी है। जे० पी० और वाहिनी के युवकों के चिंतन में पीढ़ीगत अन्तर होने के कारण कभी-कभी युवकों के ठहराव का आभास मिलता है। मार्क्स और गांधी, जे० पी० और विनोबा, पुराने सर्वोदयी तथा नवोदित सम्पूर्ण क्रान्तिकारी की विभाजन रेखा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के कर्म और चिन्तन को गहराई तक प्रभावित करती है। वाहिनी के अन्दर कार्यरत दो गुट अपनी अलग-अलग पत्रिकायें ('समग्रता' और 'प्रक्रिया') प्रकाशित कर रहे हैं। इसके बावजूद वाहिनी ने एक वर्ष में अपनी कार्यशैली निरूपित की है। व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष में उसकी अपनी भूमिका है।

दूसरा गैर राजनीतिक संगठन विद्यार्थी परिषद अपने कार्यक्रमों के द्वारा छात्र-युवा समुदाय में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सुसंगठित संगठन के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। विधान सभा के चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को राजनैतिक प्रलोभनों से अलग रखकर छात्र-संघर्ष समितियों की समाप्ति के बाद पैदा हुए शून्य को भरने के प्रयास में विद्यार्थी परिषद ईमानदारी से जुटा एक मात्र संगठन है। बिहार के छात्रों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के छात्रसंघ चुनाव में परिषद के कार्यकर्ताओं को विजयी बनाकर परिषद की भूमिका को मान्यता दी है। "छात्र शक्ति—

राष्ट्र शक्ति" तथा "आज का छात्र आज का नागरिक" के उद्घोष के अनुसार परिषद ने अपनी संगठनात्मक सुदृढ़ता तथा परिपक्वता का भरोसा दिलाया है। बिहार के शिक्षा क्षेत्र में परिषद ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो लोकनायक की सम्पूर्ण क्रान्ति में आस्था रखते हुए भारतीय आदर्शों के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र की रचना, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए रचनात्मक संघर्ष तथा सत्ता परिवर्तन के लिए छात्र-शक्ति का उपयोग अपने विविध कार्यक्रमों द्वारा कर रहा है। बिहार में परिषद की शक्ति का एक मात्र आधार है महाविद्यालय स्तर तक कार्यकर्ताओं की सुदृढ़ तथा अनुशासित पंक्ति। **विद्यार्थी परिषद के ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान के उद्योजन शिविर तथा शिक्षा क्षेत्र में छात्रों की सुविधा के लिए व्यवस्था तथा सत्ता से संघर्ष के कार्यक्रम आज भी बराबर चल रहे हैं जबकि बिहार के अन्य सभी संगठन आरक्षण के विवाद पर बुरी तरह विभाजित हैं।**

राजनीति सापेक्ष संगठनों की भूमिका का अध्ययन करने पर साफ जाहिर है कि विभिन्न दलों से जुड़े युवा संगठन युवा आक्रोश की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने के प्रयास में हैं। ध्येय विहीन सत्ताभिमुख राजनीति का प्राबल्य इन युवा संगठनों की सबसे बड़ी कमजोरी है। उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाकर आन्दोलन के गर्भ से पैदा हुई बिहार की सरकार ने युवाशक्ति को छिन्न-भिन्न करने के लिए संघर्ष के मुद्दे ही बदल दिए। इस सरकारी चाल के शिकार युवा संगठन बुरी तरह विभाजित हो चुके है। जनता पार्टी के युवा संगठन होने का दावा करने वाले युवा जनता और जनता युवा मोर्चा दोनों ही संगठनों पर जनता सरकार का प्रभाव है। युवा मोर्चा की विशेषता है कि वह एकजुट, संगठित और अनुशासित है परन्तु युवा जनता में जनता पार्टी की भांति घटकवाद पूर्ण रूप से हावी है।

बिहार में वामपंथ के पक्षधर के रूप में ए० आई० एस० एफ०, एस० एफ० आई० तथा बी० एस० ए० कार्यशील हैं तथा अवसरवादियों के प्रतिनिधि स्वरूप युवा कांग्रेस तथा एन० एस० यू० आई० परन्तु वर्तमान समय में इनकी न तो कोई साख है न ही आन्दोलन के लिए आवश्यक संगठन। कुल मिलाकर अपने पितृ संगठनों के कारण इनका अस्तित्व बरकरार है। आज भी बिहार का युवा वर्ग नेतृत्व के लिए युवा जनता तथा जनता युवा मोर्चा, विद्यार्थी परिषद और वाहिनी पर आस लगाए बैठा है।

आपातकाल के एक वर्ष के दौरान उलझी हुई परिस्थितियों को सुलझाने तथा युवा शक्ति द्वारा सत्ता पर अंकुश रखने के लिए आगे बढ़े युवक आज आरक्षण विवाद में फंस कर रह गये है। उससे उबारकर छात्र-युवा को पुनः दिशा प्रदान करना आज सबसे बड़ी समस्या है। बिहार आन्दोलन के दौरान समाप्त हुए जाति-पाँति तथा ऊँच-नीच के भेदभाव आज घृणा तथा विद्वेष का वातावरण उत्पन्न कर सामाजिक संकट का रूप धारण कर चुके है। बिहार आन्दोलन की धाराएं इस परिस्थिति में अलग-अलग भूमिकाओं में बदस्तूर है। विद्यार्थी परिषद, जनता युवा मोर्चा तथा छात्र संघ समन्वय समिति समाज को इस संकट से उबारने के लिये प्रयत्नशील हैं तो अन्य युवा संगठन स्वयं विभाजित होकर उसे अधिकाधिक गहरा कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद और जनता युवा मोर्चा ने 14 मार्च का विशाल प्रदर्शन स्थगित कर अपनी शक्ति को सामाजिक एकात्मकता का वातावरण निर्माण करने में लगा दिया। लेकिन युवा जनता और वामपंथी संगठन आरक्षण विवाद को गहरा कर रहे है।

[शेष पृष्ठ 32 पर]

परिचय : बृजभूषण

12 दिसम्बर 1977 की एक शाम। आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोडूरू प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के एक गांव पालकाएटिप्पा में एक युवक तूफान के कारण दुर्दशा को प्राप्त ऐसे लोगों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था जो जीवन से निराश हो चुके थे। रोते-बिलखते लोगों को ढाढस बँधाते, उनकी चिकित्सा करते यह नाबालिग युवक अन्दर से एकदम टूट चुका था। चिकित्सा केन्द्र के अन्य सहयोगी हैरान थे उसके कार्य को देखकर। इस युवक ने तूफान पीड़ित क्षेत्रों में रात-दिन काम किया। वह बृजभूषण था।

नागपुर विश्वविद्यालय के श्री बृजभूषण एक ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने अपने अध्ययन काल में ही सेवा का जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वह देश के आम विद्यार्थियों के लिए कल्पना मात्र है। हमेशा से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले श्री बृज भूषण प्रदेश स्तर की कई वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत हो चुके है। वर्ष 1974 में उन्हें सराहनीय स्काउटिंग के लिए 'राष्ट्रपति स्काउट' पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक मध्यमवर्गीय परिवार में 17 जून 1957 को जन्मे श्री बृजभूषण सम्प्रति नागपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महात्मा गांधी इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल सांयसेस, सेवाग्राम (वर्धा) में एम०बी०बी०एस० अन्तिम वर्ष के छात्र हैं।

बृजभूषण

बृज भूषण का कहना है कि आन्ध्र में उसने मौत को बहुत करीब से देखा। वहां मौत 19 नवम्बर की रात बड़ी चुपके से आयी पर अपने पीछे दर्द का सैलाब छोड़ गई। मरे हुये लोगों के इर्द-गिर्द आन्ध्र में बीते मेरे दिनों ने मुझे इतना क्रूर बना दिया है कि मुझे मौत से कोई डर नहीं रह गया है। मैंने पहली बार गांव के लोगों की तकलीफों को इतने करीब से देखा। इससे मेरे अन्दर देश के गांवों के लिए प्यार पैदा हो गया है। अपनी बाकी जिन्दगी में भी मैं सक्रिय रूप से गांवों से जुड़ा रहूंगा।

श्री बृज भूषण के इन कार्यों से प्रभावित होकर पिछले वर्ष उन्हें महात्मा गांधी इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल सांयसेस का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी घोषित किया गया।

शिशिर गुप्त

★

हम अंकुश का काम करेंगे, हथौड़े का नहीं

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बिहार प्रदेश छात्र संघ समन्वय समिति एवं जनता युवा मोर्चा द्वारा मुख्य मंत्री को 14 मार्च 78 को दिया गया संयुक्त ज्ञापन

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री महोदय,
बिहार सरकार, पटना।

महोदय,

हम युवा-छात्र संक्रमण-काल में आपको संबोधित कर रहे हैं। विधान सभा जनाकांक्षा के प्रतिनिधियों की सभा है और आप उस सभा के सूत्र-धार अतः वर्तमान संक्रमण-काल की अन्तःक्रियाओं के संदर्भ में आपसे संवाद हो, यह हमें अत्यावश्यक लगा। ऐसा इसलिए भी जरूरी समझा गया कि विधान सभा के भीतर और विधान सभा के बाहर के वायु मंडल में अब भी भेद उत्पन्न हो जाता है तब वह घड़ी संकट की घड़ी होती है और उसके परिणाम भयंकर होते हैं, सन् 70 से 76 के हमारे अनुभव से भी इसकी पुष्टि होती है। हम यह नहीं कहते कि वह 'भेदक वायुमंडल' तैयार हो गया है, पर यह अवश्य महसूस करते हैं कि 'भेद की प्रक्रिया' शुरू हो गयी है। भेदक प्रक्रिया का यह अंकुर विषवृक्ष बन जाय इसके पूर्व ही इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

छात्र-युवावर्ग भी इस दिशा में कुछ सोचता रहा है क्योंकि श्रीमती इंदिरा गाँधी के विषवृक्ष का विषफल अधिकतर इसे ही भोगना पड़ा था। इसीलिए पुनः हमारे कान खड़े हुए हैं। यह ज्ञापन हमारे उसी चौकन्नेपन तथा दायित्व बोध का प्रदर्शन है।

1. हम छात्र-युवा वर्ग अपने चिन्तन, अपने दायित्व-संकल्प तथा अपनी मांगें लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी बातों को बड़बोलापन, हमारे दायित्व संकल्प को दुधमुंही कल्पना तथा मांगों के टकराव अथवा चुनौती नहीं समझा जाय।

हमारा चिन्तन एवं दायित्व संकल्प

हम छात्र युवाओं का वर्ग समाज का सर्वाधिक संवेदनशील वर्ग है, इसलिए समाज-जीवन में तनिक हलचल को भी हम महसूस कर लेते हैं। समाज तथा राष्ट्र जीवन में प्रत्येक संघर्ष में हमारी निर्णायक भूमिका रही है, जहां इस तथ्य से हम गौरवान्वित हैं, वहीं हर हलचल के प्रति हम सजग भी रहते हैं, क्योंकि समाज तथा राष्ट्र जीवन में उठे हर गलत कदम की पहली चोट हमें ही सहनी होती है। हम अपनी रचनात्मक भूमिका में लगे रहना चाहते हैं, परन्तु इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हमें अपनी रचनात्मक भूमिका के लिए सही वातावरण भी मिले। इस सही वातावरण की तलाश में ही हमने 18 मार्च, 74 को बिहार विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया था। प्रश्न हो सकता है कि आज की स्थिति भी क्या वही है, जो 18 मार्च, 74 के प्रदर्शन के समय थी? हम यह तो नहीं कहेंगे कि आज की स्थिति भी वही और वैसी ही है, लेकिन यह अवश्य कहना चाहेंगे कि जिन प्रश्नों को लेकर चार वर्ष पूर्व प्रदर्शन तथा आन्दोलन हुआ था, वे अभी तक अनुत्तरित हैं। जनता सरकार को गठित हुए लगभग एक वर्ष पूरा होने को आया लेकिन 18 मार्च, 74 को उठाये गये सवाल के समाधान अभी तक नहीं निकले, इससे चिन्ता अवश्य होती है। हमें आशंका होती है कि कहीं हमारे द्वारा उठाये गये प्रश्नों को आश्वासनों के माध्यम से लट-काये रखने का कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा?

2. आज से एक वर्ष पूर्व दूसरी आजादी देश को मिली। उस लड़ाई में छात्रों नौजवानों की नियामक भूमिका थी। भारत में सन् 42 में छात्रों नौजवानों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में अगुवाई की थी। फिर बिहार आन्दोलन में भी छात्रों ने ही पहल की।

फरवरी 17, 18' 74 को छात्र नेता सम्मेलन में कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका गया। उस छात्र नेता सम्मेलन में कम्यू-निष्ट और कांग्रेस समर्थक छात्र युवा संगठनों ने छात्र आन्दोलन के पीठ में छुरा घोपने की असफल कोशिश की थी। उनके चेहरे और नीयत बेनकाब हुए। गफूर सरकार में छात्र आन्दोलन की अहमियत को समझने की कूवत नहीं थी। वे सत्ता के नशे में डूबे थे, श्रीमती इन्दरा गांधी के इशारों पर प्रान्तों की हुकूमतें बेशर्मी से चारणभाट का कार्य कर रही थी। कम्यूनिस्टों ने हमेशा की भांति उस समय भी जनभावना की उपेक्षा की, छात्रान्दोलन के साथ गद्दारी की और सत्ता के दामन से लिपटे रहे।

विधानसभा के सामने सत्रारंभ के दिन प्रदर्शन करने का छात्रों ने तय किया। वह दिन उस साल 18 मार्च का था। प्रदर्शन में कांग्रेस, सी० पी० आई, के गुर्गों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की उनकी ओट में, उनके द्वारा फैलायी गयी अराजकता को दुरुस्त करने के नाम पर पुलिस ने छात्रों के आन्दोलन को लाठी गोली से दबाने की बेवकूफी की। सी० पी० आई० के विधायक श्री लाल बिहारीसिंह आगजनी काण्ड में पकड़े गये थे। पूरा शहर गुण्डागर्दी से आक्रान्त हुआ। दसियों छात्र उस दिन शहीद हुए। समाचार पत्रों के दफ्तर जलाये गये।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस का हमला, गफूर सरकार का अंधा-बहरापन आगे के संघर्ष के लिए जिम्मेदार बना। छात्रों ने विधानसभा भंग करने का नारा दिया। लोकनायक का नेतृत्व छात्रों को प्राप्त हुआ। उनके नेतृत्व से आन्दोलन को गहराई मिली। छात्रों के उत्साह से इसका विस्तार हुआ। लोकशक्ति और राजशक्ति के बीच संघर्ष छिड़ गया। भला 5 जून का विशाल जनप्रदर्शन, 2, 3, 4 अक्टूबर, 74 को बिहार बन्द का सफल आह्वान, 4 नवम्बर को जे० पी० की ऐतिहासिक सचिवालय घेराव की यात्रा किसे याद नहीं होगी।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन को अन्ततः जे० पी० ने मोड़ दिया था, 5 जून, 74 को सम्पूर्ण क्रान्ति की घोषणा करके, कि हमें सत्ता परिवर्तन ही नहीं

करना है वह तो पड़ाव है। सम्पूर्ण क्रांति हमारी मंजिल होगी। 4 नवम्बर को पूरी तरह स्पष्ट हुआ कि बिहार सरकार तो केन्द्रीय सरकार की कठपुतली मात्र है। तब चुनाव में निबटा जायेगा, कहकर जे०पी० ने आन्दोलन को राष्ट्रव्यापी विस्तार दिया। पूरे देश में वे दौरा करने लगे।

केन्द्रीय सत्ता में विराजमान श्रीमती गांधी को भय लगा। आन्दोलन की आंच वे सह नहीं सकी। उन्होंने प्रतिक्रिया में चोट की। 25 जून, 75 की अंधेरी रात आयी। इंदिरा जी का ताण्डवनृत्य शुरू हुआ। लोकनायक समेत राष्ट्रीय नेता जेलों में डाल दिए गए। लोकतन्त्र का मुखौटा उतार फेंका गया। इन्दरा गांधी ने स्वयं तानाशाही का खुला खेल खेला। छात्र-युवा शक्ति ने राष्ट्रीय प्रतिकार शान्तिपूर्ण ढंग से प्रारंभ किया। बुलेटिने छापकर गुप्त रीति से बंटने लगी। नवम्बर, 14 सन 75 से लोक संघर्ष समिति के आह्वान पर सत्याग्रह हुआ। हजारों की संख्या में छात्रों नौजवानों ने सत्याग्रह किया। इसी संघर्ष के मोर्चे के रूप में 77 का लोकसभा चुनाव उपस्थित हुआ। इन्दिरा जी को लेनी की देनी पड़ गई। लोकनायक ने इस चुनाव को तानाशाही और लोकशाही के बीच का चुनाव बताया। लोकनायक का संदेश लेकर छात्र युवक दौड़ पड़े गांवों की ओर। चुनाव में इन्दिरा गांधी की तानाशाही पराजित हुई। लोकतन्त्र जीता। संघर्ष की आंच में विभिन्न दलों के अस्तित्व पिघल गये थे। जे० पी० की तपस्या और नेतृत्व के कारण और छात्र-युवकों के खून पसीने की कीमत पर सत्ता परिवर्तन हुआ और विकल्प के रूप में जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। छात्र-युवकों के बलिदान, जे० पी० की तपस्या और भारतीय जनता के विवेक के परिणामस्वरूप यह सरकार सत्ता में आई। इसके पीछे छात्र-युवकों का जो खून पसीना लगा है, वह हमें विरासत में मिले है।

3. छात्रशक्ति को यह अहसास भी है उसे सत्ता परिवर्तन के पड़ाव पर पहुंच कर रुकना या सत्ता के भूलभुलैया में भटक नहीं जाना है। किसी भी देश का नवनिर्माण विधानसभा की चाहर दिवारी के अन्दर या सत्ता के भारी भरकम यंत्र के द्वारा नहीं होता, वे तो जनाकांक्षाओं की पूर्ति में साधन बनकर ही सार्थक रह सकते हैं। वह विराट लोकशक्ति के जागरण, जनसहभाग के जरिए होता है। राष्ट्र कल्प अथवा नवनिर्माण तो लोकसत्ता और राजसत्ता के बीच सम्यक् समीकरण की स्थापना तथा तदनुकूल क्रियाशीलता से ही संभव है। इस समीकरण तथा क्रियाशीलता के लिए यह जरूरी है कि विधानसभाओं की अंग कार्यकारिणी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर विधानसभाओं की जनित लोकसत्ता का क्रियात्मक सहभाग अग्रसर हो। छात्रशक्ति लोकसत्ता के क्रियात्मक सहभाग का जीवन अंग है और स्वयं लोकसत्ता की जीवनी शक्ति का प्रकट रूप है, ऐसा हम मानते है।

अतः छात्रशक्ति की साधना अभी अधूरी है उसे रुकना नहीं है, आत्म-संतोष में बिखरना नही है, उसकी यात्रा शेष है। समाज-परिवर्तन, का पहाड़ उसे चढ़ना है, छात्रयुवा वर्ग के सामने गंभीर चुनौतियां है।

4. सत्ता और दलगत राजनीति से बाहर रहने में ही छात्रशक्ति की सार्थकता है। सत्ता से उसकी धार भोथरी हो जायेगी। हम सरकार के न अंधभक्त है, न अंध विरोधी। जनता-सरकार के प्रति हमारी आत्मीयता अवश्य है, आन्दोलन की उपज होने के कारण हम चाहते हैं और हमारी शुभकामनाएं इसके साथ हैं कि वह राष्ट्र कल्प का कार्य करें, पर हमारे समर्थन को हमेशा के लिए किसी भी परिस्थिति में वह पूर्ण स्वीकृत न मान लें।

5. आज भी वे तत्व जो तानाशाही के व्यवहार में आस्था रखते तथा अपने पूंजित स्वार्थों को सुरक्षित मानते हैं, सक्रिय है। चोटखाये है पर नाखून घिस कर पैना कर रहे है। छात्र-युवाशक्ति की निगरानी रखनी है कि वे तत्व सर न उठा पायें। कोई भी सत्ता तानाशाही की ओर अग्रसर न हो सके ऐसी प्रचण्ड दबावशक्ति जनता को पैदा करनी है। इसके लिए आवश्यक रहेगा कि छात्र शिक्षाक्षेत्र को राजनैतिक हस्तक्षेप और चालबाजियों से मुक्त करें। छात्रों का राजनैतिक हितों के लिए शोषण नहीं हो यह जरूरी है। शिक्षाक्षेत्र को स्वयंपूर्ण सही नेतृत्व उत्पन्न करने में समर्थ, स्वावलम्बी रहना है। हमें जनता के बीच, उसकी चेतना को विकसित करने तथा उसे उदय बनाये रखने के लिए जाना है। एक ओर तानाशाही एवं समाज विरोधी तत्व (राजनैतिक और गैर राजनैतिक) सक्रिय हैं, दूसरी ओर विभिन्न राजनैतिक गुट छात्रों की शक्ति को अपनी हैसियत बढ़ाने की दृष्टि से उपयोग करने में लगे है, वर्तमान सरकार कहीं गद्दी में जाकर महलों की भूलभुलैया में अपने को भूल न जाये यह भी देखना है। जनता के बीच जाकर छात्रों नौजवानों को संगठित होकर ऐसी ताकत पैदा करनी है कि आपात्काल का इतिहास किसी भी सरकार द्वारा भविष्य में न दोहराया जा सके।

हमें अभी हमारी मंजिल नहीं मिली है। सत्ता-परिवर्तन तो पड़ाव भर था। सम्पूर्ण क्रान्ति लक्ष्य है। समाज परिवर्तन, व्यवस्था-परिवर्तन उसके पहलू है। राजशक्ति पर लोकशक्ति का अंकुश उसका एक पहलू है। महात्मा गांधी और जयप्रकाश के सपनों का भारत बनाने को हम कृत संकल्प है। हम उसके शिल्पी हैं। हमारी वह साध है। हम ही उसके लिए सक्षम हैं। हम जानते है कि सत्ता परिवर्तन को व्यवस्था में परिवर्तन लाने का साधन बनाया जा सकता है, पर सत्ता लोगों की स्वार्थसिद्धि का उपकरण न बन जाए यह भी देखना है। कल्याणकारी लक्ष्य से वह भटक न जाए भटकने पर उसे जनता की दण्डशक्ति तैयार मिले यह भी इन्तजाम करना है।

इस दृष्टि से छात्र-युवाशक्ति को एक ओर शिक्षाक्षेत्र को सबल, संगठित, सत्ता राजनीति की पहुंच से परे खड़ा करना है। शिक्षा शिक्षाविदों के हाथ हो, शिक्षा को समाज रचना में आर्थिक संरचना में आज अपेक्षित स्थान को बचाना उसे सम्मान का स्थान मिले, प्राथमिकता मिले यह देखना है। बिहार आन्दोलन की 12 सूत्री मांगों और अन्य मूलभूत मांगों यथा मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर रोक की मांग आदि को जागृत रखना है, इस सरकार से सही कार्य कराने है। उसमें सरकार की ढिलाई न हो, नजरअंदाजी कहीं हो यह ध्यान रखना है।

6. हमारे आगे लोकनायक ने दो लक्ष्य रखें है एक रचनात्मक व्यवस्था-परिवर्तन का और दूसरा लोकशक्ति और राजशक्ति के बीच समीकरण बैठाने का। इसके लिए एक ओर ग्रामोन्मुखी होकर छात्रों युवकों की शक्ति को रचनात्मक अभियान, प्रकल्प आदि होंगे। जनता को इसके दायित्व और अधिकारों की समझदारी बढ़ानी होगी। इसके लिए हमें एक ओर शिक्षा की स्वायत्तता, शिक्षा के लोकतंत्रीकरण, शैक्षिक वातावण, शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति में परिवर्तन आदि लक्ष्य पूरे कराने है इसके लिए छात्रों को जागरुक संगठन निर्माण, समाज में वह मांग पैदा करना और सरकार पर दबाव देना होगा। दूसरी ओर छात्रों की शक्ति अनेकाविध रचनात्मक कार्यों यथा, सामाजिक कुरीतियों के

खिलाफ संघर्ष, दहेज, फिजूलखर्ची आदि के शोषण के खिलाफ स्थानीय संघर्ष की स्थितियां भी पैदा करनी होगी, वहीं तीसरी ओर सरकार के ऊपर अंकुश के नाते कार्य करना है। इस तीसरे काम का स्वरूप होगा सरकार के अच्छे कामों का उल्लेख कर सहयोग देते हुए उत्साह बढ़ाना और उसके गलत कामों की जिम्मेवारी पूर्वक निन्दा करते हुए विरोध प्रगट करना। उसे विरत करने के लिए दबाव देना। पर इस काम में हम न सरकार को भटकने देंगे न टूटने देंगे न किसी को तोड़ने देंगे। हम छात्र नौजवानों को आक्रमक किन्तु उत्तरदायी, रचनात्मक और संघर्षशील भूमिका अदा करनी है। हम अंकुश का काम करेंगे, हथौड़े का नहीं। अंकुश की धार तेज रखनी होगी। इस्तेमाल भटकाव के समय करना होगा। दिशा पर निगाह रखनी होगी। खुद मंजिल पर आगे बढ़ना होगा तथा सरकार को उस रास्ते से ले चलना होगा। महावत की समझदारी हाथी से अधिक है, इसका हमें ध्यान है। हाथी के प्रति स्नेह भी रखेंगे पर उसे मनमानी करने की छूट भी नहीं देंगे।

उपर्युक्त निवेदन में छात्रयुवा वर्ग के चिन्तन तथा दायित्व-संकल्प स्पष्टतया उभरते है। हमारी तैयारी लोकसत्ता तथा राजसत्ता के सही समीकरण की तलाश तथा उसे क्रियाशील करने एवं बनाये रखने की है। हम छात्र-युवा अपने सहभाग के तौर पर जनता-सरकार को हर प्रकार का उचित सहकार देने को तैयार है, बशर्ते वह भी हमें सही वातावरण दे। हम गांव-गांव जाकर ग्रामीण उत्थान तथा जन-जागरण करने को तैयार है, हम हर जनतन्त्र विरोधी, समाज विरोधी, तानाशाही तत्वों से टक्कर लेने को प्रस्तुत है। राष्ट्रकल्प के लिए हम वह हर कुछ करने को कृत-संकल्प है जिसकी अपेक्षा राष्ट्र हमसे करता हो। हमने अपने दायित्व-संकल्प को भी स्पष्ट किया है, उस दिशा में हमारी रचनात्मक भूमिका है। अब यह तो सरकार पर निर्भर है कि छात्र-युवाशक्ति को वह किस दिशा में क्रियाशील होने को प्रेरित करती है।

उपर्युक्त संदर्भ में कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं, इस प्रस्तुति को हमारा मांग-पत्र भी कहा जा सकता है। यों हम इन्हें सुझाव ही कहना पसन्द करेंगे, क्योंकि हर जायज मांग सुझाव ही हुआ करती है और हमारी मांगे जायज है, ऐसा हम मानते हैं। अगर ये गलत हो या त्रुटिपूर्ण हों तो हमें बतलाने का कष्ट किया जाए।

हमारी मांगें

(क) पूर्ववर्ती : मंहगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की समाप्ति के साथ-साथ 1974 के बिहार-आन्दोलन की अन्य मांगों (विधानसभा भंग करो को छोड़कर) को अविलम्ब पूरा किया जाय।

(ख) सार्वजनिक :
1. सभी मंत्री, विधायक तथा सांसद एवं उनके रिश्तेदारों की सम्पत्ति का ब्यौरा प्रकाशित किया जाय।
2. केन्द्रीय लोक सेवा आयोग एवं अन्य केन्द्रीय परीक्षाओं में राष्ट्रभाषा के प्रयोग को चालू किया जाय।
3. रोजगार के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाय।
4. पंचायतों तथा लोकपाल को क्रमशः स्थानीय स्वशासन संबंधी अधिकारों को व्यापक बनाकर अधिक शक्तिशाली बनाया जाय।
5. जन-सहभाग के लिए हर प्रशासनिक स्तर पर तथा हर मुद्दे पर सलाहकार समितियां गठित हों।

(ग) शैक्षिक :
1. वर्तमान शिक्षा-पद्धति में बुनियादी परिवर्तन हो एवं रोजगार से डिग्री का संबंध विच्छेद किया जाय।
2. शैक्षिक स्वायत्तता के लिए शिक्षा जगत में राजनैतिक दलों एवं उनके छात्र-युवा संगठनों का हस्तक्षेप बन्द हो एवं इसके लिए आचार संहिता बनायी जाय तथा शिक्षाक्षेत्र शिक्षाविदों, छात्रों तथा नागरिकों को सौंपा जाय।
3. बिहार का शिक्षा-बजट 2.75 % से बढ़ाकर 7% किया जाय।
4. छात्रों के लिए सस्ते दर पर भोजन, खाद्य सामग्री, पुस्तकें, स्टेशनरी के सामानों की आपूर्ति एवं कैंटीन की व्यवस्था प्रत्येक महाविद्यालय में की जाय।
5. (i) प्रत्येक विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम चले और कृषि विज्ञान की पढ़ाई हो।
   (ii) प्रत्येक जिला मुख्यालय में बी० एड०, आई०टी०आई०, पोलिटेकनिक एवं विधि की पढ़ाई हो।
   (iii) प्रत्येक महाविद्यालय में आनर्स की पढ़ाई की व्यवस्था हो।
6. आयुर्वेदिक एवं होमियोपैथिक विषयों में एलोपैथिक चिकित्सकों जैसी शिक्षा व्यवस्था, सुविधाएं तथा रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराये जायें। इसके लिए संबद्ध संस्थाओं को निकटतम विश्वविद्यालय से अंगीभूत किया जाय।
7. बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में बढ़ रही अराजकता, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, छात्रों पर हो रहे लाठी चार्ज आदि के विरुद्ध कड़े कदम उठाये जायें ताकि सीतामढ़ी, बड़हिया जैसे गोलीकाण्ड की पुनरावृति न हो।
8. शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के लिए आवश्यक एवं अविलम्ब कार्यवाई हो, जैसे—
   (i) विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर प्रकाशित हो।
   (ii) परीक्षा समाप्ति के 30 दिनों के भीतर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाय।
9. महाविद्यालयों के अधिकतम छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था और छात्रवृत्ति की मात्रा तथा राशि में वृद्धि हो।
10. शिक्षण-शुल्क को समान बनाया जाय।
11. खेलकूद के विकास के लिए क्रीड़ा विश्वविद्यालय एवं पृथक मंत्रालय की स्थापना की जाय तथा प्रत्येक महाविद्यालय में क्रीड़ा प्रशिक्षक, खेल-सामग्री और खेल मैदान की व्यवस्था की जाय।

विश्वास है कि आपके निर्देश में सरकार उपर्युक्त सुझावों की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करेगी ताकि छात्र-युवाशक्ति को रचनात्मक क्रिया दिशा दी जा सके। ✲ ✲

युवा जनता की माँगें

चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वायदे पूरे करो

युवा जनता ने 18 मार्च 1978 को राज्यों की राजधानियों में जनता पार्टी की सरकार को चुनाव-घोषणापत्र में किये गये उसके वायदों की याद दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। उसकी मांग है कि :

1. हर बालिग नागरिक को रोजगार का कानूनी अधिकार हो और इसे संविधान में दर्ज किया जाय।

2. इस अधिकार को अमली रूप देने के लिए हर प्रखंड में सर्वेक्षण द्वारा बेरोजगारों की सूची बनायी जाय और संविधान में इस अधिकार के दर्ज न होने तक सरकार रोजगार दफ्तरों में दर्ज व्यक्तियों को कम-से-कम 100 रु० का माहवारी भत्ता दे।

3. शिक्षा में मौलिक परिवर्तन जे० पी० आंदोलन की मुख्य मांग रही है। पांच साल में निरक्षरता दूर करना, पब्लिक स्कूल तथा वर्ग-भेद पैदा करनेवाली शिक्षा-संस्थाओं को तुरंत समाप्त करना, प्राथमिक से लेकर शोध तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना और मैट्रिक के बाद हर विद्यार्थी को रोजगार की सुविधा देना जरूरी है। इनके आधार पर नयी शिक्षा-पद्धति बन सकती है। सरकार जल्द-से जल्द ऐसी शिक्षा-नीति की घोषणा करे।

4. विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा-संस्थाओं के प्रशासन का लोकतंत्रीकरण हो। वर्तमान परीक्षा-प्रणाली को समाप्त कर योग्यता जांचने की कोई वैकल्पिक पद्धति चलायी जाय।

5. 18 वर्ष के नागरिकों को मताधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाय और चुनाव-प्रणाली के सुधार के लिए जे०पी० द्वारा नियुक्त तारकुंडे कमेटी की रपट पर सरकार निर्णय करे। प्रतिनिधि-वापसी के अधिकार को कानूनी रूप दिया जाय।

6. बिना अदालती विचार के कैद रखने की गैरलोकतंत्री प्रथा को संविधान से हटाया जाय और जेलों में जितने भी इस प्रकार के बंदी हैं, उन्हें तत्काल रिहा किया जाय। जेल के बर्बर ब्रिटिश ढांचे को समाप्त कर एक सभ्य और आधुनिक ढांचा बनाया जाय।

7. विकेन्द्रीकरण जनता पार्टी का सर्वसम्मत कार्यक्रम है। पंचायत से जिला-परिषद् तक सीधा चुनाव हो। स्थानीय प्रशासन पर पंचायत प्रखंड और जिला-परिषद् का नियंत्रण हो और इनके अधिकारों और कर्त्तव्यों का उल्लेख संविधान में हो।

8. चीनी और अन्य खाद्य वस्तुओं का निर्यात तत्काल बंद हो ताकि इनके दाम घटें। दवा, साधारण कपड़ों तथा आदमी की प्राथमिक जरूरतों की चीजों का लागत-मूल्य घोषित करना जरूरी हो ताकि जनता के दबाव से इनके दाम घटाये जा सकें।

9. जनता पार्टी ने चुनाव-घोषणा-पत्र में जीवन में सादगी लाने और आर्थिक विषमता घटाने की बात कही थी पर किया कुछ नहीं। पांच स्टारवाले होटलों को बंद कर इस दिशा में तुरंत कदम उठाये जांय। रेलों में एयरकंडीशन डिब्बे समाप्त हों। भोग-विलास की वस्तुओं का आयात तत्काल बंद हो। मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों और निजी व सरकारी क्षेत्र के सेठों और अफसरों की सुविधाओं में तत्काल कटौती की जाय।

10. सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए संथानम कमेटी की सिफारिशें तुरंत अमल में लायी जांय। मंत्रियों, संसदसदस्यों, विधायकों तथा गजटिया अफसरों द्वारा अपनी तथा नजदीकी संबंधियों की सम्पत्ति की सार्वजनिक घोषणा के लिए तत्काल कानून बनाया जाय।

11. सम्पति के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों की सूची से हटाया जाय।

12. हरिजनों, पिछड़ी जातियों तथा आदिवासियों को सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिला-स्तर पर स्वतंत्र संस्थाएं बनायी जायं और उन्हें कानून अधिकार दिये जायं। इन अधिकारों को लागू करने के लिए उनका अपना संगठन रहे।

13. साबुन, जूते आदि वस्तुओं को, जो गांवों में और कुटीर-उद्योगों में बनायी जा सकती है, बड़े उद्योगों द्वारा बनाना मना हो।

14. हर गांव में पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो और हर खेत की सिंचाई के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा हो।

15. करघनिया माल और खेतिहर उत्पादन की वस्तुओं के दाम में संतुलन रखा जाय।

16. जब तक गरीब और छोटे किसान की हालत नहीं सुधारी जाती तब तक उनके यहां काम करने वाले खेतिहर मजदूरों को सरकार आधी मजदूरी दे।

★ ★ ★

छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी की घोषणा

अब नई लड़ाई लड़नी है !

लगातार कई वर्षों से पल रहा जन-असंतोष सन्, ७४ में अचानक विद्रोह बनकर फूट पड़ा था। लोकनायक जयप्रकाश ने इस अस्त-व्यस्त विद्रोह को समेटा-सवारा और एक नयी दिशा दी। जनता की कई वर्षों की जड़ता टूटी। जन-मानस आन्दोलित हुआ। आजादी की लड़ाई के बाद यह पहला जन-आन्दोलन था जिसमें आम आदमी की तकलीफ, असंतोष और आम आक्रोश को आवाज मिली।

पिछला चुनाव इसी आन्दोलन का एक पड़ाव था। यह शायद पहला आम चुनाव था, जिसमें आम आदमी की सीधी भागीदारी थी। ३० साल से चली आ रही और अन्ततः खुल कर तानाशाही कुचक्र चलाने वाली कांग्रेसी सरकार की पराजय के रूप में एक ऐतिहासिक परिणाम भी सामने आया। नयी सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बने एक वर्ष बीत गया। आज एक वर्ष के बाद जब हम इस सरकार के कारनामों को देखते हैं तो यह स्पष्ट दिखता है कि आम आदमी द्वारा बनायी गयी यह सरकार आम आदमी की अपेक्षाओं और आशाओं से कितनी अलग है।

आज इस प्रतीक दिवस (१८ मार्च) के दिन हम सरकार को यह याद दिलाते हैं कि आम आदमी की ताकत पर बनी यह सरकार जनता की आशाओं-आकांक्षाओं की उपेक्षा कर, कुचलकर टिक नहीं सकती। साथ ही हम तमाम जनता को आवाज देते हैं कि अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति सजग हुए बिना सरकार से किसी भी तरह की अपेक्षा करना व्यर्थ है।

बीते हुए एक वर्ष में सरकार का कोई प्रयास, कोई नीति, कोई योजना इस बात का परिचायक नहीं है कि वह शोषित-दलितों के साथ है।

- भूमि-सम्बन्धी कानून अभी भी कागजी है।
- सरकार किसी भी तरह के कमजोर वर्गों की रक्षा में असमर्थ रही है।
- सम्पत्ति के अधिकार की जगह काम के अधिकार को संविधान में शामिल करने की बात पर बिल्कुल चुप्पी है।
- मंत्रियों और विधायकों के खर्च पर कोई पाबन्दी नहीं।
- दोहरी शिक्षा नीति (पब्लिक स्कूल) आज भी बरकरार है।

इतना ही नहीं, कई बातें तो जनता पार्टी की सरकार की नीयत के प्रति भी संदेह पैदा करती है।

- सत्ता पर जनता के अंकुश के लिए प्रतिनिधि वापसी के अधिकार को नकार दिया गया।
- सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा छोटे राज्यों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
- मीसा, डी० आई० आर०, गुण्डा एक्ट जनता पार्टी की सरकार के तानाशाही रुख को ही प्रकट करती है।

एक सरकार को बदल कर दूसरी सरकार बना लेना आसान है, लेकिन शोषण पर आधारित सम्पूर्ण व्यवस्था को बदल कर एक शोषणमुक्त समाज बनाना उतना आसान नहीं। शोषण के आधार पर खड़ी इस व्यवस्था के विरुद्ध हमें हर कदम सोच-समझ कर उठाना है। हमें शोषित की आह-कराह और आक्रोश को समेट कर एक निश्चित जमीन तैयार करनी है—एक नई लड़ाई की शुरूआत के लिए; सम्पूर्ण क्रांति की अगली और नई लड़ाई ! हमें गांवों की ओर बिखरी शक्तियों को एक सूत्र में बांधना है। युवा-शक्ति को शोषित-दलित किसान और मजदूर के आक्रोश और सपनों के साथ-साथ जोड़ना है।

हम आगामी 8 अप्रैल को बोध गया के गांवों में वहां के मठ और मठाधीश के सामने शान्तिमय प्रदर्शन करने जा रहे है। हमारी लड़ाई अब सीधे जमीन पर होगी, यह उसकी सांकेतिक शुरुआत है। हम शोषित-दलित जनता के साथ मिल कर संघर्ष करेंगे और सरकार पर भी दबाव डालेंगे।

हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि वह अपनी नीतियां स्पष्ट करे, अपना मूल्यांकन करे और अपना रवैया बदले।

—बिहार प्रदेश छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी
कदमकुआं, पटना-3

[पृ० ८ का शेष]

किया। वे कोई कानून, दया या मर्यादा नहीं जानते थे। क्या ऐसे लोग युवा लोगों का मार्ग दर्शन करने के योग्य हो सकते हैं? क्या उनका छात्र सम्मान करेंगे।

हमारे दिनों में उच्च शिक्षा पाने वाले छात्र सभ्यजन माने जाते थे। अध्यापक उन्हें मिस्टर कह कर संबोधित किया करते थे। हम देश में उच्च शिक्षा पाने वालों के लिए जिन पर कि हमारे अभिभावक व राष्ट्र भारी धन व्यय कर रहे हैं आज के इस व्यवहार को अनुचित समझते है।

मैं उन दिनों को लेकर व्यर्थ विलाप नहीं करना चाहता। पर विगत प्रायः ही प्रशंसा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। पर कम से कम उन अवांछनीय दिनों में अध्यापकों व विशेषकर उपकुलपतियों को अपने साथियों व छात्रों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े रहना था। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो अपने शिष्यों को क्या आदर्श दे सकते हैं। अब भी वे अपने पदों से त्याग पत्र देकर स्थिति सरल कर सकते हैं। आखिर वे भारी विद्वान माने जाते हैं और केवल रोटी कमाने के लिए वे उपकुलपति नहीं बनाये गये थे।

अधिकारी इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? उनका कहना है कि अवधि खतम होने से पूर्व वे इन लोगों को नहीं हटा सकते। पर ऐसी सरकार, जो सच्ची क्रांति के बल पर आई है, का ऐसा कहना समझ नहीं आता। उसका मतलब होगा जिसे वे सत्ता में आते समय क्रांति कहते थे उसका तात्पर्य उनका अपने प्रति मत पाने से था। यदि जनता सरकार को अपने सत्ता में रहने का औचित्य सिद्ध करना है तो वह आपत्काल से पूर्व की स्थिति वाली सरकार जैसी बातें नहीं कर सकती। उन्हें समस्याओं का हल पाना है जो अनन्त हैं। यह देखना होगा कि छात्रों की पढ़ाई जारी रहे क्योंकि छात्र हड़ताल गरीब करदाता पर भारी मार है।

मेरी छात्रों को सलाह है कि वे अपनी पढ़ाई के प्रति उपेक्षा न बरतें। वे अपनी कक्षाओं व पढ़ाई के बाद के घंटों में आन्दोलन चलायें।

पंतनगर कांड : छात्रों की विवेकपूर्ण भूमिका

अन्तराष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय पन्त नगर 13 अप्रैल को अखबारों की सुर्खियों में आ गया। पिछले एक लम्बे समय से चले आ रहे श्रमिक असन्तोष और राजनैतिक रोटी भूनने वाले दलीय प्रतिबद्ध श्रमिक नेताओं एवं राजनैतिक नेताओं के कारण पुलिस की गोली से भारी संख्या में श्रमिकों की जानें गईं तथा अनेकों घायल हुए।

घटना क्यों घटी। घटना क्रम क्या रहा। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, यह सवाल विस्तार के साथ अखबारों में आ भी चुके हैं तथा प्रमाणित जानकारी के लिए जब न्यायिक जांच हो रही है तो उस पर कुछ भी मत देना उचित नहीं किन्तु इसके बाद भी कुछ ऐसे सवाल शेष है जिनके बारे में विस्तार से चर्चा की जानी अति आवश्क है।

कोई प्रयास नहीं

पन्तनगर काण्ड किसकी गलती से हुआ यह अलग विषय है किन्तु जब पुलिस द्वारा गोली चार्ज हो गया कइयों की जानें गईं तथा कई घायल हुए तब ऐसी स्थिति में अवश्य ही स्थिति को और न बिगड़ने देने के लिए पहले बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए थी। किन्तु उसका कोई इन्तजाम न तो कुलपति और न ही जिला प्रशासन की ओर से किया गया। यह तो सामान्य समझ की बात है कि इतनी भयंकर स्थिति में कर्फ्यू लगाया जाना ही एक मात्र हल हो सकता था। प्रशासन सेना को सौंप देना ही श्रेयष्कर होता। बजाय इसके कि कुलपति महोदय कोई कारगर कदम उठाते, वह विश्वविद्यालय परिसर छोड़कर ही चले गये। जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। प्रत्यक्षदर्शी इस बात के गवाह है कि घटना से एक सप्ताह तक पन्त नगर में कोई प्रशासन नहीं रहा। अराजकता की स्थिति बनी रही। आज भी सही बात तो यह है यहां श्मशान की खामोशी है। कोई भी अफसर दूसरे से किसी कमी के बारे में सवाल नहीं कर सकता। बस, अपना-अपना काम (जितना करना चाहो) करते रहो। निश्चय ही इसे प्रशासन नहीं कहा जा सकता।

घटना के तुरन्त बाद केवल मात्र कर्फ्यू लगाकर उन सभी बाकी घटनाओं को रोका जा सकता था जिनका उल्लेख पन्त नगर में कोई प्रशासन न होने और असामाजिक, राजनीतिक हित साधकों के दबदबे के कारण समाचार पत्रों तक में न आ सका। इन्हीं तत्वों द्वारा फार्म के गेहूं के पके खेत में आग लगा दी गयी (श्रमिक लोग अधिकांश में काण्ड हो जाने के बाद पन्त नगर छोड़कर अपने-अपने घरों को लौट गये थे) अधिसंख्यक श्रमिक पूरबी अंचलों से आये होने तथा अधिकारियों के जाट होने के कारण शरारती तत्वों द्वारा पूरब-पश्चिम की जहर फैलाने की काफी हद कामयाब साजिश की गई। विश्वविद्यालय की कितनी जीपें, टैक्टर और कृषि यन्त्र कार्य पर नहीं है, इसकी अभी किसी को सुधि ही ही नहीं है किन्तु यह सही है कि घटना के चार-पांच दिन तक लोग मन चाहे ढंग से यह सामान उठाकर ले गये। कुछ असामाजिक तत्वों ने चोरी के इरादे से और कुछ विद्यार्थियों ने मौज मस्ती के लिए पास के नगरों में टहलने के लिए जीपों आदि का प्रयोग किया। पैट्रोल पंप में भण्डारित तेल की एक बूंद भी अब नहीं है।

छात्रों ने मवेशियों के चारे, दूध वितरण, पानी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं और व्यवस्थाओं की पूर्ति स्वयं अपने स्तर पर जिम्मेदाराना ढंग से की जो अपने आप में एक मिसाल है।

असामाजिक तत्वों को मौका

फार्म के साथ पशु विभाग के अन्तर्गत पन्त नगर में बड़े कीमती-कीमती मवेशी भारी संख्या में है। कहीं कोई प्रशासन न होने के कारण उन्हें किसी ने चारा नहीं डाला। विद्यार्थियों द्वारा उन्हें चरने के लिए खोल दिया गया, इसी से असामाजिक तत्वों की बन आई और अनुमान है कि बहुत से मवेशी लापता है।

श्रमिकों का बहाना

प्रशासनिक अराजकता होने के कारण, एक खास वर्ग के लोगों को जो अधिकतर अफसर है (जैसे क्लर्क और श्रमिक जो इस वर्ग के थे, वह भी इस चपेट में आ गये) उन्हें तथा उनके बीबी बच्चों का विश्वविद्यालय परिसर में रहना मुश्किल हो गया। राजनैतिक गुण्डों ने श्रमिकों का बहाना लेकर इस वर्ग के लोगों को चुन-चुनकर मारा-पीटा और इसी भय से वह परिसर छोड़कर भाग गये। विश्वविद्यालय ने जो विश्वविद्यालय के लापता कर्मचारियों की सूची सरकार को दी उनमें यही लोग अधिकांश हैं।

नैनीताल के विधायक श्री रामदत्त जोशी को पीटा जाना भी इसी सदर्भ में देखा जाना चाहिए। इन असामाजिक तत्वों और दोनों कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नियोजित प्रोग्राम का परिणाम तो पन्त नगर काण्ड था ही, साथ ही वादी में खुली छूट मिल जाने के कारण इन्होंने ऐसी हवा बांध दी कि कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।

इस सारे काण्ड में यदि कहीं कुछ शुभ देखना है तो वह विद्यार्थियों की भूमिका रही है। विद्यार्थियों को गैर जिम्मेदार और अनुशासनहीन कहा जाता है, लेकिन पन्त नगर के छात्रों ने विवेकपूर्ण निर्णय लेकर विश्व विद्यालय को और अधिक तबाही से बचा लिया। यदि कहीं विद्यार्थी वर्ग लोक में आकर भावात्मक आधार पर प्रशासन के आगे अड़ जाता तो निश्चित ही घटित काण्ड उससे कहीं बड़ा होता। इतना ही नहीं, पन्त नगर में कोई प्रशासन न रहने पर छात्रों ने मवेशियों के चारे, दूध वितरण, पानी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं और व्यवस्थाओं की पूर्ति स्वयं अपने स्तर पर जिम्मेदाराना ढंग से की जो अपने आप में एक मिसाल है।

न्यायिक जांच में तो केवल गोली काण्ड की ही जांच होगी। किन्तु कांड के बाद हुए विश्व विद्यालय के नुकसान और गुण्डागर्दी और नाजायज राजनैतिक लाभ के कारण अप्रिय घटनाओं के सूत्रधारों का पकड़ा जाना और दण्डित होना अनिवार्य है।

—कस्तूरीलाल तागरा

दिशा

सुधार चाहने वाले लोग हैं कहां ?

स्वामी विवेकानन्द

सुधारकों से मैं कहूंगा कि मैं स्वयं उनसे कहीं बढ़कर सुधारक हूं। वे लोग केवल इधर-उधर थोड़ा सुधार करना चाहते हैं—और मैं चाहता हूं आमूल सुधार। हम लोगों का मतभेद है केवल सुधार की प्रणाली में। उनकी प्रणाली विनाशात्मक है और मेरी संगठनात्मक। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश मढ़ने का साहस नहीं कर सकता कि "तुम्हें इसी भांति चलना होगा, दूसरी तरह नहीं।" मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं, जो श्रीरामचन्द्रजी के सेतु बांधने के समय थोड़ा बालू लाकर—अपना भाग पूरा कर—संतुष्ट हो गयी थी। यही मेरा भाव है। यह अद्भुत राष्ट्र-जीवनरूपी यन्त्र युग-युग से कार्य करता आ रहा है, राष्ट्रीय जीवन का यह अद्भुत प्रवाह हम लोगों के सम्मुख बह रहा है। कौन जानता है, कौन साहसपूर्वक कह सकता है कि यह अच्छा है या बुरा, और यह किस प्रकार चलेगा ? हजारों घटना-चक्र उसके चारों ओर उपस्थित होकर उसे एक विशिष्ट प्रकार की स्फूर्ति देकर कभी उसकी गति को मन्द और कभी उसे तीव्र कर देते हैं। उसके वेग को नियमित करने का कौन साहस कर सकता है ?

सामाजिक व्याधि के प्रतिकार का उपाय—शिक्षा; बलपूर्वक सुधार-चेष्टा नहीं;

अतएव हमें केवल इतना ही समझ लेना होगा कि सामाजिक व्याधि का प्रतिकार बाहरी उपायों द्वारा नहीं होगा; हमें उसके लिए भीतरी उपायों का अवलम्ब करना होगा —मन पर कार्य करने की चेष्टा करनी होगी। चाहे हम कितनी ही लम्बी-चौड़ी बातें क्यों न करें, हमें जान लेना होगा कि समाज के दोषों को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं, वरन् शिक्षा-दान द्वारा परोक्ष रूप से उसकी चेष्टा करनी होगी। समाज के दोष दूर करने के सम्बन्ध में सब से पहले तत्त्व को समझ लेना होगा, और इसे समझकर अपने मन को शान्त करना होगा, अपने खून की चढ़ती गरमी को रोकना होगा, अपनी उत्तेजना को दूर करना होगा। संसार का इतिहास भी हमें यह बताता है कि जहां कहीं इस प्रकार की उत्तेजना से समाज के सुधार करने का प्रयत्न हुआ है, वहां केवल यही फल हुआ कि जिस उद्देश्य से वह किया गया था, उस उद्देश्य को ही उसने विफल कर दिया। दासत्व को नष्ट कर देने के लिए अमेरिका में जो लड़ाई ठनी थी, उसकी अपेक्षा अधिकार और स्वतन्त्रता की स्थापना के लिए किसी बड़े सामाजिक आन्दोलन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। समाज के दोषों को प्रबल उत्तेजना-पूर्ण आन्दोलन द्वारा अथवा कानून के बल पर सहसा हटा देने का यही बुरा परिणाम होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है—इस प्रकार का आंदोलन चाहे किसी भले उद्देश्य से ही क्यों न किया गया हो। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। यही कारण है कि मैं केवल दोष ही देनेवाली संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता। दोषारोपण अथवा निन्दा करने की भला क्या आवश्यता है ? ऐसा कौनसा समाज है, जिसमें दोष न हों ? सभी समाजों में तो दोष हैं। यह तो सभी कोई जानते हैं। हम मानते हैं कि यहां बुराइयां हैं। पर बुराई तो हर कोई दिखा सकता है। मानव-समाज का सच्चा हितैषी तो वह है, जो इन बुराइयों को दूर करने का उपाय बतावे। कोई एक दार्शनिक एक डूबते हुए लड़के को गम्भीर भाव से उपदेश दे रहा था, तो लड़के ने कहा, "पहले मुझे पानी से बाहर निकालिये, फिर उपदेश दीजिये।" बस ठीक इसी तरह भारत-वासी भी कहते हैं, "हम लोगों ने बहुत व्याख्यान सुन लिये, बहुतसी संस्थाएं देख लीं, बहुतसे पत्र पढ़ लिये, अब तो हमें ऐसा मनुष्य चाहिए, जो अपने हाथ का सहारा दे, हमें इन दु:खों के बाहर निकाल दे। कहां है वह मनुष्य, जो हमसे वास्तविक प्रेम करता है, जो हमारे प्रति सच्ची सहानुभूति रखता है ?" बस उसी आदमी की हमें जरूरत है। यहीं पर मेरा इन समाज-सुधारक आन्दोलनों से सर्वथा मतभेद है। आज सौ वर्ष हो गये, ये आंदोलन चल रहे हैं, पर सिवाय निन्दा और विद्वेषपूर्ण साहित्य की रचना के इनसे और क्या लाभ हुआ है ? ईश्वर करते ये यहां न होते ! इन्होंने पुराने समाज की कठोर समालोचना की है, उस पर तीव्र दोषारोपण किया है, उसकी कटु निन्दा की है; और अन्त में पुराने समाज ने भी इनके समान स्वर उठाकर ईंट का जवाब ईंट से दिया है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक भारतीय भाषा में ऐसे साहित्य की रचना हो गयी है, जो जाति के लिए, देश के लिए कलंकस्वरूप है। क्या यही सुधार है ! क्या इसी तरह देश गौरव के पथ पर बढ़ेगा ? यह है किसका दोष ?

आज हमारा व्यवस्थाप्रणेता स्वधर्मावलम्बी राजा नहीं है, अब लोक-शक्ति का संगठन आवश्यक है

इसके बाद एक और महत्त्वपूर्ण विषय पर हमें विचार करना है। भारतवर्ष में हमारा शासन सदैव राजाओं द्वारा हुआ है, राजाओं ने ही हमारे सब कानून बनाये हैं। अब वे राजा नहीं है, और इस विषय में अग्रसर होने के लिए हमें मार्ग दिखानेवाला अब कोई नहीं रहा। सरकार साहस नहीं करती। वह तो सर्वसाधारण के विचारों की गति देखकर ही अपनी कार्य-प्रणाली निश्चित करती है। अपनी समस्याओं को हल कर लेनेवाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगता

है—काफी लम्बा समय लगता है, इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी। अतएव सामाजिक सुधार की सम्पूर्ण समस्या यह रूप लेती है :—कहां है वे लोग, जो सुधार चाहते हैं? पहले उन्हें तैयार करो। सुधार चाहनेवाले लोग हैं कहां? कुछ थोड़े से लोग किसी बात को उचित समझते हैं और बस उसे अन्य सभी लोगों पर जबरदस्ती लादना चाहते हैं। इन अल्पसंख्य व्यक्तियों के अत्याचार के समान दुनिया में और कोई अत्याचार नहीं। मुट्ठी भर लोग, जो सोचते हैं कि कतिपय बातें दोषपूर्ण हैं, राष्ट्र को गति नहीं दे सकते। राष्ट्र में आज गति क्यों नहीं है? क्यों वह जड़भावनापन्न है? पहले राष्ट्र को शिक्षित करो, अपनी निजी विधायक संस्थाएं बनाओ, फिर तो नियम आप ही आप आ जायेंगे। जिस शक्ति के बल से, जिसके अनुमोदन में विधान का गठन होगा, पहले उसकी सृष्टि करो। आज राजा नहीं रहे; जिस नयी शक्ति से, जिस नये दल की सम्मति से नयी व्यवस्था गठित होगी, वह लोक-शक्ति कहां है? पहले उसी लोक-शक्ति को संगठित करो। अतएव, समाज-सुधार के लिए भी, प्रथम कर्तव्य है—लोगों को शिक्षित करना। और जब तक यह कार्य सम्पन्न नहीं होता, तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

संस्कार करने में हमें बीज के भीतर उसकी जड़ तक पहुंचाना होता है। इसी को मैं अमूल संस्कार कहता हूं। आग जड़ में लगाओ और उसे क्रमशः ऊपर उठने दो एवं एक अखण्ड भारतीय राष्ट्र संगठित करने दो।

महान् सुधारक श्रीशंकराचार्य और उनके अनुयायियों का अभ्युदय हुआ। उस समय से आज तक इन कई सौ वर्षों में भारतवर्ष की सर्वसाधारण जनता को धीरे-धीरे उस मौलिक विशुद्ध वेदान्त के धर्म की ओर लाने की चेष्टा की गयी है। उन सुधारकों को बुराइयों पर पूरा ज्ञान था, पर उन्होंने समाज की निन्दा नहीं की। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि "जो कुछ तुम्हारे पास है, वह सभी गलत है, उसे तुम फेंक दो।" ऐसा कभी नहीं हो सकता था।

अचानक परिवर्तन नहीं हो सकते। भगवान शंकराचार्य और रामानुज इसे जानते थे। इसलिए उस समय प्रचलित धर्म को धीरे-धीरे उच्चतम आदर्श तक पहुंचा देना ही उनके लिए एक उपाय शेष था। यदि वे दूसरी प्रणाली का सहारा लेते, तो वे कपटी सिद्ध होते; क्योंकि उनके धर्म का प्रधान मत ही है क्रम-विकासवाद। उनके धर्म का मूलतत्व यही है कि इन सब नाना प्रकार की अवस्थाओं में से होकर आत्मा उच्चतम लक्ष्य पर पहुंचती है। अतः ये सभी अवस्थाएं आवश्यक और हमारी सहायक हैं। भला कौन इनकी निन्दा करने का साहस कर सकता है?

प्राचीन और आधुनिक सुधारकों में भेद
अपने ढंग पर समाज-सुधार

क्या भारतवर्ष में कभी सुधारकों का अभाव था? क्या तुमने भारत का इतिहास पढ़ा है? रामानुज, शंकर, नानक, चैतन्य, कबीर और दादू कौन थे? ये सब बड़े-बड़े धर्माचार्य, जो भारत-गगन में अत्यन्त उज्ज्वल नक्षत्रों की नाईं एक के बाद एक उदित हुए और फिर अस्त हो गये, कौन थे? क्या रामानुज के हृदय में नीच जाति के लिए प्रेम नहीं था? क्या उन्होंने अपने सारे जीवन भर चाण्डाल तक को अपने सम्प्रदाय में ले लेने का प्रयत्न नहीं किया? क्या उन्होंने अपने साम्प्रदाय में मुसलमान तक को मिला लेने की चेष्टा नहीं की? क्या नानक ने मुसलमान और हिन्दू दोनों से समान भाव से परामर्श कर समाज में एक नयी अवस्था लाने का प्रयत्न नहीं किया? इन सभी लोगों ने प्रयत्न किया और उनका काम आज भी चल रहा है। भेद केवल इतना है कि वे आज के समाज-सुधारकों की तरह दाम्भिक नहीं थे; वे इनके समाज अपने मुंह से कभी अभिशाप नहीं उगलते थे। उनके मुंह से केवल आशीर्वाद ही निकलता था। उन्होंने कभी समाज के ऊपर दोषारोपण नहीं किया। उन्होंने लोगों से कहा कि हिन्दू जाति को धीरे-धीरे सतत उत्पन्न करना होगा। उन्होंने अतीत में दृष्टि डालकर कहा, "हिन्दुओ, तुमने अभी तक जो किया अच्छा ही किया, पर भाइयो, तुम्हें अब इससे भी अच्छा करना होगा।" उन्होंने यह भी नहीं कहा, "पहले तुम दुष्ट थे, और अब तुम्हें अच्छा होना होगा।" उन्होंने यही कहा, "पहले तुम अच्छे थे, अब और भी अच्छे बनो।" ये दो बातें जमीन-आसमान का फर्क पैदा कर देती हैं। हम लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार उन्नति करनी होगी। विदेशी संस्थाओं ने बल-पूर्वक जिस प्रणाली को हममें प्रचलित करने की चेष्टा की है, उसके अनुसार काम करना वृथा है। प्रभु की जय हो! हम लोगों को तोड़-मरोड़कर नये सिरे से दूसरे राष्ट्रों के ढांचे में गढ़ना असम्भव है! मैं दूसरी जातियों की सामाजिक प्रथाओं की निंदा नहीं करता। वे उनके लिए अच्छी हैं, पर हमारे लिए नहीं। उनके लिए जो कुछ अमृत है, हमारे लिए वही विष हो सकता है। पहले यही बात सीखनी होगी। अन्य प्रकार के विज्ञान, अन्य प्रकार के परम्परागत संस्कार और अन्य प्रकार के आचारों से उनकी वर्तमान सामाजिक प्रथा गठित हुई है। और हम लोगों के पीछे है हमारे अपने परम्परागत संस्कार और हजारों वर्षों के कर्म। अतएव हमें स्वभावतः अपने संस्कारों के अनुसार ही चलना पड़ेगा—और यह हमें करना ही होगा।

धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदण्ड है

मैं देखता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की भांति प्रत्येक राष्ट्र का भी एक विशेष जीवनोद्देश्य है। वही उसके जीवन का केन्द्र है, उसके जीवन का प्रधान स्वर है, जिसके साथ अन्य सब स्वर मिलकर समरसता उत्पन्न करते हैं। किसी देश जैसे इंग्लैण्ड में—राजनीतिक सत्ता ही उनकी जीवन-शक्ति है। धनाकौशल की उन्नति करना किसी दूसरे राष्ट्र का प्रधान लक्ष्य है। ऐसे ही और दूसरे देशों का भी समझिये। किन्तु भारतवर्ष में धार्मिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन का केन्द्र है और वही राष्ट्रीय जीवन-रूपी संगीत का प्रधान स्वर है। यदि कोई राष्ट्र अपनी स्वाभाविक जीवन-शक्ति को दूर फेंक देने की चेष्टा करे—शताब्दियों से जिस दिशा की ओर उसकी विशेष गति हुई है, उससे मुड़ जाने का प्रयत्न करे, और यदि वह अपने इस कार्य में सफल हो जाय, तो वह राष्ट्र काल-कवलित हो जाता है। अतएव यदि तुम धर्म को फेंककर राजनीति, समाजनीति अथवा अन्य किसी दूसरी नीति को अपनी जीवन-शक्ति का केन्द्र बनाने में सफल हो जाओ, तो उसका फल यह होगा कि तुम्हारा नामोनिशान तक न रह जायेगा। यदि तुम इससे बचना चाहो, तो अपनी जीवन-शक्तिरूपी धर्म के भीतर से ही तुम्हें अपने सारे कार्य करने होंगे—अपनी प्रत्येक क्रिया का केन्द्र इस धर्म को ही बनाना होगा। ★

केवल चेहरे नहीं सत्ता का चरित्र बदलो

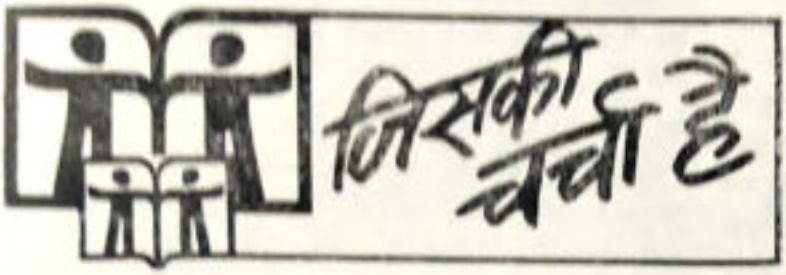

लोक सभा के चुनावों के समय जनता में जो उत्साह और आशा का संचार हुआ था वह कुल मिलाकर ठंडा पड़ गया है और जनता में निराशा की भावना बढ़ रही है। हम छोटी-छोटी बातों में उलझे रहें और 1977 में नई सरकार बनने पर जनता के मन में जो आशा फिर से जगी थी, उसे पूरा नहीं कर पाये तो देश में तानाशाही प्रवृत्तियां और ताकतों के पुनः उभरने का खतरा है।

त्रिमूर्ति पद छोड़े

★

जयप्रकाश नारायण

श्री जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर को एक पत्र लिखकर 'वर्तमान गम्भीर स्थिति' पर चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि तीस वर्षों के बाद आज हमें दुबारा एक मौका जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मिला है और इस अवसर को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अथवा आग्रह के कारण खो देना एक प्रकार से जनता के साथ धोखा होगा।

श्री नारायण ने कहा, 'हम छोटी-छोटी बातों में उलझे रहें और १९७७ में नयी सरकार बनने पर जनता के मन में जो आशा फिर से जगी थी, उसे पूरा नहीं कर पाये, तो देश में तानाशाही प्रवृत्तियां और ताकतों के पुनः उभरने का भी खतरा है। इसलिए देश के पुनर्जीवन का माध्यम बनने का जो गौरवपूर्ण अवसर जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, उसके अनुरूप हमें अपने को सिद्ध करना चाहिए।'

उन्होंने सुझाव दिया है कि पिछले जनआन्दोलन में जो बहुत से नये लोग आये और खासकर, वैसे युवक-युवतियां, जिन का तत्कालीन किसी दल से सम्बन्ध नहीं था। उन्हें राजनैतिक प्रवाह में दाखिल करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

उन्होंने कहा है कि राजनैतिक जीवन में नया खून आता रहे, ताकि वह हमेशा ताजा रहे, इसके लिए युवाशक्ति को प्रयत्नपूर्वक आगे लाना और पुराने लोगों का पदों की जिम्मेदारी से मुक्त होकर मार्गदर्शन की भूमिका अदा करना आवश्यक है।

श्री नारायण ने अपने पत्र में जनता पार्टी के तीन नेताओं सर्वश्री मोरारजी देसाई, चरणसिंह और जगजीवनराम की प्रशंसा की है और कहा है कि इन लोगों ने जो कुछ कार्य किये हैं, वे किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन साथ ही यह संकेत भी दिया है कि मैं चाहता हूं कि ये लोग स्वेच्छा से पद त्याग कर पार्टी और सरकार का मार्गदर्शन करें।

इस बात को नजरअन्दाज करना भी ठीक नहीं होगा कि लोकसभा के चुनावों के समय जनता में जो उत्साह और आशा का संचार हुआ था, वह कुल मिलाकर ठण्डा पड़ गया है और जनता में निराशा की भावना बढ़ रही है। इसकी तह में हमें जाना चाहिए।

पत्र में कहा गया है कि 'जनता के कष्ट दूर करने के लिए कार्यक्रमों का अपना महत्व तो है ही, पर बुनियादी बातों के बारे में पहले स्पष्ट हो जाना जरूरी है। मुझे लगता है कि जनतन्त्र को मजबूत बनाने और उसका सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए यह आवश्यक है कि केवल चुने हुए प्रतिनिधि को ही प्रशासनिक तन्त्र का आधार न रखकर उत्तरोत्तर ज्यादा से ज्यादा लोगों को को इस सारी प्रक्रिया में शामिल किया जावे।

उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि एक ओर जनता तथा दूसरी ओर उसके प्रतिनिधियों तथा प्रशासनतन्त्र के बीच की दूरी यथासम्भव कम हो। जनतन्त्र में आम जनता की आस्था बढ़ाने के लिए जरूरी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक तथा सार्वजनिक जीवन में सादगी और मितव्ययिता लायी जावे तथा आडम्बर और फिजूलखर्ची को रोका जावे।

मेरा जीवन व्रत

पत्रकार सम्मेलन में प्रसारित वक्तव्य

बड़ी चिन्ता की बात है कि वार्षिक परीक्षाओं के समय भी देश के अधिकांश विश्वविद्यालय छात्र-आन्दोलनों फलस्वरूप बन्द पड़े हैं। राष्ट्र की युवा-पीढ़ी के मन में व्याप्त निराशा और अशान्ति का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है ? इसे मात्र अनुशासनहीनता कह कर टाला नहीं जा सकता। युवा-पीढ़ी को आन्दोलन और विध्वंस के रास्ते से अलग करने का उपाय दमन का मार्ग नहीं, अपितु उसकी कर्म शक्ति को राष्ट्र-निर्माण के रचनात्मक कार्यों में प्रवाहित करना है। भारत के राजनीतिक नेतृत्व को आज खुलेमन से यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि युवा-पीढ़ी की कर्म शक्ति को रचनात्मक दिशाओं में प्रवाहित करने की दृष्टि से उसके द्वारा पिछले ३० वर्षों में कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ है।

नानाजी देशमुख

हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि आपातकालीन अधिनायकवाद के विरुद्ध संघर्ष में लोकतंत्र की विजय पताका को फहराने में लोकनायक जयप्रकाश जी के व्यक्तित्व के साथ युवा-पीढ़ी का ही सर्वाधिक योगदान रहा है। युवा-पीढ़ी ही उस वोट क्रान्ति का मुख्य वाहक बनी, जिसके फलस्वरूप केन्द्र में सत्ता परिवर्तन का कल्पनातीत चमत्कार घटित हो सका और जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। यह एक युग-परिवर्तन था, जिसने नयी पीढ़ी के मन में राष्ट्र निर्माण के प्रति अदम्य उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास का संचार किया था। किन्तु यह बहुत पीड़ा और चिन्ता की बात है कि गत एक वर्ष में हम उस उमंग और उत्साह को रचनात्मक दिशा नहीं दे पाये। आज वह पुनः आन्दोलन तथा विध्वंस के रास्ते पर भटक गई है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन सत्ता-राजनीति के दायरे में सिमट गया है। स्वाधीनता के पूर्व गांधी जी की प्रेरणा से जो रचनात्मक राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, वह भी स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात उपेक्षावश बिलकुल मूख गयी। रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा का ही परिणाम है कि एक ओर तो हम विगत तीस वर्षों में राष्ट्र जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई मौलिक रचना खड़ी नहीं कर पाये, दूसरी ओर सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन सत्ता-अभिमुखी राजनीति का बन्दी बन गया। ऐसी स्थिति में युवा पीढ़ी को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा मिलती भी तो कहां से और कैसे ? युवा पीढ़ी की कर्म-शक्ति को रचनात्मक दिशाओं में प्रवाहित करने के लिए आवश्यक था कि राष्ट्र के वरिष्ठ एवं प्रभावशाली राजनेता स्वयं रचनात्मक कार्य का उदाहरण प्रस्तुत करते और उसमें युवा पीढ़ी को सहभागी बनाते।

युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के कार्य में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिज्ञ अपने आचरण के द्वारा यह सिद्ध करें कि सत्ता हमारे लिए साध्य न होकर राष्ट्र निर्माण का एक रचनात्मक साधन है। यह तभी हो सकता है जब हममें से कुछ वरिष्ठ अनुभवी राजनेता स्वेच्छा से सत्ता को त्याग कर रचनात्मक कार्यों में जुटें। एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए भी मेरे मन में यह विचार इतना प्रबल होता जा रहा है कि अब मैं उसे दबा सकने में असमर्थ हूं।

मुझे लगता है कि जीवन के 60 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद भी मैं केवल राजनीतिक कार्य में ही लगा रहूं यह ठीक नहीं है। अब मुझे अपना शेष जीवन रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। देश में व्याप्त बेकारी गरीबी और आर्थिक तथा सामाजिक विषमता सीमा पार कर चुकी है। केवल क्रान्तिकारी नारे, चुनाव रणनीति, संसदीय गतिविधि एवं विध्वंसात्मक आन्दोलन के माध्यम से यह समस्या कदापि हल नहीं होगी। इसका एक ही उपाय है कि उत्पादन को बढ़ाने तथा बेकार हाथों को काम देने के लिए देश की स्थिति के अनुरूप उपयुक्त तकनीकी का विकास रचनात्मक प्रयोगों के माध्यम से किया जाये। वस्तुतः आज हमारा राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए "समग्र विकास के माध्यम से समग्रक्रान्ति"। अब यही मेरा जीवन व्रत रहेगा। मेरे इस रचनात्मक अभियान का आधार होगा देश की युवाशक्ति। विश्वास है कि इस रचनात्मक पथ पर बढ़ते समय मेरे समस्त सहयोगियों एवं देश के समस्त नागरिकों का शुभाशीर्वाद मुझे सतत् प्राप्त होता रहेगा।

दिनांक 20.4.78

—नानाजी देशमुख

हर तरह से हम एक अच्छी सरकार चला रहे हैं। सरकार ने मुद्रा, वित्त और प्रशासन के क्षेत्रों में अनेक कदम उठाये हैं जिससे पूंजी विनियोग को बढ़ावा मिला है। 1977 में कार्पोरेट क्षेत्र (निजी उद्योग) में बेमिसाल विनियोग हुआ है।

कृषि, ग्रामीण विकास, विकेंद्रित लघु उद्योग, गृह उद्योग तथा कुटीर उद्योगों आदि पर अत्यधिक जोर देने वाली सरकारी आर्थिक नीतियों का लाभदायक असर कुछ ही महीनों में महसूस किया जाने लगेगा। बिजली उत्पादन, सिंचाई, सीमेंट, भारी उद्योग आदि आधारभूत क्षेत्रों के विकास पर कारगर नजर रखी जा रही है जिससे कि इन क्षेत्रों में व्याप्त वर्षों पुराने अवरोध दूर होंगे और अर्थतंत्र तेजी से आगे बढ़ेगा—यदि सरकार द्वारा घोषित नीतियों एवं कार्यक्रमों का कारगर क्रियान्वयन हो और राज्य सरकारों द्वारा सम्यक् कार्य संपादन हो तो कोई कारण नहीं कि हम अगले 10 वर्षों में पूर्ण रोजगार न हासिल कर सकें···

शायद पहली बार ऐसा मंत्रिमंडल बना है जिसके खिलाफ़ भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद का कोई आरोप नहीं है···

शासन के इन सकारात्मक पक्षों के बावजूद पार्टी और सरकार की साख देश में और विदेश में घटती जा रही है। मुझे लगता है कि यदि हम इस क्षय को रोकने और अपनी साख को दुबारा कायम करने के लिए तत्काल कारगर कदम नहीं उठायेंगे तो जनता तथा देश दोनों के लिए विनाशक परिणाम होंगे···

सरकार के रूप में हम जनता के साथ संवाद कायम करने में सर्वथा विफल रहे हैं, हमारा जन संपर्क का प्रयास बेहद असंतोषजनक रहा है। और यह तब जब कि हजारों पत्रकार तथा लेखक पूछते रहते हैं कि क्या वे किसी तरह की मदद कर सकते हैं···चूक होने पर हमारे दुश्मन हमारा उपहास करने तथा हमारी आलोचना करने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे, पर उपहास का पात्र बनने के लिए हम जानबूझ कर ऐसे कार्य भला क्यों करें ?···

शासन में कार्य संपादन ही सब कुछ नहीं होता। प्रतीकात्मकता भी महत्त्वपूर्ण है, जनता को लगातार अनुभव होना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण के महान् यज्ञ में वे भी शामिल हैं, आज यह भावना नहीं है। वस्तुतः हमारे देश में यह शायद ही रही है···हमें आर्थिक और सामाजिक उपायों की एक पूरी शृंखला शुरू करनी होगी जो जनता को उत्साह से भर दे और उन के मन में सरकार के साथ तादात्म्य पैदा कर दे···इस हेतु निम्नलिखित कदम तत्काल उठाए जाने चाहिए।

1. उन सभी राज्यों में भूमि सुधार जहां ये सुधार नहीं किये गये हैं। उसी के साथ सभी ग्रामीण गृहविहीनों को रिहायशी जमीन प्रदान की जाये।

2. सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से कमजोर सभी वर्गों को और स्त्रियों के लिए रोजगार का आरक्षण किया जाये। हरिजनों और आदिवासियों के लिए मौजूदा आरक्षण समेत 65 प्रतिशत रोजगार आरक्षित होने चाहिए।

मेरे छः सूत्र

जार्ज फर्नाण्डीज

3. कुछ चुने हुए तथा मूल उद्योगों को सार्वजनिक स्वामित्व के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। इसी के साथ-साथ पारिवारिक समूहों द्वारा बड़े औद्योगिक घरानों के स्वामित्व का मौजूदा ढर्रा तोड़ कर आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण कम किया जाना चाहिए।

4. सभी क्षेत्र के मजदूरों के प्रतिनिधियों की एक मजदूर संसद बुलाई जाये जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचार करे तथा राष्ट्रीय निर्माण में मजदूरों की भूमिका निर्धारित करे।

5. **राष्ट्र पुनर्निर्माण सेना** बनायी जाये। यह संगठन राष्ट्रीय स्तर पर बने और सशस्त्र फौजों की तरह विभिन्न ब्रिगेडों से बांटा जाये। रा० पु० से० के स्वयंसेवकों को मासिक भत्ता दिया जायेगा, वे शिविरों में रहेंगे, खायेंगे और काम करेंगे, रेल तथा सड़क निर्माण, कुएं खोदना, सिंचाई, बांध बनाना, जंगल रोपना, गृहनिर्माण, सार्वजनिक निर्माण, साक्षर अभियान जैसे विशेष कार्य उन्हें सौंपे जायेंगे। तात्कालिक लक्ष्य रा० पु० से० के लिए दस से बीस लाख स्वयंसेवकों की भर्ती करनी चाहिए।

6. करोड़ों लोगों के लिए मकान बनाने का कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। उद्योग तथा सार्वजनिक सेवा में मजदूरों को, दस्तकारों, बुनकरों और अन्य आत्म-निर्भर मेहनतकशों को और भूमिहीन मजदूरों को, दस्तकारों, बुनकरों और अन्य आत्म-निर्भर मेहनतकशों को और भूमिहीन मजदूरों को घर दिलाने के स्पष्ट कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए।

जनता सरकार : पहले साल का हिसाब

□ प्रवाल मैत्र

किसी गरीब आदमी की अचानक लाटरी खुल जाने पर उसे कुछ दिन तक समझ में नहीं आता है कि उस पैसे का क्या करे और वह काफी पैसा अनाप शनाप खर्च कर देता है। पैसे की गर्मी उसे लापरवाह भी बना देती है।

जनता सरकार के पहले साल का हिसाब इस लाटरी पाने वाले आदमी जैसा ही है। मार्च 77 में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के अंतिम दिनों तक राजनीतिक पंडित यही मानते थे कि जनता पार्टी 'सबल विपक्ष' के नाते उभरेगी जनता पार्टी के नेता भी यही मानते थे और कइयों ने तो अपने चुनाव भाषणों में जनता से 'सबल विपक्ष' बनाने के लिये जनता पार्टी को वोट देने को कहा था। लेकिन दिल्ली के भाग्य छींका टूट गया। 5 मार्च, 77 को प्रधानमन्त्री श्री मोरार जी देसाई के नेतृत्व में केन्द्रीय जनता मंत्रिमण्डल सत्तारूढ़ हो गया।

शुरुआत के दिनों में आम जनता को यह अपेक्षा थी कि जनता सरकार पिछले 30 वर्ष से चले आ रहे ढर्रे में परिवर्तन लावेगी। उसने इस परिवर्तन की प्रक्रिया के लिये अपना मत तैयार भी कर लिया था। इसी समय एक छोटा लेकिन प्रभावशाली वर्ग चुप्पी साधे दहशत की भरी नजरों से परिवर्तन की प्रक्रिया की शुरुआत की इस घड़ी का इंतजार कर रहा था—उसे भय इस बात का था कि यथार्थतः परिवर्तन की प्रक्रिया में उसका अस्तित्व खतरे में पड़ने वाला था।

लेकिन इस छोटे, लेकिन प्रभावशाली वर्ग का भय निर्मूल साबित हुआ। नये सत्ताधीश यानी जनता सरकार 30 साल के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार आदि को समाप्त करने की बात जरूर करती थी लेकिन साथ ही उसकी 'लोकतांत्रिक प्रक्रिया' में 'अडिग आस्था' थी और इसलिये वह उस समय 'वर्तमान नियमों का उल्लंघन कर नहीं चल सकती थी।' जनता सरकार ने प्रारम्भिक 3-4 महीने वायदे करने में बिताये। लेकिन शायद धीरे-धीरे जनता सरकार 'व्यावहारिकता' समझने लगी और जहां शुरू-शुरू में सभी नेता 'संपूर्ण क्रांति' का राग पंचम स्वर में गाते थे—वहीं धीरे-धीरे वह 'पुरानी नीतियां ठीक थी—इंदिरा जी के कारण क्रियान्वयन नहीं हुआ' के कोमल 'स' पर उतर आये।

हां, सरकार का एक दावा जरूर है कि उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना की है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, प्रेस को आजादी दी है आदि-आदि। लेकिन इसका श्रेय जनता सरकार को नहीं है—उन करोड़ों सूझे इन्सानों को है जिन्होंने 16 मार्च से 20 मार्च के बीच चुपचाप वोट के हथियार का प्रयोग कर यह सब प्राप्त कर लिया था। 29 मार्च को जनता ने यह सभी पा लिया था—जनता सरकार ने 25 मार्च को सत्तारूढ़ होने के बाद 'पट्टा' भर लिख दिया है।

मंहगाई और बेरोजगारी की समस्याओं का कोई सार्थक समाधान अभी सामने नहीं आया है—और यही जनता सरकार की परीक्षा है और यहीं यह संदेह पैदा होता है कि पुरानी अर्थनीति के आधार पर ये समस्यायें कैसे हल होंगी? सच कहा जाय तो जनता सरकार अभी अपनी अर्थनीति नहीं तय कर सकी है—गांधीवाद का जप जरूर होता है लेकिन नेहरू माडल पीछा नहीं छोड़ता। ग्राम प्रधान अर्थ-व्यवस्था की बात सुनकर सिने सुने शहरी नाक भौं सिकोड़ने लगते है और सरकार फिर पुरानी राह पर चलने की बात करने लगती है। मजे की बात यह है कि वर्तमान बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने की कोई योजना तो अभी एक साल में सामने आयी नहीं, उसी के साथ बेरोजगारी की जनक शिक्षानीति पर भी किसी सही सोच के लक्षण नहीं दिखायी पड़े हैं।

व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन की बात को अगर अतिवादी कदम कह कर छोड़ दिया जाय तो भी तमाशा तो यह है कि जनता सरकार अब अपने बचाव के लिये कहती है कि नहीं हम अमुक नीति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं।

तो क्या यह मान लिया जाय कि यह सरकार 'केयर टेकर' के नाते काम कर रही है? इतनी जल्दी यह निष्कर्ष निकालना शायद गलत होगा क्योंकि

1. लोकसभा चुनाव (मार्च 77) के मात्र दो महीने पहले ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। इसलिये नीतियों को स्पष्टता से निर्धारित करने और प्राथमिकता तय करने का काम नहीं हुआ।

2. 'सबल विपक्ष' बनने को उत्सुक पार्टी 'सरकार' बन गयी।

3. जनता पार्टी में शामिल विभिन्न घटक दल और व्यक्ति वर्षों से राजनीति में थे—और उनकी अपनी-अपनी नीतियां और मानसिकता थी—एक दम अचानक परिवर्तन करना उनके लिये संभव नहीं हुआ।

4. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहस जरूरी है—इस तर्क का सहारा लेकर नयी नीतियों का क्रियान्वयन चालू नहीं किया गया।

5. पार्टी की अन्दरूनी राजनीति की भूमिका अगर छोड़ भी दें तो ये स्वयं में महत्वपूर्ण कारण हैं जिन्होंने जनता सरकार के पहले साल को 'दुविधा से गुजरने' का साल बता दिया है। लेकिन अभी भी दुविधा को इस बादल के हटने के आसार नजर नहीं आ रहे।

चन्दे की दर

राष्ट्रीय छात्र शक्ति की शुल्क दर निम्न प्रकार है जिसे भेजकर आप किसी भी महीने से सदस्य बन सकते है।

वार्षिक : 10 रुपये छमाही : 5 रुपये आजीवन 100 रुपये

शुल्क भेजने का पता

प्रबन्धक, राष्ट्रीय छात्र शक्ति,
बंगलो मार्ग, दिल्ली—7

Janta Administration in Delhi

SALIENT ACHIEVEMENTS

Rural Development

* Takavi distributed Rs. 1.45 crores
* Drinking Water Scheme Rs. 45 lakhs
* Tube-well connections 92 : to be installed soon 500.

Harijan Welfare

* Scholarships to Harijans Rs. 70.50 lakhs
* Housing subsidy to Harijans Rs. 24.50 lakhs
* Hostels for Harijan girls and boys students with board and lodging facilities.

Labour Welfare

* Restoration of Trade Union rights to workers
* Industrial Peace : More Production
* Quick disposal of complaints from the workers
* Recreational facilities ; setting of more Holiday Homes.

Education

* Technical Education training for 16,500 students
* Free uniforms and free books for all poor students
* Scholarships worth Rs. 57.73 lakhs
* Adult Literacy Centres being set up-1000.

Medical

* Two 500-bedded hospitals costing Rs. 22 crores at Shahdara and Hari Nagar
* Rs. 1 crore Modern Eye Hospital
* 7 Hospitals (100 bedded in rural areas) and 18 dispensaries.

Industry

* Licences to 24,000 industrial units in non-conforming areas
* Construction of Rs. 5.24 crores Tool Room-cum-Training Contre
* A 620 acre Industrial Township at Narela. Planned
* Community Development Centre-28 : employing 5600.

Housing

* Decision to constitute a Housing Board
* Construction of 1 lakh houses every year aimed
* Additional facilities and electricity connections in resettlement colonies.
* Total prohibition in four years : First phase started.

Issued by the Directorate of Information & Publicity, Delhi Administration

---

भेंट वार्ता

वार्ताकार □ महावीरदत्त गिरि

राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य केवल सत्ता नहीं कर सकती

—नानाजी देशमुख

पिछले अप्रैल महीने में एक पत्रकार सम्मेलन में दिये गये अपने बहुचर्चित वक्तव्य में श्री नानाजी देशमुख ने 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले नेताओं को सत्ता की राजनीति छोड़कर रचनात्मक कार्य करने की सलाह दी थी। इस सम्बन्ध में कई प्रश्नों की जिज्ञासा लेकर यह लेखक जब श्री देशमुख से मिला तो उनका कहना था, **"मैंने 60 वर्ष की बात स्वयं के लिए कही है।"** अपने जीवन का शेष समय नानाजी रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहते हैं। रचनात्मक कार्य में सत्ता की भूमिका के विषय में उनकी धारणा है कि आन्दोलनात्मक कार्यों में से आगे आने के कारण आज के ज्यादातर नेताओं को रचनात्मक कार्य करने का अवसर नहीं मिला था। **"सत्ता स्वयं रचनात्मक कार्य है पर रचनात्मक दृष्टि के अभाव में रचनात्मक कार्यों का क्रियान्वयन कठिन है।"**

नानाजी की इच्छा रचनात्मक कार्य के लिए एक व्यापक अभियान चलाने की है जिसका आधार युवा शक्ति होगी। आजादी के बाद देश के नवयुवकों के सामने एक नया सामान्य लक्ष्य नहीं रखा गया जिसके अभाव में राष्ट्रीय नवनिर्माण का कार्य अब तक जन सहयोग से वंचित है। इसलिए जनता पार्टी के महामन्त्री का स्पष्ट मत है, "राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य केवल सत्ता सफलता के साथ नहीं कर सकती।"

प्रश्न : आपने 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नेताओं को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर प्रवृत्त होने का आवाहन किया है। आपके विचार में ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें वे कर सकते हैं ?

उत्तर : मैंने 60 वर्ष की बात स्वयं के लिए कही है। कारण, मैं अपने जीवन का शेष समय रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहता हूं। रचनात्मक कार्य का अर्थ केवल इतना ही नहीं की दो-चार जगह गरीबों के मकान बनायें, कहीं सड़क बनायी जाये या कुछ जगहों पर कुछ कुटीर उद्योग खड़े कर हजार-पांच-सौ लोगों को रोजी दिलायी जाये। यह काम भी रचनात्मक है किन्तु रचनात्मक कार्य यहां ही इतने में ही समाप्त नहीं होता। वास्तव में देश में और विशेषतः राज नेताओं और युवाओं में रचनात्मक दृष्टि का विकास करने की आवश्यकता है जिसकी अभी तक उपेक्षा हुई है।

प्रश्न : क्या सत्ताधारी दल के लोग ऐसे कार्यों को सत्ता में रहते हुए अधिक प्रभावी ढंग से नहीं कर पायेंगे ?

उत्तर : सत्ता यह स्वयं रचनात्मक कार्य है। किसी भी मन्त्री का विभाग रचनात्मक कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य बात के लिए

है—ऐसी मेरी धारणा नहीं है। हरेक मन्त्रालय का कार्य पूर्णतः रचनात्मक है। किन्तु रचनात्मक दृष्टि के बिना रचनात्मक कार्यों का क्रियान्वयन कठिन है और यह दृष्टि रचनात्मक कार्यों के अभाव में विकसित नहीं हो सकती। इसलिए मेरा यह दृढ़ मत है कि देश की नई पीढ़ी को रचनात्मक कार्यों में संलग्न किया जाना चाहिए। वे ही आगे शासन का दायित्व संभालेंगे। और यह दायित्व सफलता के साथ निभाने के लिए रचनात्मक दृष्टि का विकास अनिवार्य है। अभी तक राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वाले ज्यादातर नेतागण आन्दोलनात्मक कार्यों में से आगे आये हैं। उन्हें रचनात्मक कार्यों को करने का अवसर नहीं मिला था, किन्तु भविष्य के लिए यह स्थिति मैं ठीक नहीं मानता।

प्रश्न : गांधीजी का रचनात्मक कार्य 'आजादी की लड़ाई' के सर्वमान्य लक्ष्य से जुड़ा हुआ था और इसलिए उसमें युवकों का व्यापक सहयोग मिला। आप ने अपने भावी रचनात्मक कार्य को किस सर्वमान्य लक्ष्य से जोड़ा है ?

उत्तर : गांधीजी का रचनात्मक कार्य आजादी के लिए होने वाली लड़ाई के साथ जुड़ा था। इसलिए नवयुवक बढ़-चढ़कर सहयोगी बनते थे यह बात सही है। किन्तु आजादी के बाद देश के नागरिकों के और विशेषतः नवयुवकों के सामने एक नया सामान्य लक्ष्य रखा जाना चाहिए था जिससे देश के सब नागरिक और विशेषतः युवक प्रेरित होते और अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक दायित्व के साथ राष्ट्रीय दायित्व को निभाने की स्पष्ट कल्पना उनके मस्तिष्क में जम जाती। इस सामान्य लक्ष्य के अभाव में राष्ट्रीय नव-निर्माण का कार्य जन सहयोग से वंचित बना हुआ है। राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य केवल सत्ता सफलता के साथ कर नहीं सकती। विशेषतः लोकतान्त्रिक शासन में।

प्रश्न : रचनात्मक कार्य कौन-कौन से हो सकते हैं और उसमें युवा पीढ़ी को किस रूप में साथ लिया जा सकता है ?

उत्तर : राष्ट्र के नवनिर्माण के जितने भी कार्य हैं वे सभी कार्य रचनात्मक कहे जा सकते हैं। रचनात्मक कार्य केवल आर्थिक विषय से ही सम्बन्धित नहीं रह सकते। सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्र भी रचनात्मक कार्य की परिधि में आते हैं। इन सब कार्यों में युवाओं का ही सर्वाधिक महत्त्व का स्थान है।

प्रश्न : रचनात्मक कार्यों के सम्बन्ध में ऐसे प्रयोग सर्वोदय से सम्बन्धित लोगों ने भी किये हैं और वे व्यापक मात्रा में युवा शक्ति को लगाने और दिशा देने में असफल रहे हैं। ऐसा क्यों ? इस परिणाम से बचने के लिए आप क्या सावधानी बरतेंगे ?

उत्तर : मैं सर्वोदय के सम्बन्ध में अधिक कह नहीं सकता। मेरा उन कार्यों से निकट का सम्पर्क कभी नहीं रहा। किन्तु यह कार्य दूर दृष्टि के साथ सातत्य से करने का है। ऐसे कार्यों में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। किन्तु सातत्य की भावना और एकाग्रता इन कार्यों को अन्ततोगत्वा सफलता प्राप्त करा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

प्रश्न : वर्तमान शिक्षा नीति के चलते क्या आपको लगता है कि केवल कुछ रचनात्मक प्रकल्प खड़े करने से बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जायगा ?

उत्तर : वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन रचनात्मक कार्य का ही एक अंग है। अतः वर्तमान शिक्षा बाधक हो सकती है, यह सोचना मैं आवश्यक नहीं मानता।

प्रश्न : शिक्षा पाठ्यक्रम से जुड़ी राष्ट्रीय सेवा योजना क्यों इस दिशा में सफल नहीं हो पा रही है ? आप उसे ही सफल क्यों नहीं बना रहे हैं ?

उत्तर : मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में जानकारी उन्हीं लोगों से करनी चाहिए जो इस कार्य में संलग्न हैं।

प्रश्न : क्या जनता पार्टी सरकारी स्तर पर कुछ रचनात्मक कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए सोच रही है ? आप सरकार स्तर पर रचनात्मक कार्यक्रम प्रारम्भ कराये जाने पर बल क्यों नहीं देते ?

उत्तर : सम्पूर्ण सरकारी कार्य को ही मैं रचनात्मक कार्य मानता हूं। यह दृष्टिकोण सरकारी कार्य में संलग्न सभी लोग अपनावें —इस दिशा में कार्य करना आवश्यक है और यह कार्य भी एक रचनात्मक कार्य ही है।

प्रश्न : डिग्री और रोजगार का जो संबंध बन गया है, क्या वह भी युवकों में व्याप्त हताशा का कारण नहीं है। इस कमी को दूर किए बिना युवा-असन्तोष कैसे कम होगा ?

उत्तर : डिग्री और रोजगार इनका पारस्परिक सम्बन्ध जो वर्तमान रूप में है उसे मैं उपयुक्त नहीं मानता। इस सम्पूर्ण व्यवस्था को समयानुकूल पुनर्रचना करना आवश्यक है। इसके लिए वातावरण निर्माण करना मैं अपना एक महत्त्वपूर्ण कार्य मानता हूं।

सत्ता यह स्वयं रचनात्मक कार्य है। किसी भी मन्त्री का विभाग रचनात्मक कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य बात के लिए है—ऐसी मेरी धारणा नहीं है। हरेक मन्त्रालय का काम पूर्णतः रचनात्मक है। किन्तु रचनात्मक दृष्टि के बिना रचनात्मक कार्यों का क्रियान्वयन कठिन है और यह रचनात्मक दृष्टि रचनात्मक कार्यों के अभाव में विकसित नहीं हो सकती।

अभी तक राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वाले ज्यादातर नेतागण आन्दोलनात्मक कार्यों में से आगे आये हैं। उन्हें रचनात्मक कार्यों को करने का अवसर नहीं मिला था, किन्तु भविष्य के लिए यह स्थिति मैं ठीक नहीं मानता।

प्रौढ़ शिक्षा : एक जनान्दोलन

प्रो० ओमप्रकाश कोहली
अध्यक्ष, शिक्षक संघ, दिल्ली विश्वविद्यालय

जनता सरकार ने शिक्षा क्षेत्र की प्राथमिकता में परिवर्तन करके निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देने का निश्चय किया है। निरक्षरता की चुनौती भरी समस्या पर दो दिशाओं से आक्रमण करने की नीति तय की गयी है। इनमें एक है, सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देना और दूसरा है प्रौढ़शिक्षा के लिए व्यापक जन-आन्दोलन चलाना। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए कुल शिक्षा-व्यय की लगभग आधी राशि निर्धारित की गयी है। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए योजना के प्रारूप में 100 करोड़ रुपए की राशि रखी गयी है, जो 1974-78 अवधि की राशि से लगभग तिगुनी है। प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सामूहिक आन्दोलन चलाने का संकल्प किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में 15-35 आयु वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों पर विशेष रूप से प्रयत्न केन्द्रित किए जाएंगे। सरकार ने 15-35 आयु वर्ग के 10 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को 5 वर्ष के भीतर साक्षर बनाने का महत्वाकांक्षापूर्ण लक्ष्य अपने सामने रखा है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए छठी योजना में 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं जो शिक्षा के कुल योजना परिव्यय का 10 प्रतिशत है। पांचवीं योजना में प्रौढ़ शिक्षा के लिए केवल 18 करोड़ रुपए की राशि रखी गयी थी जो कुल शिक्षा परिव्यय का लगभग 1 प्रतिशत थी। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय और उससे सम्बद्ध अभिकरणों के अलावा अन्य अनेक अभिकरणों से भी सहयोग मिल जाएगा और इन स्रोतों से भी प्रौढ़ शिक्षा पर राशि खर्च होगी योजना प्रारूप में निर्धारित 200 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त होगी।

निरक्षरता-उन्मूलन के संबंध में अब तक की प्रगति को ध्यान में रखें तो उपर्युक्त लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षापूर्ण प्रतीत होता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक साक्षरता 10 प्रतिशत से बढ़कर केवल 34 प्रतिशत की जा सकी है। निरक्षर लोगों की कुल संख्या में तो और भी वृद्धि हुई है। 1951 में 16·39 करोड़ निरक्षर थे, जबकि अब 22.65 करोड़ हैं। इनमें 15-35 आयु वर्ग के निरक्षरों की संख्या लगभग 10 करोड़ है।

प्रौढ़ शिक्षा के प्रयासों को गति देने और इन्हें जन आन्दोलन में ढालने के लिए सच्चा राष्ट्रीय संकल्प पहली शर्त है। केवल सरकारी संकल्प से काम नहीं चलेगा। सरकारी संकल्प के साथ आम जनता का संकल्प जुड़ने पर ही वांछित राष्ट्रीय संकल्प का निर्माण हो सकेगा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को यदि जन-आन्दोलन बनाना है तो इसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में सभी स्तरों पर प्रेरणा लगन और उत्साह उत्पन्न करना होगा। जन-आन्दोलन भावात्मक वातावरण में से आविर्भूत होता है और वहीं से पोषण पाता है। यद्यपि सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार और निरक्षरता उन्मूलन की महत्वाकांक्षापूर्ण योजना प्रस्तुत की है, लेकिन प्रधानमंत्री और शिक्षामंत्री के अनेक वक्तव्यों के बावजूद भी देश में अभी तक इस सम्बन्ध में भावात्मक वातावरण का निर्माण नहीं हो पाया है। **आवश्यक भावात्मक वातावरण के निर्माण के लिए देश के राजनैतिक नेतृत्व का प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करना काफी नहीं है; सामाजिक व सांस्कृतिक नेतृत्व को इस सम्बन्ध में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करके जन-मानस को प्रेरित करना होगा। राजनैतिक और सामाजिक नेतृत्व अपनी सच्ची प्रतिबद्धता का प्रमाण प्रस्तुत करके प्रौढ़ शिक्षा के विषय में व्याप्त गहरी उदासीनता को तोड़ सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है।** पिछले तीस वर्षों में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय उदासीनता का इससे बड़ा प्रमाण दूसरा क्या हो सकता है कि पहली योजना में प्रौढ़ शिक्षा के लिए कुल शिक्षा परिव्यय की केवल 3·3 प्रतिशत राशि रखी गयी थी जो बाद की योजनाओं में और भी कम हो गयी और पांचवीं योजना में तो केवल 1·4 प्रतिशत ही रह गयी।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए जन-अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह अभियान पूर्व योजना और सतर्क तैयारी के बिना न चलाया जाए। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा :

प्रौढ़ निरक्षरों को शिक्षा की सार्थकता और उपयोगिता की जीवन्त एवं तीव्र अनुभूति कराये बिना प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक शामिल करना सम्भव नहीं होगा। प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहन और बाध्यता दोनों का ही उपयोग करके शिक्षक जुटाने होंगे। बेरोजगार शिक्षित युवकों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लगाने से निरक्षरता और बेरोजगारी दोनों को हल करने में मदद मिलेगी। डिग्री प्राप्त करने के लिए ढाई-तीन महीने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लगाना प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

(1) शिक्षा पाने और शिक्षा देने वालों दोनों में ही रुचि और प्रेरणा जगाना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी राजनीतिक, सामाजिक और अन्य नेताओं को तथा सभी सरकारी विभागों को जुटना होगा। प्रौढ़ निरक्षरों को शिक्षा की सार्थकता और उपयोगिता की जीवन्त एवं तीव्र अनुभूति कराए बिना प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक शामिल करना सम्भव नहीं होगा। प्रेरणा जगाना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक प्रेरणा बनाए रखना है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की योजना स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सावधानी से बनाई जानी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा हो कि उससे निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाने के अलावा उनके व्यवसाय के सम्बन्ध में कुशलता प्रदान की जाए। यदि शिक्षा के परिणामस्वरूप प्रौढ़ निरक्षर की जीविका अर्जन की योग्यता और क्षमता में वृद्धि होगी, तभी उसे शिक्षा कार्यक्रम सार्थक प्रतीत होगा। अतः प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में साक्षरता और कौशल दोनों पर समुचित एवं सन्तुलित बल दिया जाना चाहिए।

प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहन और बाध्यता दोनों का ही उपयोग करके शिक्षक जुटाने होंगे; केवल प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं होगा।

(2) प्राप्त शिक्षा को नवसाक्षर प्रौढ़ भूलकर फिर से अनपढ़ न बन जाएं, बल्कि प्राप्त शिक्षा का उत्तरोत्तर विकास कर सकें, इसके लिए योजनाबद्ध अनुवर्ती कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा अभियान का अनिवार्य अंग होना चाहिए। निरक्षर को साक्षर बनाना जितना महत्त्वपूर्ण है, नवसाक्षर की साक्षरता को बनाए रखना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।

(3) प्रौढ़ शिक्षा का विराट कार्यक्रम केवल व्यावसायिक शिक्षकों पर निर्भर रहकर पूरा नहीं किया जा सकता। इस कार्यक्रम में शिक्षित वर्गों की सेवाओं का भरपूर उपयोग करना होगा। बेरोजगार शिक्षित युवक, सेकेन्डरी और विश्वविद्यालय स्तर के छात्र, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षक—शिक्षित समाज के इन तीन वर्गों का प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। बेरोजगार शिक्षित युवकों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लगाने से निरक्षरता और बेरोजगारी दोनों को दूर करने में मदद मिलेगी।

कालेज-विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र के लिए अपने शैक्षिक साल का एक सेमेस्टर प्रौढ़ शिक्षा के लिए लगाना आवश्यक होना चाहिए। ग्रीष्मावकाश का योजनाबद्ध तरीके से प्रौढ़ शिक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए 10-15 दिन के अल्पकालिक शिविर लगाने से विशेष लाभ नहीं होता। प्रत्येक छात्र-शिक्षक को कम से कम ढाई-तीन महीने लगातार प्रौढ़ शिक्षण का काम करना चाहिए, तभी उसके प्रयत्नों में गम्भीरता आ सकेगी। जब छात्र-शिक्षकों की एक टोली ढाई-तीन महीने तक एक प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र में काम कर चुके तो छात्र-शिक्षकों की दूसरी टोली पहली टोली के काम को अगले ढाई-तीन महीने तक अपने हाथ में ले। इस प्रकार पांच-छः महीने प्रतिदिन दो घंटे का शिक्षण देकर 300 से 350 घंटे का प्रौढ़ शिक्षण किया जा सकता है। डिग्री प्राप्त करने के लिए ढाई-तीन महीने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लगाना प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। एन० एस० एस० कार्यक्रमों को पुनर्गठित करके प्रौढ़-साक्षरता को प्रमुख और केन्द्रीय कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षण के कार्यक्रमों में छात्र रुचि और उत्साहपूर्वक तभी भाग लेंगे जबकि अध्यापक इस काम में उनके सहयोगी और सहकर्मी बनें। प्रत्येक अध्यापक के लिए अपने सामान्य शैक्षिक दायित्व के निर्वाह के अलावा कुछ समय प्रौढ़ शिक्षा के लिए निकालना आवश्यक होना चाहिए।

(4) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की सफलता में सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रयासों को एक दूसरे से तालमेल बैठाकर चलना होगा। केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर रहने से वांछनीय परिणाम नहीं निकल सकेंगे। प्रौढ़ शिक्षा की सफलता बहुत कुछ शिक्षकों के उत्साह और प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में और सरलता से प्रेरित किया जा सकता है। लेकिन आवश्यकता यह है कि स्वैच्छिक प्रयास असंगठित रूप में न चलें। विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों में तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यों का सरकारी कार्यों से तालमेल और समन्वय बैठना आवश्यक है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों को समन्वित करने के लिए तथा उनके प्रशासन और देखरेख के लिए कार्यकुशल संगठन नितांत आवश्यक है। कार्यक्रम में शामिल सभी सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों को इस संगठन के प्रति जवाबदेह होना होगा और यह संगठन प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकलापों का सतर्क मूल्यांकन करता रहेगा। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रभावकारिता सक्षम प्रशासन तन्त्र पर निर्भर होगी।

[शेष पृ० 32 पर]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक साक्षरता 10 प्रतिशत से बढ़कर केवल 34 प्रतिशत की जा सकी है। निरक्षर लोगों की कुल संख्या में तो और वृद्धि हुई है। 1951 में 17.39 करोड़ निरक्षर थे जबकि अब 22.65 करोड़ हैं। इनमें 15-35 आयुवर्ग के निरक्षरों की संख्या लगभग 10 करोड़ है।

छात्र-संसद

छात्र संघ आवश्यक है ?

छात्र-शक्ति : राष्ट्र-शक्ति

1977 की दूसरी आजादी के बाद संपूर्ण देश में छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति का पर्याय स्वीकार किया जा रहा है। इसलिए आज छात्र संघ पहले से भी अधिक महत्त्वपूर्णहो गया है। मेरे विचार से आजकल छात्र-संघ कुशल चालक का कामकरते हैं। क्योंकि छात्र-संघ के पदाधिकारी उन समस्याओं से पूर्ण रूपेण से परिचित होतेहैं जिनके कारण से छात्र समुदाय में आक्रोश होता है। छात्र समुदाय में धैर्य कम होता है तथा वे थोड़ी सी भी उत्तेजना मिलते ही हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। छात्रों को अनुशासित रखने में अध्यापक, पुलिस और सरकारी प्रशासक असफल रहे हैं। पर यह महत्त्वपूर्ण है कि यह छात्र-शक्ति छात्र-संघ के मंच से अनुशासित रहती है। छात्र-संघ के मंच में छात्रों की अटूट आस्था है। इस प्रकार छात्र संघ कई प्रकार के गम्भीर, राजनैतिक और हिंसामूलक समस्याओं के समाधान के लिए माध्यम बन सकते हैं, और छात्र शक्ति का समुचित उपयोग राष्ट्रहित में किया जा सकता है। अतः छात्र-संघ आवश्यक है, इसे किसी भी मूल्य पर कमजोर नहीं किया जा सकता।

अनिल कुमार 'मधुकर'
बी० काम० द्वितीय वर्ष
ज्ञानदेवी सलवान कालेज

छात्र-संघ लोकतंत्र का प्राथमिक स्कूल

अनेक लोगों में यह धारणा पायी जाती है छात्रसंघ राजनैतिक उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है पर यह ठीक नहीं है। यदि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए छात्रवर्ग छात्र संघ का निर्वाचन करता है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। यदि छात्रसंघ को 'राजनीति का शिकार' कहा जाएगा तो अन्य किसी भी संस्था को यही कहना पड़ेगा क्योंकि राजनीति केवल छात्र संघ पर नहीं बल्कि पूरे देश और हर संस्थाओं पर हावी है। विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर अनेक प्रकार से विद्यार्थियों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संघर्ष करना पड़ता है और छात्रसंघ इसका माध्यम बनता है। छात्रसंघ भविष्य के लिए छात्रों में सामाजिक चेतना पैदा करता है। वह लोकतंत्र का प्राथमिक स्कूल है। इसलिए उसका महत्त्व है और उसे किसी भी प्रकार कमजोर नहीं किया जा सकता।

अरुण कौशिक
बी० काम० तृतीय वर्ष
श्यामलाल कालेज

लोकतांत्रिक मूल्यों का परिचायक

मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु किसी भी संघ की उत्पत्ति स्वाभाविक है। मानव सभ्यता का घटक होने के नाते छात्रभी अपने अधिकारों एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का इच्छुक रहता है और इसी इच्छा के वशीभूत वह छात्र-संघों का निर्माण करता है। छात्र-संघ छात्रों की राजनैतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक तथा अन्य रुचियों को जागृत करते हैं, समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम इत्यादि के द्वारा कार्यक्रमों में उपस्थित प्रभावशाली व्यक्तित्व छात्रों की मानसिक चेतना कोजागरूक करते हैं तथा यह प्रभाव संभव रूप से छात्रों के चरित्र निर्माण व राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान देते हैं। छात्र-संघ संघर्ष के प्रतीक हैं। छात्र-संघ पदाधिकारी विद्यालय प्रशासन पर अंकुश रखते हैं। छात्र-संघों की गतिविधियों में संलग्नता छात्रों को दायित्व की भावना से अवगत कराती है। विशेषतया प्रजातान्त्रिक देश में छात्र-संघों का होना पूर्ण प्रजातन्त्र का परिचायक है। आदर्श छात्रसंघ की उत्पत्ति तभी संभव है जब इसके प्रतिनिधियों का संबंध आदर्श संगठन से हो।

कु० मधु शर्मा
बी० ए० तृतीय वर्ष
दौलत राम कालेज

कंचन जग्गी

प्रवीण जैन

राजकुमार शर्मा

विजय अग्रवाल

आयोजकीय

विभिन्न विश्वविद्यालय परिसरों में आज अराजकता व्याप्त है और विद्यार्थी समुदाय तनाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। प्रधान मंत्री ने छात्र असन्तोष के कारण विश्वविद्यालयों को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर देने की चेतावनी दी है। कुछ लोगों ने छात्र असन्तोष के लिए छात्र संघों को दोषी ठहराया है लेकिन दूसरा वर्ग इसे अस्वीकार करता है और उसकी धारणा है कि छात्र संघों के माध्यम से ही विश्वविद्यालयों में एक सन्तुलित एवं सामंजस्य-पूर्ण सम्बन्धों का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे में छात्र संघों की सार्थकता और उनका औचित्य विवाद का विषय बन रहा है। इस सम्बन्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के विचार प्रस्तुत हैं।

राज कुमार शर्मा

सामूहिक शक्ति का प्रतिनिधित्व

छात्र संघ एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से विद्यार्थी संगठित होकर अपनी समस्याओं पर विचार करते हैं। उदाहरण के लिए छात्र जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से उलझना पड़ता है जिसमें कालिज व विश्वविद्यालय प्रशासन में गैर-कानूनी संचालन, पुस्तकालय व छात्रावासों की कमी और सामाजिक यथार्थ से असम्बद्ध पाठ्यक्रम इत्यादि। यदि हम अपनी शिक्षा को व्यावहारिक व समसामयिक यथार्थ से सम्बद्ध चाहते हैं तो हमें इस पर सामूहिक रूप से विचार-विमर्श कर सरकार के उच्चाधिकारियों तक पहुंचना होगा और यह कार्य सिर्फ़ छात्र संघों के द्वारा ही सम्भव है। विद्यार्थी समुदाय के सभी अधिकारों की रक्षा छात्र संघ ही करने में समर्थ है चूंकि "अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता" यह सिद्धान्त प्रचलित है। कुछ दोषों के कारण छात्र संघ के महत्व को नकारना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। यदि दोषों को दूर कर दिया जाए तो छात्रसंघ अधिक प्रभावी मंच बन सकते हैं।

कु० कंचन जग्गी
बी० ए० तृतीय वर्ष
मिराडा हाउस,

छात्र संघ छात्र हितों दूर

आज के छात्र संघ एक सजी-सजायी दुल्हन की भांति वरमाला लिए हुए दृष्टिगोचर होते हैं। हम उल्लासपूर्वक, हर्षध्वनि से इसका स्वागत करते हैं परन्तु अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पर्दे की ओट में कुछ और ही प्रकट होता है। विषय को सामयिक सन्दर्भ में रखते हुए कहना पड़ेगा कि—"छात्र संघों की आवश्यकता आम छात्र के लिए प्रायः नगण्य ही है। यह उक्ति—"प्रत्यक्षं किं प्रमाणं" को पूर्णतया चरितार्थ करता है। छात्र-संघों का मूल कार्य छात्र अधिकारों की रक्षा करना है किन्तु इस रक्षा के ढोंग में—जो प्रदर्शन और नारों तक ही सीमित न रहकर हिंसा तक पहुंच जाती है और छात्रों के मूलभूत उद्देश्य शिक्षा को ही नकारता है। आज छात्र-संघों के चुनाव इतने खर्चीले व राजनीति से प्रेरित गलत मुद्दों पर आधारित होते हैं कि साधारण विद्यार्थी के लिए कल्पना करना सम्भव नहीं। छात्र-संघों के माध्यम से छिछली राजनीति शिक्षा क्षेत्र में घुस पैठ कर लेती है और छात्र हितों के साथ खिलवाड़ करती है। अन्त में छात्र संघ उस विष कन्या के समान है जिसके चुम्बन से शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों की मृत्यु सम्भव है। अतः वर्तमान में छात्र संघ अनावश्यक ही नहीं अपितु शिक्षा क्षेत्र के लिए घातक है।

प्रवीण जैन
बी० काम० (आनर्स) तृतीय वर्ष
राजधानी कॉलेज

संगठन में शक्ति है

छात्रसंघ का होना नितान्त आवश्यक है। जब मजदूर, व्यापारी और समाज के अन्य वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए संघ का निर्माण कर सकते हैं तो विद्यार्थी वर्ग पीछे क्यों रहे? वह भी अपने हितों की रक्षा के लिए छात्र-संघ का निर्माण करेगा। छात्र-शक्ति के हितों की रक्षा के लिए बनायी गयी संस्था का नाम छात्र-संघ है। उसमें कुछ दोष हो सकते हैं किन्तु चन्द साधारण दोषों को देखते हुए उसके सभी गुणों या लाभों को नजर-अन्दाज कर देना उचित नहीं है। यह सिद्धान्त मान्य है कि संगठन में शक्ति है। आज यदि किसी एक छात्र के सामने कोई समस्या आती है

अनिल कुमार 'मधुकर'

मुकेश कुमार

कु० मधु शर्मा

अरुण कौशिक

तो वह स्वयं अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकता। किन्तु वह छात्रसंघ का सहारा लेकर आसानी से अपनी समस्या को हल कर सकता है। कालेज के भीतर छात्र-छात्राओं की व्यवस्था सम्बन्धी अनेक कठिनाइयां होती हैं। परस्पर से बाहर भी समस्यायें होती हैं जिनके हल के लिए छात्र संघ ही उत्तम माध्यम होता है।

विजय कुमार अग्रवाल
बी० काम द्वितीय वर्ष
सत्यवती कालेज

सामाजिक समस्याओं से संघर्ष के केन्द्र

विद्यार्थियों को शिक्षा या अन्य क्षेत्र में उनके अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए छात्रसंघ आवश्यक है। छात्रसंघों से मेरा तात्पर्य केवल उन छात्र संघों से है जो आम विद्यार्थियों के मतदान द्वारा प्रजातान्त्रिक तरीके से चुने जाते हैं क्योंकि निर्वाचित छात्र प्रतिनिधि ही छात्रों की समस्याओं के समाधान और उनके अधिकारों को सुरक्षित रख सकने में सफल हो सकते हैं। छात्रसंघ शिक्षा संस्थाओं की समस्याओं के अतिरिक्त सामाजिक एवं आम नागरिकों की समस्या के लिए भी संघर्ष करता है। उसकी शक्ति का अनुमान करके आपात काल के दौरान तानाशाह सरकार ने छात्र-संघों में ताला लगा दिया था। पिछले लोक सभा के चुनाव में छात्रों की प्रबल भूमिका थी छात्र वर्ग देश का बौद्धिक वर्ग होता है। इसलिए वह छात्रसंघ के माध्यम से देश को नयी दिशा दे सकता है। सत्ता में आते ही जनता सरकार ने छात्रसंघों को बहाल किया—इसके लिए वह बधाई की पात्र है।

मुकेश कुमार
बी० ए० (आनर्स) द्वितीय वर्ष
रामजस कालेज

विद्यार्थियों में राजनैतिक चेतना का माध्यम

क्या छात्र संघों का होना आवश्यक है? वर्तमान परिस्थितियों में यह एक विवादास्पद है। छात्र संघ ही शिक्षा जगत में छात्रों का एक मात्र ऐसा मंच है जिससे छात्र अभिव्यक्ति को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। छात्र संघों के द्वारा ही विद्यार्थी समुदाय में राजनैतिक चेतना बनी रहती है। प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक को चाहिए कि वह राजनैतिक घटनाओं का तथा राजनैतिक शिक्षा का अध्ययन करे ताकि देश का सार्वजनिक जीवन पथ भ्रष्ट न होने पाये। चूंकि छात्र संघ के पदाधिकारी किसी न किसी विचार धारा से प्रभावित होते हैं। अतः जब वे उस विचारधारा के हित में कार्य करते हैं तो उनमें राजनैतिक चेतना रहती है। विद्यार्थी भविष्य के नागरिक होते हैं। अतः यदि प्रजातान्त्रिक पद्धति में जीने का पूर्वाभ्यास कराया जाये तो वे विद्यार्थी भविष्य में आदर्श नागरिक सिद्ध हो पायेंगे तथा प्रजातन्त्र सफल होगा। अतः विद्यार्थियों को छात्र संघ के माध्यम से प्रजातान्त्रिक प्रवृति का पूर्वाभ्यास कराया जा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन यदि कोई छात्र-हितों के विरुद्ध काम करता है तो छात्र संघ पदाधिकारी उसे रोकते हैं। अतः अपने रचनात्मक स्वरूप में छात्र संघ महत्त्वपूर्ण है।

अशोक अग्रवाल
दिल्ली विश्वविद्यालय

[पृ० 29 का शेष]

(5) प्रौढ़ शिक्षा के कार्य में जिन शिक्षकों को जुटाया जाए, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपने दायित्व का सम्यक् निर्वाह कर सकें।

चूंकि अपढ़ प्रौढ़ों में अधिकांश देहातों के तथा छोटे वर्गों और जातियों के हैं, इसलिए इनके शिक्षण के लिए आवश्यक नेतृत्व देहातों तथा छोटे वर्गों और जातियों में ही खोजा और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शहरों से शिक्षित लोगों को भेजकर ग्रामीण प्रौढ़ों को शिक्षा देने की नीति व्यावहारिक नहीं होगी।

(6) प्रौढ़ निरक्षरों के मोटे तौर से दो वर्ग हैं: असंगठित और अ-संस्थाबद्ध तथा संगठित और संस्थाबद्ध। इनमें संगठित और संस्थाबद्ध प्रौढ़ों को शिक्षा देना सरल है। जिन संस्थाओं में वे काम करते हैं, उन संस्थाओं को इन्हें साक्षर बनाने की तथा इनका कौशल स्तर उन्नत करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आवश्यकता होने पर इस कार्य के लिए कानूनी बाध्यता का उपयोग करने में सरकार को हिचकना नहीं चाहिए।

(7) यद्यपि सामूहिक साक्षरता का अभियान अधिकांशतः सभी शिक्षितों की स्वैच्छिक सेवाओं पर निर्भर होगा, लेकिन फिर भी इस दायित्व की मुख्य जिम्मेदारी शैक्षिक संस्थाओं को निभानी होगी। शैक्षिक संस्थाओं के लिए नियमपूर्वक प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं चलाना और अपने निकट के क्षेत्रों में निरक्षरता समाप्त करने का दायित्व स्वीकार करना होगा।

व्यापक निरक्षरता मिटाना प्रशासन-तन्त्र और शिक्षा-तन्त्र के अपने सामर्थ्य के बाहर है। इसके लिए जन-आंदोलन और वातावरण निर्माण आवश्यक है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है उत्कट राष्ट्रीय इच्छा। ✲

[पृ० 12 का शेष]

बिहार में वर्तमान छात्र-युवा गतिविधियों को समुचित दिशा देने के लिए आन्दोलन की बिखरी हुई अन्तर्धाराओं का विश्लेषण तथा उनकी समझ आवश्यक है। अन्यथा आन्दोलन मुख्यधारा से कटकर तात्कालिक आक्रोश की अभिव्यक्ति मात्र बनकर रह जाएगा या विभिन्न त्रुटियों एवं व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए समय-समय पर खड़े होने वाले प्रतिरोध निर्माण एवं रचनात्मक शक्तियों को कुंठित कर छात्र-युवा बहुतर एकता की सम्भावनाओं को नष्ट कर देंगे। **आज बिहार में एक सबल एवं दिशापूर्ण आन्दोलन के उभरने की प्रबल सम्भावना है। उस सम्भावना के वाहक तत्त्व तथा अन्य समर्थक तत्व भी वर्तमान है। जनता पार्टी के निर्माण एवं सत्तारूढ़ होने की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले बिहार आन्दोलन की वर्तमान शासन में भी उपेक्षित मांगें इसका आधार होंगी।** सम्पूर्ण क्रांति के दूरगामी लक्ष्य के प्रति समर्पित आन्दोलन के प्रारम्भिक अनुसंधानों को पूरा करने तथा उसके लिए आवश्यक संगठित शक्ति जुटाने के लिए आवश्यक ठोस एवं मौलिक आवश्यकताएं—महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा नीति में परिवर्तन तथा बेरोजगारी की समस्या—की पूर्ति भी नहीं हो पायी है। बिहार में खड़ा होने वाले किसी भी शक्तिशाली आन्दोलन का आधार ये ही मुद्दे होंगे जिनको छात्र-युवा ने बिहार आन्दोलन के माध्यम से उठाया हुआ है। बिहार आन्दोलन अभी भी जारी है।

परन्तु मार्च माह के प्रथम सप्ताह में उठने वाला प्रश्न अब दूसरा रूप धारण कर चुका है, अगर बिहार के छात्र-युवा वर्तमान आरक्षण विवाद की कटुता और वैमनस्य समाप्त करने में संलग्न हो जाय तो बिहार आन्दोलन की छूटी कड़ी पुनः पकड़ी जा सकती है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए युवा मानस को लम्बी और कठिन तैयारी करनी पड़ेगी।

✲

खेल अधिकारियों की राजनीति

□ राजेश सक्सेना

[पृ० 5 का शेष]

हुआ यही। मुख्यमन्त्री ने अपने भाषण में केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा 2 अप्रैल को जे० पी० की सलाह के अनुसार होनेवाले निर्णय के प्रति अपने को प्रतिबद्ध बताया और अप्रैल के बाद ही आरक्षण के प्रश्न को अंतिम रूप देने का निर्णय किया। परिणामत: रातोंरात फारवर्ड लीग द्वारा बैठकें होकर प्रात: समाचार पत्रों में प्रदर्शन के स्थगन होकर जनसभा का समाचार प्रकाशित हुआ। उसके बाद भी जो होना था वह हुआ।

31 मार्च को प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए। आठ नौ जिलों के लोग अधिक संख्या में थे। जातिवाद के आधार पर नेतृत्व की इच्छा वाले जनता विधायकों को उस समय गहरा तमाचा लगा जब भीड़ ने उनके प्रदर्शन स्थगन की सूचना को मानने से इंकार कर दिया। फलस्वरूप इन्हें नेतृत्व संभालते हुए राज्यपाल भवन की ओर जाना पड़ा। परिणाम वही हुआ जो होना था। जुलूस का रोका जाना, पुलिस द्वारा लाठी प्रहार, अश्रुगैस, नेताओं और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी, वक्तव्य, कांग्रेस, सी०पी०आई द्वारा स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश, 3 अप्रैल को बिहार बन्द न्यायिक जांच व सरकार के इस्तीफे की मांग उभरी।

जैसे आसार है उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों (आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी) के उग्र जातिवादी तत्व तथा सरकार में बदल लाने वाले राजनीतिक तत्व इस आंदोलन को जलाए रखेंगे। आरक्षण पक्ष के समर्थक उग्र तत्व आरक्षण के वर्तमान स्वरूप में और कोई भी संशोधन न हो और ऐसा होने पर आन्दोलन भड़काने की कोशिश करेंगे। आरक्षण के विरोधी तत्व आरक्षण को पूरी तरह निरस्त करने की मांग लेकर अड़े रहेंगे।

✲

खेल जगत के मानचित्र से भारत का नाम दिन-प्रतिदिन गायब होते देख हरेक खुले प्रेमी के दिल को कोफ्त होती है। क्या कारण है कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर का देश होते हुए भी हम अभी तक ओलम्पिक तथा विश्व खेलकूद आदि में हाकी तथा बिलियर्ड को छोड़कर एक भी पदक जीत पाने में असफल रहे हैं। यह नहीं कि भारत में ऐसे नवयुवकों की कमी है जो कि अपने देश का नाम ऊंचा करने में असफल हैं आज भी पंजाब तथा हरियाणा आदि में अनेक ऐसे युवक तथा युवतियां हैं जो कि शारीरिक तथा मानसिक रूप से परिपूर्ण हैं। आवश्यकता है ऐसे खेल अधिकारियों की जो कि ऐसे युवक युवतियों को ढूंढ निकाले तथा उन्हें पूर्ण रूप से प्रोत्साहन दे सकें ताकि वह देश की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा सके।

पर नहीं, भारत में खेल अधिकारियों को आपसी राजनीति से फुरसत कहां कि वह खिलाड़ियों की समस्याओं की ओर ध्यान दे सकें और उन्हें दूर कर सकें। खेल अधिकारियों का एक मात्र लक्ष्य यह है कि अपने पद पर अधिक से अधिक समय तक जमे रहें तथा प्राप्त सुविधाओं का उपभोग कर सकें। उदाहरण के तौर पर एक क्रिकेट टीम हाल में आस्ट्रेलिया आदि का दौरा करने गयी तो उसके साथ एक कोषाध्यक्ष भी गया जिसका कोई उपयोग नहीं था। कोषाध्यक्ष की बजाय यदि एक चिकित्सक साथ जाता तो अधिक उपयोगी साबित होता। आज खेल की टीमों में जो अनुशासन होना चाहिये उसकी भारी कमी है मैदान में उतरने से पहले एक नीति नहीं निर्धारित की जाती तथा परिणामस्वरूप जब टीमें मैदान पर उतरती हैं तो उनमें तालमेल का अभाव होता है।

खेल अधिकारियों का खिलाड़ियों के प्रति व्यवहार असहनीय होता है तथा वह खिलाड़ियों को अपनी जागीर समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही में आयोजित विश्वकप हाकी प्रतियोगिता के चयन कैम्प में एक चयनकर्ता की कथित अपमानजनक टिप्पणी से रुष्ट होकर तीन वरिष्ठ तथा अनुभवी खिलाड़ी चयन कैम्प छोड़कर चले गये थे। इसी प्रकार असलम शेर खान तथा गोविन्दा से हाकी संघ ने प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने को कहा पर दूसरे ही दिन मद्रास से हाकी संघ का आदेश आया कि इन दोनों को शिविर से वापिस भेज दिया जाये। खिलाड़ी का सम्मान तो दूर, यहां खिलाड़ी के स्वाभिमान को ठोकर मारकर न केवल एक दो बल्कि सभी खिलाड़ियों के स्वाभिमान तथा मनोबल को समाप्त कर दिया गया।

क्रीडा क्षेत्र में उन्नति के लिए यह परम आवश्यक है कि खिलाड़ी खेल के मैदान पर निडर तथा निश्चिन्त होकर खेलें। परन्तु आज खिलाड़ी जब खेल के मैदान पर होता है तो सोचता है कि यदि चोट लग गयी तो क्या होगा। खिलाड़ी का परिवार भी होता है तथा उसे भी अपने भविष्य की चिन्ता होती है। भूतपूर्व हाकी गोलकीपर चार्ल्स का उदाहरण सामने है। उसके घुटने तथा पैर बचाने के लिए कितने प्रयत्नों तथा कठिनाइयों से धन जुटाया गया। इस समस्या से बचने के लिए वर्तमान तथा भूतपूर्व खिलाड़ियों के कल्याण के लिए कोई कोष होना चाहिए तथा ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो उनकी योग्यतानुसार उन्हें कोई रोजगार दिलाने में मदद कर सकें। खिलाड़ियों के लिए बीमा योजनाएं होनी चाहिए ताकि यदि उसे खेल के मैदान पर चोट लग जाये तो उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े।

अंत में खेल जगत में हम अपनी प्रतिष्ठा तभी स्थापित कर सकते हैं जब बागडोर सही लोगों के हाथों में सौंपी जाये जो कि राजनीति से दूर हों तथा निजी स्वार्थों से दूर हों। साथ ही खिलाड़ियों, खेल संघोंतथा सरकार को मिलकर योजनाबद्ध तरीके से सद्भावना पूर्ण वातावरण में पूर्ण लगन तथा मेहनत से कार्य करना होगा।

✲

रपट

अरुण जेटली

22 मार्च 1978 की सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय में अचानक उपकुलपति कार्यालय पर तोड़-फोड़ और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पदाधिकारियों के विरुद्ध निलम्बन आदेश विश्वविद्यालय समाज के लिए असामान्य और अप्रत्याशित बात थी जिस पर एकाएक विश्वास नहीं हुआ। हालांकि बाद की घटनाओं और प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बात को साफ कर दिया यह किस सुनियोजित षडयन्त्र का परिणाम है? कौन इस घटना के लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार है? ये सवाल मुंह बाए खड़े हैं कि **आखिर कब तक आपातकाल की ज्यादतियों के जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन में रहकर छात्र प्रतिनिधियों को बदनाम करते रहेंगे? कब तक श्रीमती गांधी और उनके पुत्र के समर्थक विश्वविद्यालय अधिकारियों के संरक्षण में दूध पीकर जहर उगलते रहेंगे? क्या जनता सरकार मूकदर्शक बनी तमाशा देखती रहेगी? क्या विश्वविद्यालय से एमरजेन्सी खत्म नहीं होगी?**

विजय गोयल
विश्वविद्यालयी चौकड़ी के शिकार

दिल्ली विश्वविद्यालय में दोषी कौन?

इन्हीं सवालों की पृष्ठभूमि में दिल्ली विश्वविद्यालय की घटनाओं का जायजा लेना जरूरी है। 22 मार्च को लगभग 11 बजे चिलचिलाती धूप में विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल आफ इकनामिक्स से लगभग 150 छात्र-छात्राओं का एक जुलूस उपकुलपति के कार्यालय पर परीक्षाओं के स्थगन की मांग के लिए जा रहा था। छात्रसंघ भवन के नजदीक कुछ विद्यार्थियों के अनुरोध पर छात्र संघ अध्यक्ष विजय कुमार गोयल व रजत शर्मा ने भी इन लोगों के साथ चलना स्वीकार किया। जहां एक ओर परीक्षाओं के स्थगन के विषय में उपकुलपति द्वारा कई बार अस्पष्ट उत्तर दिए जाने के कारण छात्र प्रतिनिधियों के लिए छात्रों के इस समूह को निश्चित उत्तर दे पाना भी संभव नहीं था। वहीं दूसरी ओर इस जुलूस के तथाकथित नेता यह भी कहते सुने जा रहे थे कि छात्र-संघ के पदाधिकारी परीक्षाओं के स्थगन की मांग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बात का अन्दाजा लगाने का अवसर नहीं था कि ये लोग उन्हीं लोगों के प्रतिनिधि हैं जो वर्ष भर छात्र-संघ को बदनाम करने के लिये सस्ते हथकंडे अपनाते रहे हैं। छात्रसंघ के पदाधिकारी उस जुलूस में शामिल चंद लोगों के तोड़-फोड़ और हिंसा के सुनियोजित इरादे को भी भांप नहीं पाए। उपकुलपति के कार्यालय पर पहुंच कर छात्रसंघ अध्यक्ष छात्रों को इस विषय में अब तक हुई बातचीत के बारे में बता ही रहे थे कि तोड़-फोड़ के प्रयास शुरू हो गए। बाद में उपकुलपति ने बाहर आ कर जो वक्तव्य दिया उसमें एक बार फिर टालमटोल की बात और एक बार फिर से पूर्ण अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद शीशों की तोड़-फोड़ धक्का-मुक्की कुछ इस तरह हुई कि कुछ समय तक कुछ भी समझ पाना संभव नहीं था। श्रीमती गांधी के समर्थक देश भर में जारी हिंसा की नीति की छाप विश्वविद्यालय पर लगाने पर उतारू थे और अपने विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने के प्रति आश्वस्त। लगभग बीस मिनट बाद उपकुलपति फिर घटनास्थल पर उपस्थित हुए और खुफिया पुलिस और कर्मचारियों के घेरे के बीच अचानक गायब भी हो गए। यह बात ध्यान देने की है कि इस सारी घटना के दौरान उपकुलपति डा० मेहरोत्रा के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ न ही उन्होंने छात्र प्रतिनिधियों को दिए गए आरोप पत्र में इस प्रकार का कोई आरोप लगाया है परन्तु समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों के बदनाम करने के लिए उपकुलपति पर हमला किए जाने की बात खूब उछाले का प्रयास किया गया। आपात काल की ज्यादतियों से विश्वविद्यालय समाज का ध्यान हटाने का इससे अच्छा अवसर शायद उनके हाथ नहीं लगता और इसका भरपूर लाभ उठाने का प्रयास भी उन्होंने किया। विजय कुमार गोयल व रजत शर्मा सहित युवा जनता के सुधीर गोयल को निलंबित करके उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गये। केवल समाचार पत्रों में झूठे बयान दे देना शायद उपकुलपति को काफी नहीं लगा और अगले दिन देश भर के समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर इस बात को प्रचारित किया गया कि इन छात्रों को निलंबित करके इनके विरुद्ध जांच समिति की स्थापना की गई है।

इस सारी घटना को छात्रसंघ पदाधिकारियों के माथे मढ़ कर उपकुलपति और उनका विरोध क्या निकालना चाहता था ये बात बाद की घटनाओं से और भी जाहिर तौर पर सामने आ गई।

इसी दिन शाम को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरुण लेटलो पर शराब में धुत एक गुट ने हमला करने का प्रयास किया। विश्वविद्यालय छात्र-संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष उस समय दीन छात्र-कल्याण व एक कॉलेज के प्रिंसीपल के साथ सुबह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर चर्चा कर रहे थे तो वाइस-चांसलर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इन लोगों ने उन्हें भद्दी गालियां दीं और पीटने का प्रयास किया। पता नहीं कि डा० कुकला ने इस घटना की सूचना विश्वविद्यालय अधिकारियों को दी या नहीं लेकिन इतना अवश्य है कि विश्वविद्यालय ने इस बारे में चुप्पी साध लेना ही उचित समझा। अगले दिन की घटना ने सारे षड्यन्त्र का दिन दहाड़े पर्दाफाश कर दिया। 23 मार्च को सुबह जब छात्र-संघ के पदाधिकारी उपकुलपति के कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे तो छात्र-संघ भवन में वाइस-चांसलर और इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहां के अध्ययन कक्ष में पढ़ रहे छात्रों को एक गिरोह ने पीट कर बाहर निकाल दिया—शीशे और फर्नीचर को तोड़ा गया—अनेकों महत्वपूर्ण कागज निकाल कर फेंक दिए गए—इसकी लिखित सूचना उपकुलपति को दी गई और कोई कार्यवाही न होने पर प्रोत्साहन पाकर इन तत्वों ने छात्र-संघ भवन में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस को शिकायत की गई पर वह भी हाथ बांधे विश्वविद्यालय की संपत्ति को फुंकता देखती रही। बाद में फायर-ब्रिगेड को बुलाया गया। आज तक इस सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया है। विश्वविद्यालय समाज को अधिकारियों की इस खामोशी पर बहुत आश्चर्य भी नहीं हुआ है—यह वर्ष भर का अनुभव है कि यूथ-कांग्रेस के नेताओं को कुछ भी करने की खुली छूट है। यह बात अलग है कि चुनाव में उनके बुरी तरह पिटने को उपकुलपति रोक नहीं पाए। एमरजैन्सी के दो सालों में उनका बस चला था तो चुने हुए छात्र-संघों को समाप्त कर उनके प्रतिनिधियों को कारागार में भेज दिया गया था और इन्हीं संजय-समर्थकों को मनोनीत कर छात्रों पर उनके प्रतिनिधि के रूप में थोप दिया गया था।

तोड़-फोड़ की इन घटनाओं की पृष्ठभूमि और छात्र-संघ व विद्यार्थी परिषद् को बदनाम करने की विश्वविद्यालय की नीति कोई राज नहीं है। जिन तीन छात्रों के विरुद्ध निलंबन आदेश जारी किए गए हैं आपात काल में तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब विश्वविद्यालय को पुलिस चौकी में बदल कर उपकुलपति नसबंदी के कैम्पों का उद्घाटन कर रहे थे तो उनकी नजर में ये लोग देशद्रोही थे। शायद इसलिए कि उस खौफनाक वातावरण के बीच इन्हीं छात्रों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष की आवाज को बुलंद किया था। विश्वविद्यालय समाज काले शासन के समर्थक उपकुलपति के भुलावे में आकर यह विश्वास करने को तैयार नहीं है कि लोकतंत्र के प्रहरी ये छात्र-प्रतिनिधि एका-एक ही इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। इस बात पर अवश्य विश्वास किया जा सकता है कि पुलिस की घोर यातनाओं और जेल के सींखचों के भीतर तथा भूमिगत रह कर शांतिपूर्ण संघर्ष करने वाले लोग उपकुलपति की आंखों में खटकते रहे हैं और लगातार इनसे बदला लेने के अवसर ढूंढे जा रहे थे। 31 मार्च से उपकुलपति द्वारा बैठाई गई जांच समिति ने कार्य करना शुरू किया। छात्रों ने इस समिति के गठन को गैर-संवैधानिक ठहराते हुए मांग की कि विश्वविद्यालय की आचार संहिता के नियम 8 के आधार पर जांच-समिति में छात्रों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि उपकुलपति के विरुद्ध छात्र-संघ की शिकायतों पर प्रधानमन्त्री जांच कर रहे हैं इसलिए उपकुलपति द्वारा छात्र-संघ के पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच समिति की नियुक्ति न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। लेकिन जांच-समिति नेनाटकीय तरीके से आपत्तियों पर ध्यान न देते हुए काम करना शुरू कर दिया। इस तथाकथित कार्यवाही के दौरान जो तथ्य सामने आए वे बड़े रोचक है।

डीन छात्र-कल्याण डा० कुकला के बयान के अनुसार उन्हें एक दिन पहले ही पुलिस से सूचना प्राप्त थी कि खुफिया-रिपोर्ट के अनुसार 22 मार्च को उपकुलपति के कार्यालय पर हिंसात्मक प्रदर्शन होगा। सवाल ये है कि डीन महोदय ने इस सूचना की जानकारी उपकुलपति को क्यों नहीं दी? यदि दी—तो आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध क्यों नहीं किए गए?

डीन ऑफ कालेज श्री महेन्द्रसिंह से जब कहा गया तो उन्होंने अपने बयान में कुछ बाहरी तत्वों का उल्लेख किया है। इसके जवाब में कि उन्होंने इन लोगों को कैसे पहचाना कि ये ही बाहरी तत्व है तो उन्होंने बाहरी तत्व (आउट साइडर) शब्द की कई दार्शनिक परिभाषाएं दीं। पता चला है कि डीन साहब कुछ समय पहले अंग्रेजी के प्राध्यापक थे परन्तु 'आउट साइडर' शब्द का सही अर्थ जानते नहीं हैं।

मजे की बात ये है कि इस समिति के सामने जब इन अधिकारियों के बयान लिए जा रहे थे तो छात्रों को वहां उपस्थित नहीं रहने दिया गया और न ही बयानों के आधार पर कोई प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई।

विश्वविद्यालय की ओर से ग्यारह ऐसे लोगों की सूची दी गई थी जिन्हें इस घटना के दौरान चोट लगी बताया गया था। छात्रों ने अनुरोध किया कि इन सभी लोगों को जांच समिति के सामने बुलाया जाना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं उन्हें भी बुलाया जाए ताकि पता चले कि वास्तव में अपराधी कौन है?

11 अप्रैल को इस घटना में घायल सात कर्मचारियों ने अपने बयानों में कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष और सचिव ने न कोई हिंसा की न ही किसी प्रकार का दुर्व्यवहार! चार कर्मचारियों ने तो साफ-साफ शब्दों में कहा कि जब कुछ लोग उन्हें मार रहे थे तो विजय कुमार गोयल और रजत शर्मा ने आकर उन्हें बचाया।

इन बयानों के बाद जांच-समिति को लगा कि सच्चाई को छिपा पाना उनके लिए संभव नहीं रहेगा इसलिए शेष चार व्यक्तियों को बाद में आने के लिये कहा गया ताकि इस बीच योजना तैयार की जा सके। और संभवतः षड्यन्त्र को पूरा करने का कार्यक्रम इसी बीच तैयार कर लिया गया। अगले दिन निलंबित छात्रों के घर एक नोटिस भेजकर कहा गया

कि 'समिति' की कार्यवाही में सहयोग नहीं देना चाहते इसलिए इसकी कार्यवाही समाप्त की जाती है। बारह अप्रैल को अचानक नाटक समाप्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त करने के लिए जो पत्र छात्र देना चाहते थे उसे लेने से भी उपकुलपति और जांच-समिति के अध्यक्ष ने इंकार कर दिया।

क्या विश्वविद्यालय अधिकारी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि उनकी दृष्टि में कानून और न्याय क्या है ? विद्यार्थियों को बचाव का अवसर दिये बिना, प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी को नकार कर दिया गया। घटना में चोटग्रस्त एकमात्र प्राध्यापक श्री प्रभु चावला सहित अन्य अनेकों कर्मचारियों के बयान रिकार्ड नहीं किए गए और फिर मनमाने तरीके से कार्यवाही बन्द कर छात्रों को दोषी ठहराने का नाटक किया गया। संभवतः जांच-समिति को इस बात की स्वप्न में भी जानकारी नहीं थी कि उसके अध्यक्ष से की गई सारी बातचीत और तीन दिन की कार्यवाही निलंबित किये गये छात्रों ने टेप-रिकार्ड कर ली थी।

और बहुत से तथ्य प्रकाश में आ सकते है यदि तथाकथित 'जांच समिति' की रिपोर्ट को सामने लाया जाए जिसे छात्रों के बार-बार मांगने पर भी उपकुलपति ने नहीं दिया है। शायद तब विश्वविद्यालय को बताना पड़ेगा कि जांच-समिति के सामने विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अपने बयानों में जिन नामों का उल्लेख करते हुए सीधे मार-पीट करने का आरोप लगाया है उनके विरुद्ध कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया !

परीक्षाओं के बाद विश्वविद्यालय बन्द होने के कारण अभी तो सड़कों पर छात्र-शक्ति की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही पर कॉफी-हाउस का गरम वातावरण साफ बता रहा है कि विश्वविद्यालय के खुलते ही जुलाई में निष्कासन आदेश की वापिसी की मांग से लेकर उपकुलपति और उनके साथियों को हटाए जाने के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। सन 72-73 में भी उपकुलपति द्वारा तत्कालीन छात्र-संघ अध्यक्ष श्री राम खन्ना को निष्काकिए जाने पर विश्वविद्यालय लगभग तीन महीने बन्द रहा था। और अंत में डा० सरूप सिंह को झुक कर आदेश वापस लेने को बाध्य होना पड़ा था।

इस बार लगता है स्थिति और विकट हो सकती है। डा० आर०सी० महरोला सीधे तौर पर आपात काल में जुल्म ढाने के जिम्मेदार ठहराए गए हैं। इन्होंने केवल तानाशाही पूर्ण शासन का समर्थन ही नहीं किया था, बल्कि श्रद्धा से नतमस्तक होकर उसका गुणगान किया। उस समय की यूथ-कांग्रेस की नेता श्रीमती रुखसाना सुल्ताना के साथ जबरन नसबंदी कैंपों के उद्घाटन जैसे कार्य करके डा० मेहरोला विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को बेचने के दोषी हैं। अनेकों कांग्रेसी मंत्रियों के भाई भतीजों की गैर-कानूनी नियुक्तियों विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर सीधे प्रहार थीं जिसमें तत्कालीन शिक्षा मन्त्री डा० नूरुल हसन की नियुक्ति भी शामिल है। यहां तक कि उपकुलपति के गिरोह ने पुलिस अधिकारियों को विद्यार्थी परिषद व अन्य लोकतांत्रिक संगठनों से सम्बद्ध विद्यार्थी प्राध्यापकों की सूची देने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की।

इन ज्यादतियों की लंबी कहानी के नायक के प्रशासन में लगता है विश्वविद्यालय में अभी भी एमरजैन्सी जारी है। इंदिरा-समर्थकों को संरक्षण और चापलूसी की राजनीति का धुंआ वातावरण को दमघोंटू बनाए हुए है। वर्षभर कार्यक्रमों में हुल्लड़ और गुंडागर्दी मचाने वाले तत्व अपनी इस विजय पर आज भी जश्न मना रहे हैं और तानाशाही के के खिलाफ संघर्ष चलाने वाले आज अन्याय के शिकार हो रहे हैं। सरकार मूक दर्शन बनी शायद विश्वविद्यालय में एक और क्रांति की प्रतीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री ने आपात्काल की ज्यादतियों के विरुद्ध स्वयं जांच करने की घोषणा तो की थी पर अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आए हैं। इस पृष्ठभूमि में लगता है विश्वविद्यालय आने वाले वर्ष में निर्णायक दौर से गुजरेगा। विश्वविद्यालय समाज को विश्वविद्यालय से एमरजैन्सी हटने का बेताबी से इन्तजार है।

•••

प्रतिनिधियों की आवश्यकता

'राष्ट्रीय छात्र शक्ति' के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय और प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधियों की तुरन्त आवश्यकता है। लेखकीय प्रतिभावाले छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकों तथा पत्रकार युवकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता, वर्तमान कार्यक्षेत्र, अनुभव आदि का पूर्ण उल्लेख करते हुए लिखें—

प्रबन्ध सम्पादक
'राष्ट्रीय छात्र शक्ति'
३६, बंगलो मार्ग
दिल्ली—११०००७

Delhi Electric Supply Undertaking

[Municipal Corporation of Delhi]

SOME 'DOS' AND 'DONTS' FOR USERS OF ELECTRICITY

1. Dos' :

(i) Entrust the electrical installation, replacement addition or alteration work only to the Licensed wiring Contractors.

(ii) Use quality materials and standard house hold electric appliances.

(iii) Avoid overloading and limit your requirements to the extent of sanctioned load, otherwise get your excess requirments regularised.

(iv) Plug points and appliances should be suitably earthed.

2. 'Dont.s' :

(i) Temper with supply mains, meter equipments, earth wiring etc.

(ii) Allow children to touch the electricity mains with any metallic bars or rods, and to fly kites in the vicinity of the over-head supply mains. The use of metallic chords or wet threads is dangerous to life.

(iii) Use stay and supports of supply mains for drying clothes and tying cattles and pets.

(iv) Climb up the supply poles for any reason.

(v) Cut the house earthing wire as it is an essential safety measure.

(vi) Touch any bave electric wire.

(vii) Use unearthed appliances.

(viii) Use portable heaters and fans in the bath-room.

(ix) Use temporary wiring for extension of lights and fans etc.

(x) Remove the plug from an appliance or socket until it is switched off.

(xi) Allow switches or sockets to remain uncovered or broken

(xii) Clean any portable appliances or look for the cause of any defect therein without switching off.

(xiii) Touch the person involved in electric shock without switching off the main switch.

(xiii) Delay in rendering immediate medical aid to person who suffers from electric shock.

'Electricity, while a very obedient servant for convenience, is likely to prove very dangerous if not properly used.'

विज्ञापन और सिनेमा में नारी का इस्तेमाल

स्नेहलता रेड्डी

स्त्री अपनी परिस्थितियों के कारण यह मानती है कि वह सिर्फ पुरुष के उपभोग और तारीफ की वस्तु है। कोई अचरज की बात नहीं कि विज्ञापनों और सिनेमा में स्त्री का निर्दयता से शोषण किया जाता है। हमारे युग में स्त्री के बारे में गन्दे खयालों को छिपे तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। खासकर व्यापार और उद्योग की दुनिया में तो वह बहुत ज्यादा होता है। हम सिगरेट, मोटरकार और अन्य चीजों के विज्ञापन में सुन्दर और आकर्षक लड़कियों को देखते हैं। स्त्री को कल पुरजों, पैकेट, डिब्बे और विलास के समान की नौकरानी की हैसियत में पेश करना मनुष्य की काम-भावना को विकृत करना ही है।

अखबारों, इश्तहारों, रेडियो और सिनेमा में विज्ञापन के लिए स्त्री को जिस तरह पेश किया जाता है वह तो तमाम गन्दे साहित्य से भी ज्यादा बुरा है। अगर कामुक और गन्दे साहित्य पर से सब तरह की पाबन्दी हटा ली जाय तो देश को उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि इस तरह के विज्ञापन से होता है। इस तरह के विज्ञापन से उत्तेजना और हताशा की भावना पैदा होती है, जो आक्रामकता और पशुता को बढ़ावा देती है। स्त्री को नगण्य और तुच्छ बनाने के साथ-साथ इस तरह के विज्ञापन हममें सभी के लिए नुकसानदेह है। विज्ञापन ऐसी चीजें दिखाते हैं, जिनके हम मालिक होना चाहते हैं। विज्ञापन में रेफ्रीजेरेटर (खाने-पीने की चीजों को ठंडा रखने की मशीन) और प्रेशर कूकर (भाप के दबाव से रसोई बनाने का डिब्बा) के साथ स्त्री को दिखाया जाता है तो उससे इस खयाल को बढ़ावा मिलता है कि स्त्री भी एक ऐसी वस्तु है जिसको मालिक चाहिए। यही खयाल आगे बढ़कर मानता है कि स्त्री भी खरीद-फरोख्त की चीज है।

बात यहीं खत्म नहीं होती। आखिर स्त्री को विज्ञापन में कुछ खास-खास कामों के साथ जोड़ने या दिखाने का क्या मतलब है? यही तो कि वह केवल इन्हीं कामों के काबिल है। उसे रसोई बनाते, सिलाई करते, चीजें खरीदते ही दिखाया जाता है। हां, यह दिखाते हुए स्त्री को भोग की वस्तु के रूप में दिखलाने में कभी-कभी नहीं की जाती। रसोई बनाते, सिलाई करते हुए भी भोग की वस्तु के रूप में उसका प्रतीक बना रहता है। पुरुष के खर्च करने की क्षमता का उसे प्रतीक बनाया जाता है। इसके साथ वह खर्च करनेवाली भी है क्योंकि पुरुष उसके जरिये ही खर्च करता है। इस तरह उसे विज्ञापन की दुनिया में बिक्री का साधन बनाया जाता है। खपत के हर सर्वेक्षण से यह जाहिर हुआ है कि आकर्षक स्त्री का चित्र विज्ञापन का सबसे ज्यादा कारगर लटका होता है। वह जो कुछ भी करे उसका चित्र बिकता है। हमारी सभ्यता की यह 'स्त्री-पूजा' चहुं ओर है। व्यापार और उद्योग की दुनिया पुरुष की काम-भावना के छिपे तौर पर इस्तेमाल करने और उससे फायदा उठाने को तुली हुई है।

स्त्री और पुरुष दोनों आदमी हैं और उनसे आदमी के रूप में ही व्यवहार किया जाना चाहिए, लिंग भेद के आधार पर नहीं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि वे एक ही मानवता के अंग हैं, उनके मानवीय अनुभव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके शारीरिक फर्क पर जोर देना तो पाप है। यही नहीं, स्त्री और पुरुष को अलग-अलग भूमिकाएं प्रदान करना और मनमाने ढंग से दोनों में से किसी को मुख्य और किसी को गौण बताना भी अनुचित है। यह सही है कि बहुत-सी स्त्रियां अपने लिए गृहिणी या सेक्रेटरी (बड़े-बड़े दफ्तरों में सेक्रेटरी के पद पर स्त्रियों को ही नियुक्त किया जाता है) की परम्परागत भूमिका चुनेंगी लेकिन उन्हें इन्हीं भूमिकाओं में बांध देना गलत होगा। स्त्री को हर पेशे और व्यवसाय की विभिन्न भूमिकाओं में दिखाया जाना चाहिए।

किसी भी काम का आधार जिस (लिंग) नहीं होना चाहिए और हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि फलां काम स्त्री के स्त्रीत्व या पुरुष के पौरुष से मेल नहीं खाता। स्त्रियों और पुरुषों दोनों को ही विमानचालक, अन्तरिक्ष यात्री, इंजीनियर, मिस्त्री, कारीगर आदि की भूमिकाओं में दिखाया जाना चाहिए और इसी तरह पुरुषों को भी नर्स सेक्रेटरी और बच्चे की संभाल करने वाली भूमिकाओं में। घर के कामों में—रसोई बनाने, सफाई करने, बच्चों के पोतड़े बदलने—स्त्री और पुरुष दोनों को ही दिखाया जाना चाहिए। कभी-कभी यह भी दिखाया जा सकता है कि पुरुष तो खाना पका रहा है और स्त्री कूड़ेदान को बाहर ले जा रही है। भोजन के लिए पुरुष को स्त्री पर निर्भर नहीं बताया जाना चाहिए; न ही उसे घर के काम-काज के अनुपयुक्त और अपनी निजी देखभाल के मामले में लापरवाह या बेवकूफ जताना चाहिए। स्त्री का वर्णन पुरुष के साथी और साझीदार के रूप में होना चाहिए, उसकी मिल्कियत के रूप में नहीं।

हिन्दुस्तानी सिनेमा में तो स्त्री को कुछ खास किस्म की भूमिकाओं में ही दिखाया जाता है। मेरा खयाल है कि दुनिया में हिन्दुस्तानी सिनेमा ही एकमात्र सिनेमा है, जिसमें स्त्री की एक अत्यन्त स्नेह-वत्सल मां और पतिव्रता पत्नी की, जो अपना सब-कुछ त्याग करने को तत्पर हो, भूमिका के सिवाय और कोई भूमिका नहीं होती। हिन्दुस्तानी सिनेमा में स्त्री की भूमिका तय है। हां, हिन्दुस्तानी सिनेमा में स्नेह-वत्सल, मां और पतिव्रता पत्नी के ठीक उलट स्त्री की एक और भूमिका भी होती है। यह भूमिका रखैल, पुंश्चली, वेश्या और पश्चिमी फैशन की नकल करने वाली स्त्री की होती है, जो इतनी चंचल और भौंड़ी होती है कि एकदम अविश्वसनीय

लगती है। हिन्दुस्तानी सिनेमा में स्त्री को मनुष्य रहने नहीं दिया जाता, यहां तक कि उसे कभी हमारी समस्याओं के बारे में बुद्धिमत्ता के साथ बातचीत करते हुए भी दिखाया नहीं जाता। उसे मेज-कुरसी की तरह निर्जीव और यहां से वहां ले जाने वाली ऐसी चीज की तरह दिखाया जाता है, जिससे कमरे की शोभा बढ़ती हो। हिन्दुस्तानी सिनेमा में स्त्री देवी या दासी, अतिमानवी या भोग की वस्तु है। उसकी नकली भूमिका के तहत भी उसके आत्म-द्वन्द्व और उसकी चिन्ता व परेशानियों को कभी छुआ नहीं जाता। आज तक किसी फिल्म में स्त्री को एक व्यक्ति के रूप में सहानुभूति और समझदारी से नहीं दिखाया गया है। हाड़ मांस और आत्मा के एक जीवित व्यक्तित्व के रूप में स्त्री का अस्तित्व हिन्दुस्तानी सिनमा को अस्वीकार है। वह जीवन के सुख-दुख में पुरुष के साथ समान रूप से डटी हुई, उसके समकक्ष है, यह कभी हिन्दुस्तानी सिनेमा में अभिव्यक्त नहीं होता।

अगर मैं सीता या सावित्री पर नये ढंग से फिल्म बनाना चाहूं तो नहीं बना सकती। मुझे सेंसर बोर्ड तुरन्त रोक देगा क्योंकि वह यह मानता है कि धार्मिक कथाओं की नयी व्याख्या नहीं की जा सकती, उन्हें छुआ तक नहीं जा सकता। मुझे याद है कि मदरास में एक समय धार्मिक विषयों पर फिल्म बनाने के लिए हिन्दू धर्मादा बोर्ड (हिन्दू एन्डोमेंट बोर्ड) की इजाजत लेनी पड़ती थी। शायद यह नियम अभी भी चल रहा हो। सरकार हमें धर्म और जाति की बुराइयां और उनके अन्याय मिटाने को तो कहती है पर धर्म और जाति के अन्याय और अत्याचार को हर धार्मिक फिल्म में पुष्ट किया जाता है। आप इस अन्याय और अत्याचार का विरोध करने वाली फिल्म बना कर तो देखिये ! आप का क्या हाल होता है सेंसर बोर्ड आप पर टूट पड़ेगा और आपकी फिल्म धरी की धरी रह जायेगी। हमारे समाज में कथनी और करनी में भी ज्यादा बड़ी खाई मानने और कहने के बीच की है। सरकार मानती कुछ है और कहती कुछ और है। वह प्रगतिशील और लोकतंत्री होने का दावा करती है लेकिन उसके नामजद प्रतिनिधि रूढ़िवादी व्यवस्था को पूरी ताकत के साथ कायम रखना जरूरी मानते हैं। अगर सरकार का सचमुच में इरादा स्त्रियों की हालत सुधारना और उन्हें आजादी दिलाना है तो उसका यह कर्तव्य है कि वह ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दे, जो स्त्री को समाज में उसका पूरा दरजा प्राप्त करने में मदद दें, उसकी स्थिति का सही वर्णन करें। फिल्म वित्त निगम और अन्य संस्थाओं द्वारा तथा सेंसर नीति को प्रगतिशील बनाकर स्त्री फिल्म निर्माताओं को ढूंढना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र की मानसिकता पर उसकी पुरा कथाओं का जबरदस्त असर रहता है। व्यावसायिक सिनेमा निर्देशकों और निर्माताओं को इस बात का पूरा ज्ञान है और उन्होंने इससे बार-बार मुनाफा कमाया है। जब तक इन पुरा कथाओं की जकड़ को तोड़ा नहीं जाता तब तक सही मायने में प्रगति नहीं हो सकती; हमारे समाज में जो क्रूरता जम कर बैठ गयी है उसे हटाया नहीं जा सकता। सीता का ही उदाहरण लें। मैं उसके पुरुष के आधिपत्य को चुपचाप बरदाश्त करने और अपने सतीत्व की परीक्षा के लिए अग्नि परीक्षा को बिना विरोध के स्वीकार करने के बारे में शंका प्रकट करना चाहूंगी। क्या इस शंका को प्रकट करने वाली फिल्म बनायी जा सकती है ?

हमारे देश में स्त्री को घनघोर आर्थिक मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। गरीब परिवार की स्त्री को तो परिवार के कष्ट का लगभग सारा बोझ ही ढोना पड़ता है। हमारे साहित्य और सिनेमा में गरीब स्त्री के कष्ट और उसकी यातनाओं पर कितना ध्यान दिया जाता है ? कुछ हद तक मलयाली सिनेमा इस बारे में अपवाद है और इसका मुख्य कारण यह कि केरल में परम्परागत मातृ सत्तात्मक (ऐसा समाज जिसमें पिता के बजाय मां प्रधान हो) समाज के कारण स्त्री की समाज में हैसियत अपेक्षाकृत अच्छी है। खाती-पीती और धनी महिलाएं, जो स्त्री अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं; समाज में स्त्री की हैसियत में दिलचस्पी नहीं रखती और अगर रखती है तो एक हद तक ही। यह आशा की जा सकती थी कि कम से कम मशहूर फिल्म अभिनेत्रियां, जिन्होंने काफी रुपये कमाये हैं और इसके चलते जिन्होंने सामाजिक या आर्थिक ख्याति प्राप्त की है, स्त्रियों में चेतना फैलाने का काम करेंगी, लेकिन ये लोग तो फिल्मों में अभिनय करके ही संतुष्ट हो जाती हैं और फिल्में भी ऐसी कि जिनमें पुरुष जाति के मूल्यों का गुणगान किया जाता है। अगर कोई स्त्री कभी-कभार फिल्म बनाती है, जो घिसी-पिटी लकीर को और भी ज्यादा दुहराती है। सिनेमा के दर्शकों में स्त्रियों की संख्या बहुत बड़ी है। अगर वे अपने को संगठित करें और अपनी जरूरतों को समझें तो शायद ऐसी फिल्मों का बायकाट करें, जो स्त्री को अपमानित करती हैं और उसको गलत और नकली ढंग से पेश करती है। महिला संगठन फिल्म निर्माताओं को स्त्री को उसकी असलियत में पेश करने के लिए बाध्य कर हिन्दुस्तानी सिनेमा में क्रान्ति ला सकते हैं।

★

स्नेहलता रेड्डी—एक संवेदनशील अप्रतिम कलाकार, जो आपातकाल की क्रूरता और बर्बरता का शिकार हो गई। इमरजेंसी में २८ अप्रैल १९७६ को वह गिरफ्तार की गई और १५ जनवरी १९७७ को पुलिस की यातनाओं के बाद मरणासन्न अवस्था में उन्हें जेल से रिहा किया गया, ५ दिन बाद ही २० जनवरी को उनका निधन हो गया। फिल्म अभिनेत्री के नाते उनका एक विशिष्ट स्थान था, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण था सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उनकी भूमिका, उनका मानवीय पहलू। प्रस्तुत लेख स्नेहलता रेड्डी की अन्तिम रचना है।

कविता

न हो पीढ़ी यह बदनाम

लगता तुम्हें कठिन क्यों इतना,
इस राष्ट्र पुरातन की पुनर्रचना।
प्रिय इतिहास लिखे वह नाम,
ऐसा कर जाते कुछ काम ॥

अभिशापित है जीवन जिनका,
बन जाते तुम संबल उनका।
इस तरुणाई का सपना होता,
उनके जीवन का वरदान ॥

मरती सब, क्यों नहीं कहानी,
इतिहास लिखे, भर आंखों में पानी।
युग-युग में आंसू भर-भर कर,
जन-जन याद करें वह नाम ॥

परिणय का प्यारा अनुबन्ध,
माता का स्नेहिल सम्बन्ध।
वात्सल्य सने वे नाम,
कितना हो जाते शुभ नाम ॥

वह घायल एक सिपाही,
जो लगता कोई अपाहिज।
देता रुद्ध कण्ठ पैगाम,
विरासत उसकी लेते थाम ॥

कोई रामायण लिख दूंगा,
युग को शब्द रूप दे दूंगा।
इने-गिने परवानों में होगा,
जलता तेरा भी एक नाम ॥

आज, समय तुम्हें चुनौती देता,
हिम गिरि तेरी मनौती करता।
प्रश्न चिन्ह को दे दो उत्तर,
न हो, पीढ़ी बदनाम ॥

शब्द नहीं, उर की है आस,
गीत नहीं प्राणों की प्यास।
साथ नहीं देगा कोई तो,
हर दम साथ तेरा भगवान ॥

—रामजी गिरि

अगले अंक में

विशेष रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में छात्र अशांति

•

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थितियों का बेबाक विवेचन

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों का बोलबाला

•

लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और आगरा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र का अवलोकन

उत्तर प्रदेश के बीमार विश्वविद्यालय

•

कहानी एक भ्रष्ट वाइसचांसलर की

•

रैगिंग बन्द करो

•

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 30वें स्थापना दिवस पर विशेष लेख

नये संदर्भ : नयी चुनौतियां

"ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान"
प्रकल्प के राष्ट्रीय शिविर, जयपुर की रपट

तथा

अन्य सभी स्थायी स्तम्भ

राष्ट्रीय छात्र-शक्ति **जुलाई, 1978**

हलचल

हरियाणा के छात्रों का भ्रष्ट कुलपति के खिलाफ संघर्ष जारी

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलपति श्री हरद्वारी लाल को हटाये जाने एवं मेडिकल छात्रों पर हुए अत्याचार की निष्पक्ष जांच एवं उचित कार्यवाही की मांग पर जोर देने के लिए विद्यार्थियों का आन्दोलन लम्बे समय से चल रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार के अदूरदर्शी रवैये के कारण मामला अभी तक उलझा हुआ है।

छात्रों का आरोप है कि कुलपति श्री हरद्वारी लाल नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं। जातिवाद का नंगा नाच विश्वविद्यालय में हो रहा है, छात्रों को दो गुटों में बांटने के लिए गुण्डा तत्वों को कुलपति द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है।

विद्यार्थियों द्वारा बहिष्कार के बिना प्रचलित शिक्षा में बुनियादी बदल सम्भव

—आचार्य विनोबा भावे

आचार्य विनोबा भावे ने विचार व्यक्त किया है कि जब तक विद्यार्थियों द्वारा प्रचलित शिक्षा का बहिष्कार नहीं किया जायेगा, शिक्षा में बुनियादी बदल नहीं होगा। जब विद्यार्थी स्कूल-कालेज छोड़ देंगे तो शिक्षक भी बेकार हो जायेंगे और सरकार भी परिवर्तन के बारे में ईमानदारी, साहस एवं प्राथमिकता के साथ विचार करेगी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव श्री महेश शर्मा एवं पंजाब-हिमाचल-जम्मू-काश्मीर के संगठन मंत्री श्री आलोक कुमार के साथ हाल ही में पवनार आश्रम में एक भेंट में श्री विनोबा भावे ने यह मत व्यक्त किया है।

श्री महेश शर्मा ने उनसे पूछा था कि प्रचलित शिक्षा के प्रति किसी को भी श्रद्धा नहीं है लेकिन विद्यार्थियों से सभी की यह अपेक्षा है कि विद्यार्थी शान्त एवं अनुशासित रहें, ऐसा क्यों? बदलाव की आवश्यकता महसूस होने के बाद भी दिशाहीनता एवं यथास्थिति लगातार बनी हुई है तथा सरकार-समाज-शिक्षक-विद्यार्थी कोई भी जिम्मेदारी का परिचय नहीं दे रहा है तो परिवर्तन की प्रक्रिया की शुरूआत कहां से कैसे होगी?

विद्यार्थी परिषद से उनकी क्या अपेक्षा है, यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन को विद्यार्थियों में विज्ञान और अध्यात्म के प्रचार पर जोर देना चाहिए।

पटना में युवा उद्योजक शिविर का आयोजन

शिक्षित नवयुवकों को स्वयं रोजगार, हेतु प्रेरित करने तथा इस रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करने की दृष्टि से आगामी 12, 13, 14, 15 व 16 जुलाई को पटना में एक युवा उद्योजक शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार की ओर से आयोजित इस विशेष शिविर में बिहार के विभिन्न जिलों के लगभग 100 चुने हुए युवक भाग लेंगे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस नई दिशा में पिछले कुछ समय से प्रयास प्रारम्भ करके विद्यार्थी-संगठनों की रचनात्मक शक्ति को एक नया आयाम दिया है। पटना के इस शिविर से पूर्व पूना में महाराष्ट्र प्रदेश का एक शिविर 26, 27, 28, 29 जनवरी को हो चुका है।

इस शिविर की विभिन्न बैठकों में सरकारी एजेन्सियों के प्रतिनिधियों के साथ ही कई युवा उद्योगपति भी भाग लेंगे।

रांची के बिरला तकनीकी संस्थान के इन्जीनियरिंग स्नातक श्री भारत पुरे इस शिविर के संयोजक हैं। युवा उद्यमी श्री राजकुमार मोदी एवं श्री रामचन्द्र प्रसाद ने इस आयोजन को सफल बनाने का दायित्व अपने कंधों पर लिया हुआ है।

ग्राम-विकास अभियान में सहयोग हेतु कर्पूरी ठाकुर की अपील :

बिहार के मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी एवं अन्य छात्र-युवा संगठनों से अपील की है कि वे सरकार की समान्वित ग्रामीण विकास (Integrated Rural Development) की 305 ब्लाकों में लागू की जा रही योजना में सक्रिय एवं हर सम्भव सहयोग हेतु आगे आएं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो० बाल आप्टे महामंत्री श्री महेश शर्मा, केन्द्रीय संगठनमंत्री श्री मदन दास, क्षेत्रीय संगठनमंत्री श्री गोविन्दाचार्य तथा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री बृजेन्द्र झा एवं प्रदेशमंत्री श्री सुशील मोदी के साथ पटना में एक भेंट में श्री ठाकुर ने बताया कि विकास, उत्पादन एवं रोजगार की गति हम तेज कर सकें, तभी कुछ हो सकेगा। जे० पी० से कई बार, कम से कम आधा दर्जन बार मैंने आग्रह किया है कि इस काम के लिए छात्र-युवा संगठनों को एक साथ बुलाकर बात की जाए। उन्होंने दो बार कार्यक्रम भी बनाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इसलिए अब मैंने स्वयं ही बात करने का तय किया है।

उन्होंने कहा कि हमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ठोस जवाब की अपेक्षा है।

विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो० बाल आप्टे ने श्री ठाकुर को बताया कि सरकार के ऐसे कार्यक्रमों में पूरा सहयोग देने की हमारी नीति है। इसी दृष्टि से हम आपके आग्रह पर भी विचार करेंगे।

श्री आप्टे ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं का वातावरण इस प्रयास में बाधक है, प्रशासन को अपना रवैया बदलने की आवश्यकता है। नये वातावरण में पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता है।

श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि प्रशासन के रवैये से हमें भी परेशानी है। इस विषय पर हम भी चिन्तित हैं, लेकिन प्रशासन को सुधारने में अभी समय लगेगा। श्री ठाकुर ने विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व को यह विश्वास दिलाया कि भ्रष्टाचार से निपटने में हम सक्षम हैं और पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं।

बम्बई में ग्रीष्मकालीन श्रमानुभव शिविर

अखिल भारतीय विद्यार्थीपरिषद की बम्बई शाखा के तत्वावधान में 24 मई से 28 मई तक एक ग्रीष्मकालीन श्रमानुभव शिविर का आयोजन किया गया। शिविर बम्बई के निकट 'मनोहर' गांव में लगाया गया और इसमें बम्बई महानगर के साथ ही थाने के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कई अध्यापक भी शिविर में सम्मिलित हुए।

इस शिविर के अन्तर्गत क्षेत्र के वनवासियों के जीवन का सर्वेक्षण किया गया। समस्याओं के अध्ययन एवं अन्य सामाजिक-धार्मिक राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्य की चर्चा के साथ ही श्रम-कार्य भी किया गया। वनवासी क्षेत्र में जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत वार्तालाप भी हुआ। प्राध्यापक मोहन आप्टे ने अपनी हिमालय-यात्रा के संस्मरण भी सुनाए।

शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने व्यवस्था का पूरा भार स्वयं ही वहन किया।

वेकेशन एम्प्लायमेंट ब्यूरो, बरेली

छुट्टियों में विद्यार्थियों के लिए रोजगार हेतु विद्यार्थी परिषद की योजना

अखिल भारतीय विद्यार्थीपरिषद, बरेली की ओर से 'विद्यार्थी अवकाश-कालीन रोजगार केन्द्र' प्रकल्प की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है. विद्यार्थी परिषद के बरेली संभाग के संगठनमंत्री श्री श्रीनिवास ने बताया कि इस प्रकल्प के अन्तर्गत इस बार ग्रीष्मावकाश की अवधि में 50 विद्यार्थियों को एक से दो माह तक के लिए रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है।

विभिन्न उद्योगों की ओर से इस प्रकल्प में सहयोग किया जा रहा है। रहेलखण्ड एम्प्लायर्स आर्गनाइजेशन के अध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द सेठ, डा० ए० पी० सिंह एवं युवा उद्योगपति श्री विजय गोयल इस प्रशसनीय आयोजन में अधिक सहयोग कर रहे हैं।

अ० भा०वि०प० की राष्ट्रीय कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक 1,2 व 3 जून को जयपुर में होगी। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो० बाल आप्टे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष एवं मंत्री भी बैठक में आमंत्रित किए गये है।

विद्यार्थी परिषद के महासचिव श्री महेश शर्मा ने बताया है कि कार्यसमिति में देश और विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए आगामी कार्य-योजना पर निर्णय लिया जायेगा। छात्र आन्दोलन की दिशा, अन्य संगठनों के प्रति दृष्टिकोण एवं सम्बन्ध, केन्द्र एवं राज्य सरकारों की शिक्षा-नीति एवं कार्यक्रम, ग्राम-विकास एवं राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में छात्रशक्ति की रचनात्मक भूमिका पर विस्तार से विचार-विमर्श होगा।

कार्यकारिणी आगामी वर्ष में सदस्यता अभियान तथा अगले राष्ट्रीय अधिवेशन का स्थान एवं समय के बारे में भी निर्णय लेगी।

जे० पी० छात्र-युवा नेताओं की बैठक बुलायेंगे

छात्रशक्ति की रचनात्मक भूमिका एवं शैक्षणिक सुधारों पर चर्चा होगी

श्री जयप्रकाश नारायण ने शीघ्र ही छात्र-युवा नेताओं की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक बुलाने का निश्चय किया है। यह बैठक जून के अन्तिम सप्ताह अथवा जुलाई में पटना में होने की सम्भावना है।

जे० पी० से मिलने के उपरान्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो० बाल आप्टे ने बताया है कि इस बैठक में इमरजैन्सी के पूर्व के संघर्ष से जुड़े राष्ट्रीय छात्र-युवा संगठनों के प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालय छात्रसंघों के अध्यक्ष एवं महासचिव भाग लेंगे।

जे०पी० के साथ भेंट में प्रो० आप्टे ने इस बात पर जोर दिया था कि आन्दोलन से जुड़े हुए युवा संगठनों को सर्वमान्य मुद्दों पर मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। जे० पी० ने इस बात पर पूरी तरह सहमति व्यक्त की और इस दिशा में होने वाले प्रयास को अपना हर सहयोग एवं मार्गदर्शन देने की इच्छा व्यक्त की।

श्री आप्टे ने बताया कि जे० पी० के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस बैठक की तिथियां शीघ्र ही तय होंगी। बैठक में छात्रशक्ति की रचनात्मक भूमिका तथा शैक्षणिक सुधारों पर चर्चा होगी।

एस०एफ०आई० की केन्द्रीय कार्यसमिति

स्टूडेन्ट फेडरेशन आफ इण्डिया (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) की केन्द्रीय कार्यसमिति की बैठक जुलाई में उदयपुर में आहूत की गई है। संगठन के अध्यक्ष श्री प्रकाश कारत एवं महामंत्री श्री सुभाष चक्रवर्ती सहित 30 छात्रनेता देश भर से इस बैठक में सम्मिलित होंगे।

ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान प्रोजेक्ट का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विगत 2 अक्टूबर, सन् 1977 से पूरे देश में प्रारम्भ एक अभिनव प्रकल्प ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आगामी 4, 5, 6 व 7 जून, 1978 को जयपुर में आयोजित होगा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर इस शिविर का उद्घाटन करेंगे।

इस शिविर में विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों सहित लगभग 250 ऐसे कार्यकर्ता भाग लेंगे जो देश में विभिन्न केन्द्रों पर इस प्रकल्प के क्रियान्वयन में प्रमुख दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। पिछड़े क्षेत्रों में सेवा कार्य एवं नवनिर्माण में जुटे कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। योजना आयोग के सदस्य प्रो० राजकृष्ण, सुविख्यात श्रमिक-नेता श्री

दत्तोपन्त ठेंगड़ी, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के सेक्रेटरी श्री राधाकृष्ण बनवासी कल्याण केन्द्र के प्रमुख श्री रामभाऊ गोडबोले, भारत के शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम अधिकारी प्रो० एच०आर० शाह तथा राजस्थान हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल जैन भी शिविर में शामिल होंगे।

शिविर में गांवों, वनवासी क्षेत्रों, हरिजन बस्तियों एवं झुग्गी—झोंपड़ियों में सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक-स्वास्थ्य संबंधी स्थिति और विकास कार्यों में विद्यार्थियों के योगदान पर चर्चा होगी। अभी तक के कार्य एवं अनुभवों की समीक्षा करते हुए आगामी वर्षों की योजना तय होगी।

इस प्रकल्प के अन्तर्गत देश की युवा पीढ़ी में समाज के पिछड़े लोगों की स्थिति के प्रति समझदारी, जागरूकता एवं प्रतिबद्धता विकसित करने के लिए कुछ चुने हुए क्षेत्रों में सघन कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही देश की योजना, शिक्षा एवं जनमानस को ग्रामोन्मुखी बनाने के लिए सभी स्तरों पर वैचारिक अभियान चलाया जाएगा।

राजस्थान विश्वविद्यालय सीनेट व सिंडीकेट के चुनाव

विद्यार्थी परिषद को उल्लेखनीय सफलता

राजस्थान विश्वविद्यालय के सिंडीकेट एवं सीनेट के लिए हाल ही में सम्पन्न छात्र-प्रतिनिधियों के चुनाव में विद्यार्थी परिषद को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

सीनेट के लिए निर्वाचित दस छात्र प्रतिनिधियों में से छः स्थान विद्यार्थी परिषद, दो निर्दल, एक युवा जनता एवं एक वामपंथी मोर्चा को प्राप्त हुआ है। श्री लक्ष्मीनारायण डाह (भीलवाड़ा), श्री अमिताभ हीरावत (जयपुर), श्री भारतलाल शर्मा, श्री विनोद प्रकाश दीक्षित, श्री रवीन्द्र कुमार जैन एवं श्री नन्द किशोर शर्मा (सभी विद्यार्थी परिषद) श्री गजराजसिंह शक्तावत एवं मधुकर श्याम चतुर्वेदी (निर्दल) श्री राजेन्द्रसिंह राठौर (युवा जनता) एवं श्री मुनिदेव त्यागी (आर०डी० एस०एफ) सीनेट के लिए चुने गये हैं। राजस्थान वि०वि० की सीनेट में कुल सदस्य 114 हैं।

सिंडीकेट में 21 में 2 छात्र-प्रतिनिधि हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता श्री भरतलाल शर्मा (शोध छात्र, केमिस्ट्री) तथा निर्दलीय श्री मधुकर श्याम चतुर्वेदी सिंडीकेट के लिए चुन लिए गये हैं। कड़े संघर्ष में युवा जनता के श्री राजेन्द्रसिंह राठौर और वामपंथी मोर्चा के श्री मुनिदेव त्यागी पराजित हो गये। इमरजेन्सी के पूर्व 74-75 में भी विद्यार्थी परिषद के प्रमुख नेता श्री सुनील भार्गव सिंडीकेट के सदस्य रह चुके हैं।

जनता पार्टी के संगठकों में शीघ्र एकता की सम्भावनाएं धूमिल

युवा जनता और जनता युवा मोर्चा दोनों ही उत्सुक नहीं

जनता पार्टी से जुड़े हुए दोनों युवा संगठनों द्वारा परस्पर आरोपों एवं विलय की शर्तों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निकट भविष्य में एकता की सम्भावनाएं बहुत धूमिल है। पार्टी के हाई कमान की ओर से विशेष पहल ही इस स्थिति को बदलने में सफल हो सकती है, लेकिन पार्टी नेतृत्व की गम्भीर व्यस्तताओं एवं आन्तरिक कलह को देखते हुए यह कठिन है।

युवा जनता बनाम लायन्स क्लब

पिछले दिनों पार्टी हाई कमान द्वारा बुलाई गई एक बैठक का युवा जनता ने बहिष्कार कर दिया था। बाद में उसका एक प्रतिनिधिमण्डल पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर से मिलने गया तो उनके रवैये को श्री चन्द्रशेखर ने काफी फटकारा। युवा जनता द्वारा शर्तों के साथ पार्टी का समर्थन किये जाने की बात पर श्री चन्द्रशेखर ने कहा था कि ऐसे समर्थन को हम महत्व नहीं देते। लायन्स क्लब भी जनता पार्टी का समर्थन करता है।

युवा जनता के नेतृत्व का यह मत रहा है कि वे कई छात्र-युवा संगठनों के विलय होने पर बने हैं और जनता युवा मोर्चा ने अपना अस्तित्व जानबूझकर अलग रखा है। वे यह भी चाहते हैं। कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी पार्टी के युवा संगठन में शामिल होना चाहिए।

जनता युवा मोर्चा के नेताओं को लगता है कि भूतपूर्व सोशलिस्टों ने 1 मई 77 को पार्टी बनने के भी पूर्व ही अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए जल्दबाजी में 'युवा जनता' बना डाला। उनका यह भी कहना है कि इसमें ऐसे लोगों की भरमार हो गई है जिनका जे० पी० आन्दोलन और इमरजेन्सी के विरुद्ध संघर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं था। भूतपूर्व कांग्रेसी और गुण्डा तत्वों ने जनता पार्टी में घुसने के लिए युवा जनता का द्वार चुन लिया है। पिछले लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ने वालों को युवा जनता में सम्मानजनक स्थान है। अपनी ही सरकारों के विरुद्ध वातावरण बनाकर युवा जनता इन्दिरा कांग्रेस को मदद कर रही है। मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में युवा जनता की भूमिका पर जनता युवा मोर्चा को गम्भीर आपत्ति है।

जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय सम्मेलन

जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन अगस्त के अन्तिम सप्ताह में पूना में होगा जिसमें देश के सभी भागों से कई हजार प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह निर्णय मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की गत 13 मई को नई दिल्ली में सम्पन्न बैठक में लिया गया है।

जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० सुब्रमण्यम स्वामी एम० पी० के अनुसार मोर्चा की सदस्यता 2,40000 हो गयी है। मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने सभी प्रदेश इकाइयों को निर्देश दिया है कि जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटें।

••••••

With

Best

Compliments

From

Krishna Engineering Works

PRE EMINANT FOR GEARS & PINIONS

8712, ROSHANARA ROAD

DELHI-7

Phone : H.O. 51-5068 51-6680
Unit 2 : 59-1856 59-0422
Unit 3 : 74-2146

दिल्ली नगर निगम

जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान

लिक भवन, नई दिल्ली

जल के बिना जीवन असम्भव है। दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान एशिया भर के विशाल एवं नवीनतम संयंत्रों द्वारा शुद्ध किए जल से आपकी सेवा कर रहा है।

अधिक अच्छी तथा व्यवस्थित जल प्रदाय सेवा के लिए कृपया निम्न प्रकार आपका सहयोग अपेक्षित है :—

1. नल की टूटी ठीक से बन्द करें।
2. आवश्यकतानुसार ही पीने के पानी का प्रयोग करें।
3. टपकते नल की टूटी और वाशर की जाँच करायें तथा खराब टूटी या वाशर को तुरन्त बदलवा दें। सिस्टर्न व ऊपर की टंकियों के रिसाव को भी तुरन्त ठीक करायें।
4. टूटियाँ बढ़ाने के लिए विभागीय स्वीकृति लें और लाइसेंस शुदा प्लम्बर से भवन के अन्दर के पीने के पानी की फिटिंग करायें।
5. भवन में ऊपर की मंजिलों पर पानी पहुँचाने के लिए तल मंजिल पर टंकी बनायें और उस पर बुस्टर पम्प लगायें।
6. पानी की लाइन राष्ट्रीय सम्पत्ति है। इनकी अपनी वस्तु की तरह ही देखभाल करें।
7. अपने भवन में आवश्यकता के अनुरूप ही पानी का भण्डार रखें।
8. कम दबाव की स्थिति में अपनी फिटिंग की जाँच करायें और आवश्यकता हो तो पुरानी फिटिंग बदलवा दें।
9. पानी की मुख्य पाइप लाइन रिसने या फटने की दशा में तुरन्त दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में जल विभाग को अथवा दूरभाष संख्या 617672 या 222491 पर सूचित करें।

दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान के समस्त कर्मचारी आपकी सेवा के लिए सदैव प्रस्तुत हैं।

(जन सम्पर्क अधिकारी दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा प्रसारित)

SHRIRAM
SBP

The Symbol of Quality

Shriram Stable Bleaching Powder is manufactured in a most modern Plant under strict raw material and process control procedures. It is guaranteed to contain minimum 35% available chlorine. In fact, Shriram SBP is the only stable bleaching powder with this maximum amount of available chlorine.

SPECIAL CHARACTERISTICS

- Shriram SBP is a pure white, free flowing powder without hard lumps or impurities.
- Provides maximum advantage at minimum cost to various industries, such as Textile, Silicate, Paper, Metallurgy, Sugar, Leather and many more.
- It is tropicalised and highly stable.
- Ideal for water purification and economical environmental sanitation too.
- Freely available throughout the country.

No wonder, because of its quality, Shriram SBP has earned for itself a big export market.

For your requirements contact your nearest dealer, or write to us at :

Trade Enquiries to :

D.C.M. CHEMICAL WORKS

Chemicals Marketing Department, Kanchenjunga Building,
18, Barakhamba Road, New Delhi-110 001

DCM-43

रचनात्मकता की बजाय विध्वंस को प्राथमिकता क्यों?

★ राष्ट्र प्रकाश

देश में दूसरी आजादी ने एक परिवर्तन को जन्म दिया है—वह है सत्ता परिवर्तन। लेकिन यह सभी समस्याओं का निदान नहीं है। इसके आगे की कई प्रक्रियाएँ हैं, जिनके आधार पर वास्तविक परिवर्तन होगा। पहले सत्ता परिवर्तन की समाज परिवर्तन—यह एक साइकिल की तरह घूमने वाली प्रक्रिया है—एक के साथ दूसरा भी गतिमान हो—ऐसा नजर आना चाहिए। आपात स्थिति में समाचारपत्रों पर पाबन्दी थी—अर्थात कोई भी समाचार तब तक नहीं छप सकता था जब तक कि वह सैन्सर न हो जाए। इसका नुकसान यह था कि देश में चल रही गतिविधियों की तनिक भी जानकारी जन-मानस तक नहीं पहुँच पाती थी। आज आजादी है। अखबारों से सैन्सर समाप्त हो चुका है। अब अखबार वाले कुछ भी छाप सकते हैं। कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन इसके कारण जो समस्या सामने आ रही है और जिन बातों को तूल दिया जा रहा है उससे परिवर्तन की प्रक्रिया में बाधा आती है। पिछले दिनों अखबारों में राजस्थान के खेतड़ी नामक प्रकरण की काफी जोरों से चर्चा रही। देश की संसद तक इसकी गूंज पहुंची। अखबारों में सैकड़ों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की बातें छापी गयीं जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। कई प्रतिनिधि मंडलों को खेतड़ी जाना पड़ा। जानकारी एकत्र की गई और यही बात सामने आयी कि समाचारपत्र में जिस रूप में विषय को छापा और उभारा गया है—वह गलत था।

पिछले दिनों जनता पार्टी के महासचिव श्री नानाजी देशमुख ने एक प्रैस वक्तव्य दिया जिसकी अभी तक जोरों से चर्चा चल रही है। "साठ वर्ष से ऊपर आयु के राजनीतिज्ञों को सत्ता की राजनीति से हटकर रचनात्मक काम में लग जाना चाहिए।" मुझे नानाजी देशमुख के मूल वक्तव्य को पढ़ने का अवसर मिला है जिसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि जो बात उन्होंने उठायी है—उसका जिक्र बिल्कुल नहीं हो रहा है बल्कि साठ साल की आयु के बाद राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए और इसका अर्थ श्री मोरारजी भाई, श्री चरणसिंह तथा जगजीवन राम को इस्तीफा देना चाहिए इस रूप में सामने लाया जा रहा है। जबकि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि युवकों में जो आज अनुशासनहीनता व असंतोष दिखाई दे रहा है उसका कारण यह है कि उनके सामने कोई आदर्श नहीं रक्खा गया है। कुछ लोगों के द्वारा, जो कि समय-समय पर समाज को दिशा प्रवाहित करने का काम भी करते हैं, कोई ठोस कार्यक्रम युवकों के सामने नहीं रखा गया है। और इसलिए वह युवा-पीढ़ी जिसने सत्ता परिवर्तन के कार्य में बहुत सहायता प्रदान की और सत्ता परिवर्तन का माध्यम बनी, आज निराश है। क्योंकि उनकी शक्ति, जिसका उपयोग रचनात्मक कार्य में हो सकता है, विध्वंस की ओर जाती हुई नजर आ रही है। इन सब बातों के स्थान पर अखबार में केवल साठ वर्ष की बात को तूल दिया गया है जिसके कारण नानाजी देशमुख द्वारा कही गई बात ने अखबार वालों के कारण एक नया मोड़ ग्रहण कर लिया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के विषय में भी समाचारपत्र वालों की जो भूमिका सामने आयी उससे पर्याप्त रोष पैदा होता है। अखबार वालों के कारण प्राथमिकता इस बात को मिलती रही है कि किस कालेज में बसें रोकी गई हैं। यदि आज किसी कालेज में 10 बसें रुकी हैं तो उससे अगले दिन के अखबार में 15 बसें वहां रोक दी गईं—इस प्रकार के वर्णन पढ़ने को मिलते रहे हैं। बसें रुकी हुई हैं, उसका फोटो अखबार के प्रथम व मुख पृष्ठ पर छपा हुआ है। इस प्रकार की भूमिका के साथ समाचार पढ़ने को मिलते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अखबार वालों की इस भूमिका के कारण ही सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए छात्र नेता बसें रोकने में अगवानी करते हैं। यदि आज किसी एक कालेज के बारे में समाचार छपा है कि उसमें 15 बसें रोकी गई हैं तो उसके साथ ही उस कालेज के छात्र नेताओं के वक्तव्य भी छपते हैं। इसने एक होड़ को जन्म दिया है कि अगले दिन कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि पुरानी बसें रोकने का रिकार्ड भी तोड़ा जाए, अपनी फोटो भी अखबार में आ सके और साथ में वक्तव्य भी छपें। अखबार वाले यदि इस प्रकार के विषयों को तूल न देते और केवल कैजवल रूप में इन समाचारों को छापते तो मैं समझता हूँ कि बसें अधिक नहीं रोकी जातीं। इनके स्थान पर प्राथमिकता उन विषयों को मिलनी चाहिए जो विद्यार्थियों में अच्छी तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। विश्वविद्यालय में जो ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनको अखबार में स्थान मिलना चाहिए। केवल बड़े-बड़े नेताओं वाले कार्यक्रम के समाचार ही अखबारों में नहीं छपने चाहिए। अभी हाल तक जो रवैया चल रहा है उसका अनुभव तो यह कहता है कि अखबार में यदि प्रैस विज्ञप्ति भी भेजी जाए तो अधिकतर उसी को स्थान मिलता है जिसमें कोई आन्दोलन, हड़ताल, भूख-हड़ताल, घेराव, घेराव आदि की बात होती है। यदि कोई कार्यक्रम होता है तो उसको छापने के लिए शायद अखबार वालों के पास स्थान नहीं होता है।

इस प्रकार के रवैये के चलते हुए, छात्र रचनात्मक कार्य में जुट जाएंगे, इस पर मन के एक कोने में शंका पैदा होती है क्योंकि यदि फोटोबाजी और माल्यार्पण ही होता रहा तो रचनात्मक कार्य होना कठिन है।

शिक्षा के साथ देश का भविष्य जुड़ा है। आज तक मिल रही शिक्षा की पद्धति दोषपूर्ण है। इसके माध्यम से परिवर्तन लाना संभव नहीं है। ऐसा सामने आ चुका है। शिक्षा सम्मेलनों आदि में शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बोल चुके हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति सड़ी-गली है। मैकाल

ने उस समय की आवश्यकता के अनुसार क्लर्क पैदा करने के लिए इस शिक्षा पद्धति का निर्माण किया था और इसलिए आज तक यह शिक्षा पद्धति वही क्लर्क पैदा कर रही है. विश्वविद्यालय से निकलकर स्नातक क्लर्क की नौकरी करना चाहता है क्योंकि हाथ का काम करने का स्नेह व गर्व उसमें पैदा नहीं किया गया है। आज जबकि 10+2+3 की पद्धति भी ठीक से काम नहीं कर रही है, नयी पद्धति में 8+4+3 की बात शुरू की जा रही है। जनता पार्टी को शासन में आये एक वर्ष से अधिक हो चुका है लेकिन जिस क्रान्तिकारिता की अपेक्षा उससे थी उस दिशा में यदि कुछ भी हो रहा हो तो सन्तोष हो सकता है। ये प्रश्न हैं जो मस्तिष्क में उभरते हैं और विचार आता है कि कुछ आगे होना ही चाहिए। यदि नहीं हुआ तो क्या होगा ? जो सपना संजोकर जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आन्दोलन चल रहा था, जिसके लिए अनेक लोगों ने कष्ट सहे, अनेक जीवन बलिदान हो गये—उसका परिणाम लाना आवश्यक है, यह अपेक्षित है, समय की माँग है.....।

विवेकानन्द जागृति केन्द्र

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दिल्ली प्रदेश शाखा द्वारा "ग्रामोत्थान हेतु छात्र अभियान" प्रकल्प के अन्तर्गत दिल्ली की एक रिसेटिलमेंट कालोनी जहांगीर पुरी में 'विवेकानन्द जागृति केन्द्र' का शुभारंभ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष **प्रो० बाल आप्टे** ने विगत् उनतीस मई को किया। इस केन्द्र द्वारा आगामी महीनों में प्रौढ़ शिक्षा, बाल पुस्तकालय एवं खेल तथा युवाओं, प्रौढ़ों के लिए नि.शुल्क वाचनालय जैसे प्रकल्प शुरू किये जायेंगे। केन्द्र का शुभारम्भ करते हुए प्रो० आप्टे ने ग्रामीण विकास के रचनात्मक कार्यक्रमों में शक्ति लगाने के लिए युवा छात्रों का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष **प्रो० कृष्णभट्ट** महामन्त्री **श्री महेश शर्मा** तथा दिल्ली प्रदेश के संगठन मन्त्री **श्री राष्ट्रप्रकाश** भी उपस्थित थे।

—नरेन्द्र सोलंकी

पाठकों तथा लेखकों से

'राष्ट्रीय छात्र शक्ति' के स्थायी स्तम्भों के लिए आप रचनायें भेज सकते हैं।

- ☐ भेंटवार्ता के अन्तर्गत शिक्षा-क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं तथा छात्र युवाओं की समस्याओं और गतिविधियों पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के इन्टरव्यू उनके आकर्षक चित्रों सहित प्रकाशित किये जायेंगे।
- ☐ 'व्यक्ति' स्तम्भ के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में कार्यरत ऐसे प्राध्यापकों, विद्यार्थियों आदि का जीवन परिचय इन्टरव्यू सहित प्रकाशित किया जाएगा जो अपने विषय, क्षेत्र विशेष में विशिष्ट प्रतिभा रखते हैं।
- ☐ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली छात्र-युवा गतिविधियों से संबंधित समाचार तथा विचारोत्तेजक लेख 'अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि' स्तम्भ में प्रकाशित किये जायेंगे।
- ☐ छात्र-छात्राओं, शिक्षकों आदि के बीच विभिन्न समस्यामूलक विषयों पर आयोजित परिचर्चा को 'राष्ट्रीय छात्र शक्ति' में अवश्य स्थान प्राप्त होगा।
- ☐ 'राष्ट्रीय छात्र शक्ति' में प्रकाशित सामग्रियों पर तथा अन्य विषयों पर पाठक अपनी राय हमें अवश्य लिख भेजें। उपयुक्त विचार "हमारा मत" में प्रकाशित होंगे।
- ☐ इनके अतिरिक्त भी 'राष्ट्रीय छात्र-शक्ति' के स्वरूप को देखते हुए विभिन्न विषयों पर रचनायें प्रेषित की जा सकती हैं। अस्वीकृत रचनायें तभी लौटाई जा सकेंगी जब उनके साथ टिकट लगा पता लिखा लिफाफा संलग्न हो।
- ☐ सभी प्रकार की रचनायें तथा अन्य पत्र निम्नलिखित पते पर भेजनी चाहिए:—

'राष्ट्रीय छात्र-शक्ति' हिन्दी मासिक
36, बंगलो मार्ग, कमला नगर, दिल्ली-7

12 hours after you've put hot tea into this flask

And that's the heart of the matter. Take the Refill. A special raw material composition enables us to make stronger one-piece Refills that are more resistant to temperature changes. And the higher degree of vacuum created by sophisticated machines gives you a Flask that keeps hot liquids hot and cold liquids cold – longer. A Flask like this needs just one more thing. The range HammerMaster comes to you in a wide choice of designs, colours and capacities to suit your taste.

ASK FOR A GOOD FLASK-YOU'LL GET A

HammerMaster

[पृ० 50 का शेष]
सरकारी प्रयत्नों से ही लिया जाता रहा है और सरकारी प्रयासों का समीकरण हमेशा राजनैतिक दल के लाभों से ही बनाया जाता रहा है।

इस राजनैतिक संस्कृति में परिवर्तन आवश्यक है। और यहां भी एक बार फिर जनता पार्टी को ही पहल करनी पड़ेगी। पहले कदम के तौर पर जनता पार्टी विवेकहीन विलक्षण विचारों और सार्वजनिक विरोधाभासों को छोड़ कर जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करे यह जरूरी है। सब जानते हैं कि देश इस समय असाधारण समस्याओं का सामना कर रहा है और उनमें से किसी का भी सरल समाधान नहीं खोजा जा सकता। राष्ट्रीय स्तर पर एक जुट होकर इन समस्याओं के समाधानों को अंधेरे में टटोलना होगा।

हमें पहले से तैयार योजनाबद्ध समाधानों की आवश्यकता नहीं बल्कि एक ईमानदार और प्रभावी प्रयास की आवश्यकता है।

असन्तोष और दंगे

व्याप्त असन्तोष, हिंसा और उपद्रव इस रोग का संकेत देने के साथ-साथ प्रभाव भी लक्षित करते हैं। कई प्रकार के स्पष्टीकरण दिये जा रहे हैं—कहा जाता है कि वर्तमान असन्तोष 19 महीने की आपात् स्थिति की घुटन की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आ रहा है। इस असन्तोष का कारण सरकार के कामों से भी जोड़ा जाता है जो जन-सामान्य की भारी उपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं उतरी नजर आती है।

जनता सरकार का सत्तारूढ़ दल के रूप में कार्य और इसका जन-सामान्य की पार्टी के रूप में कार्य इन परिस्थितियों के कारण की जड़ माने जा रहे हैं।

पार्टी की भीतरी कलह, प्रशासन में अक्षमता और समाज में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जनता पार्टी के लिये सिरदर्द पैदा किये हैं और नागरिकों के लिये परेशानी है। यह सब स्पष्टीकरण उचित भी हैं और इन में एक हद तक सच्चाई भी है। तो भी वे एक समाधान प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं और जनता पार्टी में सुधार को साधारण रूप से प्रोत्साहन देना स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस बात से हालांकि इनकार नहीं किया जा रहा है कि इस सम्बन्ध में सारी जिम्मेदारी जनता पार्टी के कंधों पर है पर इतना ही काफी नहीं है। हम महसूस करते हैं कि अगले दो वर्ष नागरिकों द्वारा शांति व अनुशासन और सहयोग व रचनात्मक वर्षों के रूप में घोषित कर देने चाहियें। राष्ट्रीय स्तर पर एकात्मकता को तैयार किये जाने की आवश्यकता है जो कि ऐसा वातावरण बनाने में सहयोग देगा जहां हिंसा और उपद्रव का लोप हो जायेगा।

एक राष्ट्रीय विकल्प

हमें एक राष्ट्र के रूप में, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस बात को विश्व के सामने स्थापित करना है कि स्वतंत्रता और अनुशासन परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। हमें तानाशाही के विरुद्ध अपनी रक्षा करनी है और लोकतंत्र में विश्वास अभिव्यक्त करना जरूरी है।

केवल दिखावे की राजनीति के द्वारा नहीं बल्कि रचनात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से।

देश भर में स्थिति चिंताजनक है। असन्तोष के विभिन्न आयाम हैं। कैम्पस में बिगड़ी हुई स्थिति सारी परिस्थिति का एक भाग है और हम अनुभव करते हैं कि इस असन्तोष की स्थिति का इलाज प्रधानमंत्री का निश्चयात्मक वक्तव्य नहीं हो सकता। विद्यार्थियों से यह कहना बहुत आसान है कि यदि आप चाहते हैं तो विश्वविद्यालयों को अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया जाएगा। लेकिन छात्र-समुदाय की समस्याओं का हल निकाले बिना उन्हें सुधारने का उपदेश देना न केवल विद्यार्थियों के साथ अन्याय है बल्कि उन्हें अधिकारियों से सीधे लड़ने को बाध्य भी करता है। विद्यार्थी समाज अपनी परिस्थितियों की साधारण प्रकृति से ही व्यवस्था विरोधी लगता रहा है। लेकिन यदि व्यवस्था इन्हीं आधारों पर विद्यार्थी विरोधी रुख अपनाती है तो फिर यह किसी भी रचनात्मक राष्ट्रीय प्रयास के प्रति गहरा प्रतिघात होगा जब कि परिस्थितियों की मांग है कि ऐसे प्रयासों में अब देर नहीं होनी चाहिए।

राजनीतिज्ञों को सुधारना पड़ेगा

विद्यार्थियों को सुधारने की आवश्यकता है इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन प्रशासन को भी आवश्यक रूप से सुधारना चाहिये राजनीतिज्ञों को भी सुधारना पड़ेगा और प्रत्येक वर्ग को अपने क्षेत्र में शुरुआत करनी होगी और तब आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को भी इस के लिये तैयार करना होगा। जो प्रक्रिया आज नजर आ रही है उससे समझ में आता है कि जब आप बिना अपनी जिम्मेदारी समझे दूसरों को उपदेश देने लगें तो कम से कम उस उपदेश की दिशा में अपने स्वयं के व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। हम प्रधानमंत्री से सहमत हैं जब वह राष्ट्रीय रचनात्मक वातावरण के निर्माण की इच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन हमारा आग्रह है कि केवल इतने पर ही रुकने से काम नहीं चलेगा बल्कि उन्हें अपेक्षित वातावरण के निर्माण के लिये सभी को प्रयास में शामिल करने में उन्हें पहल करनी होगी। हमारा विश्वास है कि विद्यार्थी समुदाय इस प्रयास के प्रति स्वयं के अत्यंत स्वीकारात्मक रूप में स्वयं को समर्पित करेगा।

यदि हम ऐसा वातावरण निर्माण कर पाने में सफल होते हैं तो फिर तानाशाही की ताकतें निश्चित रूप से स्वतः ही समाप्त हो सकेंगी। सूर्य की आराधना करो, अंधकार निरस्त हो जाएगा।

इस राजनैतिक संस्कृति में परिवर्तन आवश्यक है। इसके लिए जनता पार्टी को ही पहल करना होगा। सबसे पहले जरूरी है कि जनता पार्टी विवेकहीन विचारों और सार्वजनिक विरोधाभासों को छोड़कर जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करे। दूसरे, अगले दो वर्ष अनुशासन, सहयोग, शान्ति और रचनात्मक कार्य के वर्षों के रूप में घोषित कर देने चाहिए।

दृष्टिकोण

एक राष्ट्रीय चुनौती

● प्रो० बाल आप्टे

दिल्ली में एक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोरारजी देसाई की निश्चयात्मक घोषणा कि वह विश्वविद्यालयों को अनिश्चित काल के लिये बन्द कर देंगे यदि विद्यार्थी ऐसा चाहते हैं। विद्यार्थी समाज के प्रति प्रशासन के अपेक्षित रवैये को सही रूप में सामने नहीं रखा जाता। विशेषतौर पर ऐसे समय में जबकि छात्र-असन्तोष की वर्तमान स्थिति देश भर की चिन्ता का कारण बनी हुई है। उपद्रवों के कारण पैदा राष्ट्रव्यापी हिंसा और असन्तोष की वेदना से सारा देश तड़प रहा है। यह चिंता की बात है कि जहां इस असन्तोष के कारण और उसकी प्रकृति के आयाम बहुमुखी हैं और वहीं इनसे प्रभावित वर्ग या वर्गों से इसका परस्पर सम्बन्ध भी नहीं है। दूसरी ओर राजनैतिक ठेकेदारों ने इस असन्तोष की तुलना पहले ही 73-74 के श्रीमती गांधी के शासन-काल की परिस्थितियों से करनी शुरू कर दी है।

अखबारी नीति का असर

श्रीमती गांधी ने आपात् काल में जो किया उसे सही साबित करने और आपातकाल की वकालत करने का बीड़ा कुछ समाचार पत्रों ने बहुत पहले से उठा रखा है और अब इस सारी असन्तोष की स्थिति से ये लोग लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही ठेकेदार हैं जिन्होंने श्रीमती गांधी को हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों का एकमात्र संरक्षक घोषित किया हुआ है और यही लोग इस प्रचार में लगे हैं कि समाज का सारा कमजोर वर्ग श्रीमती गांधी के पीछे है और वही इनको नेतृत्व दे सकती है, इनकी आवाज उठा सकती है। इस संदर्भ में चेतावनियां भी दी जा रही हैं जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री की कमजोर वर्गों की बराबर के रूप में स्तुति और गुणगान से अधिक कुछ भी नहीं है ये लोग समाज के उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष के समय हथियार डाल दिये थे और बाद में जनता सरकार की जीत पर श्रीमती गांधी की निंदा करने में पहल करने के लिये खींचातानी भी की थी। श्रीमती गांधी का समाचारों में आवश्यक प्रचार बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है यह बात ध्यान देने की है कि ये तथाकथित बुद्धिजीवी पलायन के दोनों मार्ग खुले रखना चाहते हैं।

हमारा प्रयास यह कभी नहीं है कि लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति उत्पन्न आशंका को इंच मात्र भी कम किया जाए। यह खतरा अभी भी उतना ही बना हुआ है। परन्तु इस खतरे से निपटने का तरीका केवल इन नीतियों के प्रति असन्तोष व्यक्त करना नहीं हो सकता बल्कि एक लगातार प्रयास की आवश्यकता है जिससे देश भर में शांति और सहयोग का रचनात्मक वातावरण तैयार किया जा सके। यह बात भी साफ तौर पर समझी जानी चाहिये कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर जनता सरकार को ही इस राष्ट्रीय प्रयास के नेतृत्व का जिम्मा सम्भालना पड़ेगा। इस बात को भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि जनता पार्टी एक राजनैतिक दल के विकल्प के रूप में सामने नहीं आई है बल्कि यह तानाशाही और भाई-भतीजावाद से परिपूर्ण शासन के विकल्प का स्वरूप लेकर उभरी है इसका कार्य इसलिये और भी कठिन है कि जन-सामान्य जनता सरकार के काम को नापने के लिये उन पैमानों से बिल्कुल अलग पैमानों का प्रयोग करेगा जिनका इस्तेमाल तीस वर्ष कांग्रेसी शासन के विषय में निर्णय करने में किया गया है। जनता पार्टी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सत्ता में आई है। तो भी, दुर्भाग्यवश तीस वर्षों से बनी दूषित राजनैतिक संस्कृति की घुटन में एक सत्तारूढ़ दल के रूप में स्वयं को प्रभावी सिद्ध करने में इसे गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है।

राजनैतिक संस्कृति

वर्तमान संस्कृति में अवसरवादी सत्ता के चारों ओर घूमते हैं और जगह पा जाते हैं। दिखावे की राजनीति इन अड्डों पर शासन करती है और वही लोग उभर कर सामने आते हैं जो किसी प्रकार से योग्य नहीं हैं। व्यक्ति के विषय में फैसले उसकी कार्यक्षमता से नहीं बल्कि पूर्व चरित्र और निजी स्वामी भक्ति के आधार पर लिये जाते हैं और फिर जनता-मंत्रियों की साधारण अनुभवहीनता, प्रशासन के बजाय राजनीति में लगे रहना, नौकरशाही का नियंत्रण तथा इसका निहित-स्वार्थों को संरक्षण स्थिति को और भी विकट बना देता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रयास का अर्थ अब तक केवल

[शेष पृ० 49 पर]

एक राष्ट्र के इतिहास में ऐसे भी युग आते हैं जब कि विधाता उसके सम्मुख एक ही कार्य और एक ही लक्ष्य रख देता है, जिसके लिए अन्य सब कुछ चाहे वह अपने-आप में कितना भी उच्च और महान क्यों न हो, बलिदान कर देना पड़ता है। ऐसा ही समय अब हमारी मातृभूमि के लिए आ गया है : इस समय उसकी सेवा से अधिक प्यारी कोई चीज नहीं, अन्य जो कुछ भी है उसे उसी लक्ष्य की ओर ले चलता है, यदि तुम्हें अध्ययन करना है, मातृभूमि के लिए अध्ययन करो। अपनी देह, मन और आत्मा को उसकी सेवा के योग्य बनाओ। अपनी आजीविका कमाओ इस भावना से कि तुम देश के लिए जी सको। तुम विदेशों में जाओ तो इस भावना से कि वहाँ से ज्ञानार्जन करके लौटोगे उससे मातृभूमि की सेवा करोगे।

[illegible] द्वारा [illegible] प्रिंटर्स, [illegible] दिल्ली [illegible] में मुद्रित
[illegible] नई दिल्ली-[illegible] से प्रकाशित।

लेखकों से

- राष्ट्रीय छात्र शक्ति में प्रकाशनार्थ विचारोत्तेजक लेख, समाचार, रिपोर्ताज, फीचर, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से इण्टरव्यू, परिचर्चा, कविता, कार्टून, रेखांकित आदि रचनाएं उपयुक्त चित्रों सहित आमन्त्रित हैं।

- शैक्षणिक समस्याओं, छात्रसंघों एवं छात्र-युवा संगठनों की रचनात्मक तथा आन्दोलनात्मक गतिविधियों, अन्तर्राष्ट्रीय छात्र-युवा गतिविधियों और जिला क्षेत्र से सम्बन्धित रचनायें 'राष्ट्रीय छात्र-शक्ति' में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की जायेंगी।

- रचना कागज के एक ओर हाशिया छोड़कर साफ-साफ लिखी या टाइप की हुई होनी चाहिए।

- रचना अस्वीकृत होने की दशा में वापसी के लिए टिकट लगा पता लिखा लिफाफा भेजना आवश्यक है।

- रचना के बारे में निर्णय एक माह के भीतर भेज दिया जाता है।

- रचना के अन्त में पूरा नाम व पता लिखना तथा मौलिक व अप्रकाशित होने की घोषणा करनी आवश्यक है।

- समीक्षा हेतु पुस्तक की दो प्रतियां आनी आवश्यक है।

- अनूदित रचनाओं के साथ मूल लेखक की स्वीकृति आवश्यक है।

- रचनाएं निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें—

सम्पादक,
'राष्ट्रीय छात्र शक्ति'
३६, बंगला मार्ग
दिल्ली-११०००१